

हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

9 मार्च, 1978

खण्ड 1, अंक 9

अधिकृत विवरण

विषय सूची

वीरवार, 9 मार्च, 1978

	पृष्ठ संख्या
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(9) 1
नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	(9)
32	
अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(9)
38	
8 मार्च, 1978 को किए गए बहिर्गमन के सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय द्वारा अवलोकन	(9)
48	
वैयक्तिक स्पष्टीकरण— श्री सुरेन्द्र सिंह द्वारा	(9) 48
विशेषाधिकार प्रश्न	(9)
49	

हरियाणा विधान सभा

वीरवार, 9 मार्च, 1978

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर 1, चण्डीगढ़ में प्रातः 9.30 बजे हुई ।

अध्यक्ष (ब्रिगेडियर रण सिंह) ने अध्यक्षता की ।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या 213

प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि माननीय सदस्य श्री शमशेर सिंह सदन में उपस्थित नहीं थे ।

TOURIST CENTRES IN THE STATE

***231. Swami Aditya Vesh :** Will the Education Minister be pleased to state —

(a) the total number of tourist centres at present in the State together with the monthwise and yearwise expenditure incurred and income accrued from the date of each tourist Centre was set up-to-date, separately; and

(b) the total income accrued from the sale of liquor during the period as referred to in part (a) above, separately ?

Education Minister (Col. Rao Ram Singh) :

(a) 24. Statement I and II containing information

in regard to yearwise expenditure incurred on running/managing the tourist centres and income accrued from the each of them from the date of starting, are laid on the table of the House. It is not possible to supply monthwise expenditure incurred and income accrued as the time and labour involved in compilation of this information will not be commensurate with the benefits to be derived therefrom.

(b) As per tentative/unaudited accounts the total income of Rs. 165.68 Lacs accrued to the Haryana Tourism Corporation during the period from 1.9.74 to 31.3.77. Figures of income prior to 1.9.74 cannot be given as during that period accounts in respect of sale of liquor were not maintained separately. Income horn sale of liquor during the year 1977-78 has not yet been compiled and, therefore, cannot be supplied.

STATEMENT-I

Expenditure incurred on Running the Tourist Complexes and income Accrued from them for the Period from 1968-69 to 31.8.74

(Department Period)

(Rs. in lakhs)

Name of the Centres	1968-69		1969-70		1970-71		1971-72		1972-73		1973-74		1974-75 1.4.74 to 31.8.74	
	Exp.	Incom e	Exp.	Incom e	Exp.	Incom e	Exp.	Incom e	Exp.	Incom e	Exp.	Incom e	Exp.	Income
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. 1. Badkhal	-	-	-	-	-	-	1.94	3.28	8.80	9.01	11.47	13.88	7.22	9.49
2. SurjKund	--	-	-	-	-	-	0.49	0.80	1.73	1.65	2.20	2.15	1.30	1.26
3. Magpie		-	-	-	-	-	-	-	-		1.34	1.51	0.94	1.19

4.	Hodel	-	-	-	-	--			-		-	-	-	-
5.	Soh na	-	-	-	-	-	-	-	0.54	0.18	1.21	1.19	0.97	0.87
6.	Sultanpur	-	-	-	-	-	-		0.13	0.10	0.40	0.34	0.43	0.40
7.	Dharuhera	-	-	-	-	-	-		0.58	0.57	1.43	1.43	0.71	0.67
8.	Gurrgaon	-		-	-	-	-		-	--	0.82	0.90	0.83	0.96
9.	Narnaul	-	-	-			-	-	0.38	0.32	1.71	1.62	1.56	1.63
10.	Hissar	-	-	-	-	-	0.21	0.25	3.08	3.32	1.73	4.39	4.09	4.30
11.	Bhiwani	----	-	-	-	-	-	-	-	-	1.33	1.54	1.80	1.83
12.	Jind	-	-	-	-	-	-	-	0.65	0.60	1.07	1.08	2.00	2.06
13.	Rohtak (Myna)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.53	0.54
13.	Rohtak(Tilyar)	--		-	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	Uchana		--	-	--		0.90	1.20	6.33	6.55	18.10	19.22	19.20	19.9

																0
15.	Pipli	-	--	--	-			0.13	0.14	2.58	2.67	2.92	3.08	2.14	2.28	
16.	Gharound a	-	-	-	-	--	-	-	-	-	-	0.06	0.09	0.96	0.98	
17.	Hathniku nd	-	-	-	-	-	-		-	0.03	-	0.05	-	0.30	-	
18.	Samalkha	-	-	-	-	-	-	0.04	0.03	0.76	0.65	1.19	1.32	0.82	1.01	
19.	Sonepat	-	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.88	0.92	
20.	Panipat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21.	Pinjore	1.00	1.07	0.50	0.53	0.60	0.66	1.23	1.33	3.08	4.01	3.13	4.84	2.21	3.16	
22.	Panchkul a	-	-	-	-	-		-	-	2.09	2.13	2.90	3.29	2.68	2.91	
23.	Youth Hostel Panchkul a	-	-	-	--	-	-	-		-	-	-	-	-	-	

G. Total	1.00	1.07	0.05	0.53	0.60	0.66	4.94	7.03	30.76	31.96	55.06	61.87	51.30	56.3
														6

Note : Prior to 1.9.74 the tourist centres were run/managed by the Tourism Department and as such figures of expenditure / income have been given in a separate statement.

STATEMENT II

Expenditure incurred on running of the Tourist Complexes and income accrued from them for the Period from 1.9.74 to 31.3.77

(Corporation Period)

(Rupees in Lakhs)

S. No.	Name of the Centres	1.9.74 to 31.3.75(74-75)		1975-76		1976-77	
		Expenditure Rs.	Income Rs.	Expenditure Rs.	Income Rs.	Expenditure Rs.	Income Rs.
1.	Badkhal	10.86	10.82	20.41	20.88	24.63	24.80
2.	Surjkund	1.89	1.56	4.85	5.56	6.73	7.39
3.	Magpie	1.29	1.45	3.15	3.27	3.28	3.50
4.	Hodel	0.86	0.77	4.19	4.18	5.13	5.61
5.	Sohna	1.66	1.50	2.55	2.42	3.76	3.66
6.	Sultanpur	0.52	0.45	1.25	1.13	1.34	1.45

7.	Dharuhera	1.77	1.82	3.43	3.53	4.06	4.31
8.	Gurgaon	2.69	2.42	4.09	4.03	4.91	5.27
9.	Narnaul	1.79	1.81	2.44	2.24	2.04	1.97
10.	Hissar	5.13	5.04	18.38	18.56	19.91	20.15
11.	Bhiwani	1.89	1.84	3.30	3.29	3.70	3.79
12.	Jind	1.49	1.33	2.51	2.42	1.81	1.61
13.	Rohtak (Myna)	3.16	3.26	8.10	8.87	7.05	7.61
13.	Rohtak (Tilyar)	--	-	-	-	8.35	8.61
14.	Uchana	34.92	35.90	56.27	58.58	69.18	70.84
15.	Pipli	2.92	2.89	0.03	6.01	6.34	6.95
16.	Gharounda	1.08	0.99	0.80	0.83	0.67	0.78
17.	Hathnikund	0.02	-	0.08	0.01	0.67	0.01
18.	Samalkha	1.10	1.05	2.94	3.02	3.57	4.08

(Closed in
Feb.,1977)

19.	Sonepat -	2.45	2.46	4.40	4.99	4.08	4.61	
20.	Panipat	-	-	-	-	17.13	17.24	
21.	Pinjore	3.77	3.69	6.62	6.93	7.84	8.68	
22.	Panchkula	3.45	3.57	4.77	4.58	4.13	4.06	
23.	Youth Hostel Panchkula.	0.05	0.02	0.09	0.03	0.32	0.22	
24.	Tauru	-	-	-	-	-	-	(Started on 3.10.77)
	G. Total	84.76	84.64	160.65	165.36	210.03	217.32	

Note : 1. Expenditure/income figures for the year 77-78 have not yet been compiled. Moreover according to the Companies Act, the accounts of the Corporation are finalised in the month of June of the Subsequent year.

2. The expenditure/Income for the years 75-76 and 76-77 are based on tentative accounts so far finalised as these are yet to be audited by the Statutory Auditor.

स्वामी आदित्यवेश : क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि— जो सरकार के पर्यटन केन्द्र काफी घाटे में चल रहे हैं, क्या सरकार के पास इनको बन्द करने की कोई योजना विचाराधीन है?

कर्नल राव राम सिंह : स्पीकर साहब, कल भी मैंने एक जवाब में कहा था कि जो जेस्टेशन पीरियड होता है, और जो होटल बगैरह होते हैं, वह जब शुरू किये जाते हैं तो उसके एक दो या तीन साल तक वे लौस में जाते हैं और जब उसकी एडवरटाइजमेंट हो जाती है और लोगों को भी पता लग जाता है कि यहां पर एक टूरिस्ट काम्पलेक्स है, उसके बाद वे प्रोफिट में चलते हैं । आमतौर पर यह वर्क आउट किया गया है कि पहले 5—6 साल कोई काम्पलेक्स अगर लौस पर जाता है तो उसके बाद वह प्रोफिट में जायेगा । अगर कहीं ऐसा देखा गया कि जेस्टेशन पीरियड के बाद भी कोई काम्पलेक्स लौस में जा रहा है तो उसको बन्द करने पर विचार किया जायेगा ।

स्वामी आदित्यवेश : अध्यक्ष महोदय, अभी मिनिस्टर साहब ने यह फरमाया कि चार पांच साल चलने के बाद अगर कोई काम्पलेक्स घाटे में जायेगा तो उसके बाद उनको बन्द कर दिया जायेगा, क्या मन्त्री महोदय बताएंगे कि सूरजकुण्ड, होडल, सुल्तानपुर धारूहेडा वगैरह कई ऐसे काम्पलेक्स हैं जोकि काफी घाटे में चल रहे हैं और सरकार का इन पर काफी खर्चा हो रहा

है, क्या सरकार इस तरफ भी ध्यान देने की कृपा करेगी और ऐसे घाटे वाले काम्प्लैक्स को बन्द करने का विचार करेगी?

कर्नल राव राम सिंह : अध्यक्ष महोदय, इस वक्त तो उनको बन्द करने की सरकार की कोई ऐसी स्कीम विचाराधीन नहीं है । अगर माननीय सदस्य इस बारे में अलग-अलग प्रश्न पूछेंगे तो मैं उन सभी की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके उनको पूरा-पूरा जवाब दे दूंगा ।

स्वामी आदित्यवेश : क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि इन पर्यटन केन्द्रों पर अनाचार के केसिज भी होते हैं, क्या सरकार इनकी रोक थाम के लिये कोई कदम उठाने का विचार रखती है? इसके साथ मैं सरकार से यह भी कहूंगा कि इन पर्यटन केन्द्रों पर बड़ी भारी करप्शन है, जिसके कारण हुडधंग भी होते हैं ।

कर्नल राव राम सिंह : स्पीकर साहब, करप्शन और हुडधंगा मचाने में बड़ा फर्क है जहां तक करप्शन का ताल्लुक है, अगर कोई माननीय सदस्य ऐसा कोई केस प्वायंट आउट करेंगे, और अगर वह साबित हो जाता है तो कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जायेगी । इस बात का मैं इस सदन में आश्वासन देता हू कि जनता सरकार करप्शन को बिल्कुल भी टोलरेट नहीं करेगी । जहां तक हुडधंगा की बात है इसके लिये मैं माननीय सदस्य को बता देना चाहता हू कि हरेक टूरिस्ट काम्पलेक्स पर या उसके नजदीक

ही पुलिस का पूरा इन्तजाम है । अगर ई वहांपर हुडधंगा मचाता है तो उस के खिलाफ कार्यवाही की जाती है ।

स्वामी आदित्यवेश : अध्यक्ष महोदय, यह जो सरकार को पर्यटन केन्द्र हैं, उनके नजदीक के जो गांव हैं, वहां पर लोगों पर इन पर्यटन केन्द्रों का बड़ा बुरा असर पड़ रहा है, गरीब किसान और मजदूर इन पर्यटन केन्द्रों के शिकार होते जा रहे हैं, क्या ऐसी चीजों को रोकने के लिये सरकार के पास कोई स्कीम है?

कर्मल राव राम सिंह : अध्यक्ष महोदय, जब से मैंने यह पर्यटन विभाग संभाला है, तब से मैं तकरीबन तकरीबन सभी पर्यटन केन्द्रों का विजिट कर चुका हूं और मैंने देखा है कि जो भी नजदीक वाले गांव के लोग हैं, वे इन से बहुत ही खुश हैं, उनको वहां पर नौकरियां मिलती हैं, उनके दूध और अन्य चीजों की बिक्री भी वहां पर होती है और टूरिस्ट काम्पलेक्स में जो लीकर है, वह उन गरीब लोगों की जेब से बाहर कीरू वात— है वे गांव वाले अगर दारू के शौकीन होंगे तो बाहर से कांटरी वाइन ही पीते होंगे । इन केन्द्रों में इस तरह की कोई प्रोवजन नहीं है ।

चौधरी पीर चन्द : क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जैसे इन टूरिस्ट काम्पलेक्स में घाटा ही चल रहा है,

इसको देखते हुए और टूरिस्ट काम्पलैक्स न बनाने का सरकार का कोई विचार है?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया ।)

चौधरी हरस्वरूप बूरा : क्या मन्त्री महोदय बताएंगे कि यह जो पर्यटन केन्द्र सरकार ने खोल रखे हैं, ये सारे के सारे घाटे पर चल रहे हैं या कोई मुनाफे पर भी चल रहे हैं?

कर्नल राव राम सिंह : अध्यक्ष महोदय, इस बारे में स्टेटमेंट सदस्य महोदय के सामने है । इन टूरिस्ट काम्पलैक्स को पहले डिपार्टमेंट रन कर रहा था । 3 1- 8- 1974 को कारपोरेशन बनाई गई और उस कारपोरेशन में 1- 0 1974 से आज तक जो नुकसान हुआ है, उसकी फिगर्ज दी गयी है, 197 4-7 5 के पहले 6 महीनों में कारपोरेशन को 12 हजार रुपये का नुकसान हुआ, 197 5- 76 में 4 लाख 71 हजार का फायदा हुआ और 197 6-7 7 में भी 7. 21 लाख का फायदा हुआ । यह जो काम्पलैक्स हैं यहां पर सारी दुनियां के लोग आते हैं, हरियाणा टूरिजम ओर्गेनाइजेशन ही एक ऐसी ओर्गेनाइजेशन है जिसने घाटा का अवार्ड हासिल किया है और कहीं भी हिन्दोस्तान में किसी और आर्गेनाइजेशन को यह अवार्ड नहीं मिला । यह हरियाणा का ट्रिकम ओर्गेनाइजेशन ही ऐसा है जोकि काबिले तारीफ है ।

श्री मूल चन्द मंगला : जो टूरिस्ट काम्पलैक्स हैं वहां पर अमीर आदमियों की ही ठहरने की व्यवस्था है लेकिन जो गरीब लोग हैं उनके लिये यहां ठहरने की कोई व्यवस्था नहीं है और न ही उनकी ऐकमोडेशन का ही कोई प्रबन्ध है क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि क्या ऐसे लोगों के लिये कोई व्यवस्था की जा सकती है ताकि गरीब लोगों को भी इन पर्यटन केन्द्रों से सुविधाएं प्राप्त हो सकें?

कर्मल राव राम सिंह : जब से हरियाणा में जनता पार्टी सरकार ने टेक ओवर किया है, हमने बहुत से टूरिस्ट कम्पलैक्स बनाये हैं और अब हम कैम्पर्ज हट्स भी बना रहे हैं और हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने सोहना के बारे में जहां से नया चश्मा निकला है, आदेश दिये हैं कि यहां पर यात्रियों के लिये सभी प्रकार के प्रबन्ध किये जाएं और वहां पर पांच-सात रूपये रोज के मामूली खर्च से ठहरने का प्रबन्ध किया जाएगा और यह सारा प्रबन्ध बहुत जल्द ही करने जा रई है ।

कंवर राम पाल सिंह : मैं मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि जैसे जनता सरकार की तरफ से यह अभियान चलाया जा रहा है कि नशाबन्दी की जाए तो क्या टूरिस्टस काम्पलैक्सों में शराब की सेल बन्द करने का कोई विचार है?

कर्मल राव राम सिंह : जहां-जहां हरियाणा सरकार नशाबन्दी का एरिया डिकलेयर करती जा रही है वहां-वहां

शराबबन्दी की जाएगी । यह एक फेज्ड प्रोग्राम है जैसे कि ताउडू तथा सिरसा के कुछ इलाके हैं जो शराबबन्दी के लिये डिकलेयर किये गये हैं । इसी प्रकार जैसे-जैसे एरियाज शराबबन्दी के लिये डिकलेयर किये जाएंगे वहां शराब बन्द की जाएगी ।

श्री फतेह चन्द विज : स्पीकर साहब, मन्त्री महोदय ने बताया है कि कुछ नई जगहों पर टूरिस्टस काम्पलैक्स बनाने जा रहे हैं, क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि क्या उनमें भी यह बार जारी रखी जाएगी या नहीं?

कर्नल राव राम सिंह : इस सवाल के साथ मेन सवाल का कोई संबंध नहीं है । जो काम्पलैक्स बने हुए हैं उनके बारे में सवाल पूछ सकते हैं । **चौधरी खुरशीद अहमद** स्पीकर साहब, खर्च और इंकम की स्टेटमेंट वर्ष 1976 और 1977 में बताया गया है कि गुड़गांव सैंटर में 4 लाख 91 हजार का खर्चा है और 5 लाख 27 हजार की आमदनी है इसी तरह से सोहना में 5 13 लाख का खर्चा है और 5 61 लाख की आमदनी है, इसी तरह से सूरज कुड में 6. 73 लाख का खर्चा है और 7. 39 लाख की आमदनी है और मैगपाई में 3 28 लाख का खर्चा है और 3. 50 लाख की आमदनी है तो क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे विय इस व्यू को देखते हुए कि जो दिल्ली के नजदीक सैंटर है वे सारे प्रोफिट में चल रहे हैं इसलिए इन्की एक्सपैशन करने का सरकार का कोई प्रोग्राम है?

कर्नल राव राम सिंह : माननीय सदस्य का यह बहुत अच्छा सवाल है । जहां—जहां इनमें प्रोफिट चल रहा है वहाँ—वहाँ अगले साल और डिवैल्पमेंट के प्लान बनाय जा रह है ।

श्री भले राम : मन्त्री' जी ने अभी बताया कि इन कम्पलैक्सों में घाटा है दया मन्त्री महोदय बताने की कृपा क्रेग' कि जो कन्सैशन एम0 एल. 0 एज0 और मिनिस्टरो को काफी वगैरह में मिलता है अगर उसको बन्द कर दिया जाए तो यह घाटा पूरा नहीं हो जाएगा?

कर्नल राव राम सिंह : अगर सब एम0एल0एज0 साहिबान की ऐसी मर्जी होगी तो यह कन्सैशन बन्द कर देंगे ।

श्री टेक राम : मैं मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि भिवानी में जो काम्पलैक्स है वह घाटे में चल रहा है तो सरकार उसके बारे में क्या सोच रही है?

कर्नल राव राम सिंह : भिवानी के बारे में अगर स्टेटमेंट देखी जाए तो उसमें 197 6—7 7 में 3. 70 लाख का खर्चा है और 3 79 लाख की आमदनी है इस तरह से वह 9 हजार के फायदे में है ।

श्री देवी दास : क्या मन्त्री महोदय बताएंगे कि सोनीपत के अन्दर जो काम्पलैक्स है क्या वहां ठहरने की पूरी व्यवस्था है अगर नहीं है तो इंतजाम किया जाएगा?

कर्नल राव राम सिंह : यह एक सैपरेट सवाल है । इस वक्त मेरे ध्यान में नहीं है कि वहां पर ठहरने का इंतजाम है या नहीं । लेकिन उसके पास नेशनल हाई-वे पर जितने भी काम्पलैक्स हैं वहां पर ठहरने का पूरा इंतजाम है । अगर सोनीपत में भी डिमांड ज्यादा होगी तो वहां केलिये भीविचार कर लेंगे । लेकिन हमारा प्लान यह है कि काम्पलैक्स जितना भी कम खर्च वाला हो वह बनाया जाए ।

स्वामी आदित्यवेश : क्या मन्त्री महोदय बताएंगे कि दिल्ली के नजदीक जो पर्यटन केन्द्र खोले हुए हैं उनमें दिल्ली और गाजियाबाद के दस्यु प्रवृत्ति के लोग ज्यादा ठहरते हैं । इस चीज को देखते हुए क्या उनको बन्द करने का कोई प्रोग्राम है?

(कोई जवाब नहीं दिया गया)

चौधरी गंगा राम : स्पीकर साहब, इस हाउस में दो-चार एम0एल0ए0 ऐसे हैं जिनके घर रोटी नहीं बनती क्योंकि वे छडे छांग है क्या आपकी कोई ऐसी स्कीम बन सकती है जिससे कि हमें वहां सस्ती रोटी मिल जाए? (हंसी)

(कोई जवाब नहीं दिया गया)

Share of Ravi-Beas Water

***263. Chaudhri Jagjit Singh Pohloo** : Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state the steps taken or proposed to be taken by the Government to take the

share of Haryana from the surplus Ravi-Beas water as per the decision of the Central Government taken in this regard in the year 1976 ?

Irrigation & Power Minister (Shri Verendar Singh)
: Work on Sutlej Yemuna Link in Haryana is being executed on top priority to transport Haryana's share in the surplus Ravi-Beas waters. The matter is being pursued with the State of Punjab for start of work on the link canal and its early completion in Punjab territory.

श्री अध्यक्ष : पोहलू साहब यह मामला पहले भी कई दफा आ चुका है?

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू : स्पीकर साहब, मैं टू दि प्वांयट ही पूछूंगा । मैं वजीर साहब से पूछना चाहता हूँकि यह स्कीम पंजाब में कहां से शुरू होगी और हरियाणा में किस मुकाम पर मिलेगी?

श्री वीरेन्द्र सिंह : पंजाब में कीरतपुर के नजदीक एक गांव लोहंद है वहां से शुरू होगी और जो पंजाब का आखिरी गांव है उसका नाम है सरला कलां और जो हरियाणा का शुरू का गांव है उसका नाम है डगेरिया, वहां पर यह मिलेगी ।

श्री सुरेन्द्र सिंह : क्या मन्त्री महोदय बताएंगे 'कि उस वक्त की केन्द्र सरकार ने जो हरियाणा का हिस्सा 3 5 मिलियन एकड फीट इस पानी में से तय किया था क्या आज की सरकार

तथा मुख्य मन्त्री उस फैसले को वाजिब समझते हैं या उस पानी को कम समझते हैं ।

Shri. Verendar Singh : That award is not negotiable That is final.

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू : क्या मन्त्री महोदय बताएंगे कि नहर पूरी होने के बाद हरियाणा को जो पानी 'मिलेगा उस वक्त कौन-कौन से जिले को ज्यादा पानी मिलेगा?

श्री वीरेन्द्र सिंह : पानी के बंटवारे का जहां तक ताल्लुक है वह पानी उपलब्ध होने पर होगा ।

Veterinary Hospital

***254. Chaudhri Sant Kanwar** : Will the Minister for Development and Panchayats be pleased to state -

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to open more Veterinary Hospitals in District Rohtak , if so, the time by which these are likely to be opened; and

(b) the steps, if any, being taken by the Government to convert the existing Veterinary Dispensaries in District Rohtak to Veterinary Hospitals, particularly, in Hassangarh constituency of District Rohtak ?

विकास तथा पंचायत मन्त्री (सरदार तारा सिंह) :

(क) जी नहीं ।

(ख) वर्ष 197 7- 78 में रोहतक जिले में 'डिस्पैसरी मंडौठी को हसनगढ पशु हस्पताल में बदल दिया गया है परन्तु रोहतक जिले के निर्वाचन क्षेत्र में किसी पशु डिस्पैसरी इत्यादि को बदलने का प्रस्ताव नहीं है ।

चौधरी संत कंवर : मैं मन्त्री जी से पूछना चाहता हूँ कि जिस गांव वाले स्वयं बिल्डिंग तैयार करके दे दे तो क्या वहां पर सरकार डाक्टर और दवाइयों का प्रबन्ध कर देगी?

सरदार तारा सिंह : यह तरीका तो ठीक है लेकिन इसके साथ-साथ हमें बजट में पैसे की प्रोवीजन को भी ध्यान में रखना होता है । अगर पैसा मंजूर न हो तो उस वक्त तक यह काम करना मुश्किल है ।

चौधरी लाल सिंह : मैं मन्त्री जी से पूछना चाहता हूँ कि जहां पर लोग गरीब हैं और केवल पशुओं के सहारे गुजारा करते हैं वे बिल्डिंग नहीं बना सकते क्या वहां पर सरकार खुद बिल्डिंग बनाकर डिस्पैसरी खोलेगी?

(कोई जवाब नहीं दिया गया)

चौधरी ईश्वर सिंह : क्या मन्त्री महोदय. बताएं कि जनता सरकार आने के बाद हरियाणा में कितने पशु चिकित्सालय खोले गये हैं?

सरदार तारा सिंह : जनता सरकार बनने के बाद नया हस्पताल तो कोई नहीं खोला गया लेकिन दस डिस्पैसरिया अप-ग्रेड की गई है जिनके नाम इस प्रकार है :- सोनीपत में बजाना खुर्द, रोहतक में मंडोठी, हिसार में अगरोहा, सिरसा में सुखचान, महेद्रगढु में जोड़ी, और स्टाकमैन सैटर्ज-अम्बाला में साहा, कुरुक्षेत्र में भार सहीदा, तथा हरिगढ भोरख भिवानी में बामला और जींद में लखन माजरा । इसके अलावा हम 20 डिस्पैसरिया 1978-79 में अप-ग्रेड कर रहे है ।

चौधरी संत कंवर : क्या मन्त्री महोदय बताएंगे कि जो दवाईयां जरूरी होती हैं क्या वे डिस्पैसरीज में मिल जाती हैं या जिन लोगों के पशु बीमार होते हैं, उनको खरीद कर लानी पड़ती हैं?

सरदार तारा सिंह : कुछ दवाईयां मिलती हैं लेकिन कुछ दवाईयां ऐसी भी हैं जिनकी सारी कीमत हरियाणा सरकार नहीं दे सकती । 25 फीसदी हरियाणा सरकार देती है, कुछ जमींदार को देनी पड़ती है जो पशु का मालिक होता है और 50 परसेंट सैन्ट्रल गवर्नमेंट भी देती है । सारी दवाईयां हरियाणा सरकार नहीं देती ।

श्री लछमन सिंह : क्या मन्त्री महोदय फरमाएंगे कि जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद, नई डिस्पैसरीज खोलने के लिए, सरकार ने कोई प्रोजेक्ट, फाइनांस डिपार्टमेंट से पैसा लेने

के लिए भेजी है । क्या कोई प्रोपोजल गई है कि इतने हस्पताल हमने खोलने हैं?

सरदार तारा सिंह : यह क्वेश्चन सैप्रेट है । ऐनिमल हसबैंडरी के लिए जितना बजट होता है उसी के मुताबिक स्कीम बनाई जाती है ।

Shri Lachhman Singh : This is not the reply to my question. My question is whether the Development Department placed any proposal before the Finance Department, if so, for how many dispensaries ?

सरदार तारा सिंह : सैप्रेट नोटिस दे, मैं इसका जवाब दे दूंगा ।

Shri Lachhman Singh : This is not a separate question. the Hon. Minister may give the reply either in affirmative or negative.

श्री अध्यक्ष : आपने जवाब दिया है कि पैसे की कमी की वजह से नहीं हो सकता, इसके बाद ये सवाल पूछें ।

Shri Lachhman Singh : I would seek your protection. The

reply from the Government is not at all satisfactory

Mr. Speaker : It appears that no proposal was made.

Shri Lachhman Singh : He should say it directly

that no proposal was made .

सरदार तारा सिंह : जितने पैसे बजट में अलाट होते हैं. उसके मुताबिक स्कीम बनती है । इसके इलावा और कोई स्कीम हमारे पास नहीं है ।

चौधरी हरस्वरूप बूरा : मेहम के अन्दर फलड के टाईम पर टैम्परेरी डिस्पैसरीज और सैन्टर खोले हुए थे । क्या मन्त्री महोदय बतायेंगे कि उनको परमानेंट करेंगे या कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करेंगे?

सरदार तारा सिंह : फलड के दौरान कई टैम्परेरी सैन्टर खोले थे और जब फलड खत्म हो गया तो उनको बन्द कर दिया गया है ।

चौधरी राम किशन : जैसा कि मन्त्री महोदय ने बताया कि पशु चिकित्सालय हर डिस्ट्रिक्ट में बोले गए लेकिन जिला जींद को इससे महरूम रखा गया । मन्त्री महोदय ने लखनमाजरा को जींद का गांव बताया है । यह जींद डिस्ट्रिक्ट में नहीं लिया जाना चाहिए, यह तो रोहतक डिस्ट्रिक्ट का एक कस्बा है । क्या मन्त्री महोदय जींद में पशु चिकित्सालय खोलने पर विचार करेंगे?

सरदार तारा सिंह : जरूर विचार होगा । जो 20 डिस्पैसरिया हम दे रहे हैं, उन को खोलते समय जिला जींद का जरूर ख्याल करेंगे ।

कंवर राम पाल सिंह : मन्त्री महोदय ने बताया कि नई डिस्पेंसरीज खोलेंगे और वर्ष 1978-79 में कुछ को अप-ग्रेड करेंगे । मैं पूछना चाहूंगा कि जो नई डिस्पेंसरीज खोलेंगे या अप-ग्रेड करेंगे! उनको खोलने का क्राइटेरिया क्या है?

सरदार तारा सिंह : कुछ पापुलेशन का हिसाब होता है, कुछ लोगों की डिमांड पर डिपेंड करता है और कुछ पशुओं का नम्बर देखते हैं कि पिछले साल में कितने पशु इलाज करवाने के लिए आए । इस तरह जरूरत के मुताबिक खोलते हैं और यही क्राइ-टेरिया है ।

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू : स्पीकर साहब, देहातों में, वैटरनरी हॉस्पिटलज की बिल्डिंग बनवाने के लिए पंचायतों ने पैसा इकट्ठा करके दे रखा है और तीन-तीन साल से जमा कर रखा है । मिसाल के तौर पर जखौली गांव वालों ने पैसे दिए हैं । क्या सरकार वहां जल्दी बिल्डिंग बनवाने की कोशिश करेगी, अगर नहीं बनानी है तो क्या वह पैसा वापिस दिलवायेगी? क्या जखौली गांव में बिल्डिंग बनाने की कोई प्रपोजल है?

सरदार तारा सिंह : बहुत जल्दी बनाने की कोशिश करेंगे । अगर कोई ऐसा गांव है, मेरे ध्यान में लाएं, विचार करेंगे ।

चौधरी देस राज : क्या मन्त्री महोदय बताएंगे कि हरियाणा प्रान्त में इस साल कितने स्टॉकमैन सैन्टर खोले जाएंगे?

सरदार तारा सिंह : मेरे पास लिस्ट है, अगर मेरे माननीय सदस्य चाहते हैं तो मैं पढ़ देता हूँ लेकिन इसमें एक घंटा लगेगा ।

श्री मूलचन्द मगला : स्पीकर साहब, जहां दवाइयों का स्टॉक रखते हैं, वहाँ दवाइयों के रखने का प्रबन्ध ठीक नहीं है जिसकी वजह से दवाइयां खराब हो जाती हैं और 90 परसेंट दवाइयां ऐ सी होती है जिनकी डेट एक्सपायर हो जाती है । यह हालत पलवल में ही नहीं. सारी स्टेट में ऐ सी ही है जिसकी वजह से पशुओं को आराम नहीं होता । क्या मन्त्री महोदय दवाइयों के रखने की व्यवस्था ठीक करवायेंगे?

सरदार तारा सिंह : अभी तक मेरे नोटिस में ऐसी बात नहीं आई कि जो दवाइयां खराब हो गई हों, उनको इस्तेमाल किया हो । लेकिन मैं पलवल में गया हूँ, वहां मुझे यह शिकायत मंत्री कि स्टॉक वाले कमरे की छत खराब है, उस छत को बनवाना चाहिए दवाइयों खराब होने को बात मेरे नोटिस में नहीं है ।

चौधरी हुक्म सिंह : देहातों में जो नई डिस्पेंसरियां खोली जाती है उनकी बिल्डिंग अक्सर दएहात वाले बनाते हैं । क्या मन्त्री महोदय बताएंगे कि आगे के लिए इनको सरकार ही बनाये ?

सरदार तारा सिंह : जो नई डिस्पैसरीज बन रहीं हैं, इसमें दो बातें हैं । पहले स्टाकमैन सैन्टर बनता है, फिर डिस्पैसरी बनेगी और उसके बाद हास्पिटल बनता है । पहले बिल्डिंग गांव वालों को बनानी पड़ती है ।

श्री लहरी सिंह मेहरा : क्या मन्त्री महोदय बताएंगे कि जिन गांवों में डिस्पैसरी की बिल्डिंग तैयार है, वहां पर डिस्पैसरी क्यों नहीं खोली गई और इसका क्या कारण है?

सरदार तारा सिंह : मेरे नोटिस में ऐसी कोई बात नहीं लाई गई, अगर माननीय सदस्य बताएंगे तो एक्शन ले लेंगे ।

चौधरी हरस्वरूप बूरा : जो सैन्टर खोले हैं और उन में जो डाक्टर देहातों में पशुओं को देखने के लिए जाते हैं, वे लोगों से फीस चार्ज करते हैं । क्या माली महोदय बताएंगे कि क्या उन्होंने कोई फीस मुकर्रर कर रखी है तभी वे चार्ज करते हैं या अपनी मजी से चार्ज करते हैं?

सरदार तारा सिंह : गवर्नमेंट ने कोई फीस मुकर्रर नहीं की और अगर कोई आदमी फीस चार्ज करता है तो मेरे ध्यान में लाएं, फौरन एक्शन लूंगा और सजा पूरी दिलवाई जाएगी ।

चौधरी उदय सिंह दलाल : स्पीकर साहब, पिछले 30 सालों से हरियाणा में जितनी वैटरनरी होस्पिटल बने हैं, इनको ब्लाक समितियों ने, ग्राम पंचायतों ने अपनी तरफ से पैसा इकट्ठा

करके बनवाया है, सारा पैसा गांव वालों से लेते हैं । क्या सरकार इस पालिसी को चेंज करेगी?

सरदार तारा सिंह : यह सैप्रेट क्वेश्चन हे, नोटिस दे दे

|

Income accrued from Auction of Shops

***275. Chaudhri Har Swarup Bura :** Will the Chief Minister be pleased to state --

(a) the total income accrued from auction of shops and licences given to Vendors at the Bus Stands in the State Depot-wise to Haryana Roadways during the year 1977-78; and

(b) whether the prices of articles and eatables meant for sale at the shops at Bus Stands are fixed by the Govt. or are being charged by the shopkeepers arbitrarily ?

मुख्य संसदीय सचिव (श्री जगन नाथ) :

(क) कथन सदन की मेज पर रखा जाता है ।

(ख) वस्तुओ की दरे उपायुक्तों की अध्यक्षता में जिला स्तर पर बनाई गई प्राइस कन्ट्रोल कमेटियों द्वारा नियत की जाती हैं ।

कथन

दुकानों की नीलामी तथा रेहड़ी वालों से प्राप्त किराया
से डिपो वाइज वर्ष 197 7-7 8 की कुल आय -

	रुपये
पैसे	
1. हरियाणा राज्य परिवहन, जीद	1,51,
605. 82	
2. हरियाणा राज्य परिवहन, हिसार (1- 4- 77 से 3 1- 1-7 8)	6,17,53
5.30	
3. हरियाणा राज्य परिवहन, भिवानी	2,53,63
1.00	
4. हरियाणा राज्य परिवहन, रोहतक	7,14,33
1.05	
5. हरियाणा राज्य परिवहन, रिवाड़ी	1,29,52
0.00	

64. 00	6.	हरियाणा	राज्य	परिवहन,	करनाल	12,24,6
2.00	7.	हरियाणा	राज्य	परिवहन,	कैवल	2,32,82
6.00	8.	हरियाणा	राज्य	परिवहन,	अम्बाला	5,26,79
00	9.	हरियाणा	राज्य	परिवहन, चण्डीगढ		12,265.
2.00	10.	हरियाणा	राज्य	परिवहन,	गुडगांवा	2,58,39
				कुल		41,23,5
62.17						

चौधरी हरस्वरूप बूरा : क्या चीफ पार्लियामैन्टरी सैक्रेटरी साहब को यह इल्म है कि बस अड्डे पर जो चीजें मिलती हैं वे शहर की वस्तुओं से ज्यादा मंहगी हौती' हैं?

श्री जगन नाथ : स्पीकर साहब, इसके लिए तो एक कमेटी बनई जाती है जिसका अध्यक्ष डी० सी० होता है । इसके सदस्य एक तो जी०एम ० होता है, एक सी०एम०ओ० होता है और एक नौन-आफिशियल आदमी होता है । इन चार आदमियों की कमेटी' औवशन से पहले कीमते निर्धारित करती है । उसी हिसाब से ये चीजें बिकती हैं ।

चौधरी हरस्वरूप बूरा : अध्यक्ष महोदय, इस सवाल के जवाब में चीफ पार्लियामैंटरी सैक्रेटरी साहब ने 41 लाख के करीब आमदनी बताई है जबकि असलियत में करोड़ों की आमदनी बस अड्डों पर कुए ती है । क्या ये बताने की कृपा करेंगे कि इन शौप्स को औक्शन करने की बजाय हौसपिटैलिटी डिपार्टामैंट द्वारा चलाने का प्रबन्ध किया जाएगा?

श्री जगन नाथ : इस समय ऐसा विचार नहीं है । यह एक सुजेशन है, इस पर हम गौर करेंगे ।

श्री फतेह चन्द विज : क्या चीफ पार्लियामैंटरी सैक्रेटरी साहब यह बताएंगे कि इनको इस किस्म की कोई शिकायतें मंत्री हैं कि इन दुकानों पर जो चीजें बिकती हैं उनका स्टैन्डर्ड बहुत घटिया है? यदि मंत्री है तो इन्होंने बस स्टैन्ड के दुकानदारों के खिलाफ कोई ऐक्शन लिया है?

श्री जगन नाथ : हम समय समय पर अफसरों को वहां भेजते हैं । मैं भी कई बार गया हू । हम इस चीज को सुधारने

की कोशिश कर रह हैं । क्योकि यह पुर! नी सर कर का बिगाड़ा हुआ ढांचा है इसलिए इसको सुधारने मे थोड़ी देर लगेगी ।

श्री मूल चन्द जैन : क्या चीफ पार्लियामैन्टरी सैक्रेटरी. यह बताएंगे कि जो कीमतें नीलामी से पहले कमेटी, जिसका जिक्र अभी इन्होंने किया है—, मुकर्रर करती है, उनकी. फ़ैहरिस्त हर डिपो पर लटकाई जाती है?

श्री जगन नाथ : जी हां, हर दुकान पर लटकाई जाती है ।

श्री मूल चन्द जैन : क्या चीफ पार्लियामैन्टरी सैक्रेटरी यह बताएंगे कि अगर कोई दुकानदार न लटकाता हो तो उसके खिलाफ ऐक्शन लिया जाएगा?

श्री जगन नाथ : अगर कोई न लटकाता हो तो माननीय सदस्य हमें बताएं हम अवश्य ऐक्शन लेने ।

चौधरी देस राज : क्या चीफ पार्लियामैन्टरी सैक्रेटरी साहब यह बताने की कृपा क रेंगे कि जो प्राईस फिक्स की जाती है उसका क्राइटेरिया क्या हे?

श्री जान नाथ : क्राइटेरिया तो कमेटी फिक्स करती है । वह सारे हालात को देख कर ही कीमतें फिक्स करती है ।

चौधरी भले राम : क्या चीफ पार्लियामैन्टरी सैक्रेटरी साहब बताने की कृपा करेंगे कि बहुत सारे स्टालज के पर जो

पांच पैसे या दस पैसे वापस देने की बजाय एक गोली दे देते हैं, उसके 'लिए कोई गवर्नमेंट के'। हिदायतें हैं? (हंसी)

(कोई जवाब नहीं दिया गया ।)

चौधरी ईश्वर सिंह : क्या चीफ पार्लियामैन्टरी सैक्रेटरी जी यह बताएंगे कि इन स्टालज से जो आमदनी होती है उसे यात्रियों की सुविधा के लिए बस स्टैन्ड के सुधार पर ही खर्च करने की कोई स्कीम सरकार के विचाराधीन है?

श्री जगन नाथ : ऐसी कोई स्कीम सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

श्री मूल चन्द जैन : क्या चीफ पार्लियामैन्टरी सैक्रेटरी साहब बताएंगे कि जैसे और दुकानों पर फूड इंस्पेक्टर जाकर देखते हैं कि 'किसी चीज में अडलटेरेशन तो नहीं है, उसी तरह इन बस स्टैन्ड के स्टालज पर जाकर भी पिछले साल किसी फूड इंस्पेक्टर ने जांच की है और किसी के खिलाफ कोई ऐक्शन लिया गया है ?

श्री जगन नाथ : उस कमेटी में सी0एम0ओ0 होता है और उसे इसीलिए रखा जाता है ताकि वह समय समय पर जाकर देखे कि चीजे खराब हैं या सही हैं ।

श्री मूल चन्द जैन : क्या उन्होंने कभी इस बात को देखा?

श्री जगन नाथ : इसके लिए अलग नोटिस दीजिए ।

श्री भले राम : क्या चीफ पार्लियामैन्टरी सैक्रेटरी बताएंगे कि यह जो प्राईस होती है यह मार्किट प्राईस से कितनी ज्यादा होती है?

श्री जगन नाथ : वह कुछ ज्यादा होती है, इसमें कोई शक नहीं क्योंकि वहां के खर्चे को देख कर ही ऐसा किया जाता है ।

चौधरी लाल सिंह : क्या चीफ पार्लियामैन्टरी सैक्रेटरी साहब यह बताएंगे कि बस स्टैन्डज के पर मुसाफिरों को उतरते और चढ़ते हुए जो स्क्रीन पिलाई जाती है उसको रोका जाएगा?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया ।)

श्री लहरी सिंह मेहरा : क्या चीफ पार्लियामैन्टरी सैक्रेटरी बताने की कृपा करेंगे कि उनके पास कोई ऐसी शिकायत आई है कि बस अड्डे पर जो कीमतें लगाई होती हैं उनसे दुगुनी या तिगुनी कीमतें चार्ज कर ली जाती हैं?

श्री जगन नाथ : ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है ।

चौधरी गंगा राम : क्या चीफ पार्लियामैन्टरी सैक्रेटरी साहब यह बताएंगे कि इन दुकानों में से यदि कोई दुकान हमारे रिटायर्ड फौजी चलाना चाहें तो उनको बोली देते वक्त कुछ रियायत देंगे?

श्री जगन नाथ : रियायत दी जा रही है ।

Bus Depot at Safidon

***242. Chaudhri Ram Kishan :** Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to set up a Bus Depot at Safidon, if so, the time by which it is likely to be set up ?

मुख्य संसदीय सचिव (श्री जगन नाथ) : इस समय सफीदों में उप डिपो खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है । लेकिन कुछ समय के बाद गौर करेंगे ।

Provision of Extra Facilities in the Buses of Haryana

Roadways.

***288. Chaudhri Shiv Ram Verma :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to provide more facilities to the passengers in the buses of Haryana Roadways, if so, the details thereof.

(b) the steps taken to ensure that the employees of Roadways behave properly with the passengers;

(c) the details of instructions if any issued by the Government for stoppage of the buses at the fixed bus stopping points; and

(d) the steps, if any, taken by the Government to ensure that the passengers get a bus to their destination after a short interval ?

मुख्य संसदीय सचिव (श्री जगन नाथ) :

(क) सवारियों को आरामदायक याता देने के लिए विभाग ने हाल ही में बसों के नमूनों में सुधार किया है । इन बसों में अच्छी अपहोल्सटरी लगाई गई है तथा लैगसपेस भी अधिक रखी गई है जिससे यात्री— सुगमता से बैठसकें । शीघ्र ही आरामदायक सीटों वाली नयी नमूने की एक्सप्रेस बसें भी चलाई जाएगी ।

(ख) समय समय पर चालक/परिचालकों को हिदायते दी जाती हैं कि वह यात्रियों से सद्दयवहार करे । महा प्रबन्धक अपने कर्मचारियों के साथ समय समय पर बैठके करते रहते हैं और इन बैठकों में इन्हें बालियों के प्रति सद्दयवहार से पेश आने के लिये कहा जाता है ।

(ग) चालक/परिचालकों को समय समय पर हिदायते दी जाती हैं कि वे बसे केवल निर्धारित बस अड्डों पर ही रोककरें ।

(घ) बसों में वृद्धि के कारण मार्ग पर बस सेवाओं में काफी वृद्धि हो गई है ।

चौधरी शिव राम वर्मा : अध्यक्ष महोदय, हमारी बहुत सी बसे ऐसी हैं जिनके शशि टूटे हुए हैं और खिड़कियां खड-खड करती हैं, बंद करने पर वे फिर खुल जाती हैं । सर्दी में तो वे सक से मारती हैं और गर्मियों में लू से मारेंगी । क्या चीफ पार्लियामैन्टरी सैक्रेटरी साहब इसका कोई प्रबन्ध करेंगे?

श्री जगन नाथ : उनका काफी प्रबन्ध किया जा रहा है । हमारे जो वर्क वहेस हैं वही पर वे ठीक कराई जाती है ।

श्री सुरेन्द्र सिंह : क्या चीफ पार्लियामैन्टरी सैक्रेटरी महोदय बताने की कृपा करेंगे कि यात्रियों की सुविधा के लिए जनता सरकार बनने के बाद बसिज के फलीट में और बसें जोड़ी गई है?

श्री जगन नाथ : आपने तो अपने समय में मारुति की घटिया बसों को जोड़-दिया था लेकिन हमने 200 के करीब अच्छी बसें जोड़ी है । (विघ्न)

श्री सुरेख सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरे सवाल का जवाब नहीं आया । मैं यह जानना चाहता हूं कि जनता सरकार बनने के बाद कितनी बसे बसों के फलीट में जोड़ी गई? (विघ्न)

श्री जगन नाथ : बताया तो है कि दो सौ बसें जोड़ी गई । (विघ्न)

श्री सुरेन्द्र सिंह : कोई नहीं जोड़ी गई । मुझे मुख्य मंत्री जी ने रिटन जवाब दिया है कि कोई बस नहीं जोड़ी गई ।
(विधन)

श्री फतेह चन्द विज : अध्यक्ष महोदय, पहले बच्चों को यह सुविधा थी कि वे बसों द्वारा घर से स्कूल और स्कूल से घर आ जा सकते थे । मैं चीफ पार्लियामेन्टरी सैक्रेटरी साहब से यह जानना चाहता हूँ कि क्या वह सुविधा अब है या वापिस ले ली गई है क्योंकि देखा यह गया है कि बस वाले बच्चों के लिए बस को खड़ी नहीं करते?

श्री जगन नाथ : सुविधा तो है लेकिन माननीय सदस्य को अगर कोई ऐसी शिकायत है तोवे हमारे नोटिस मे लाएं, हम दूर कर देंगे ।

श्री बलदेव तायल : क्या चीफ पार्लियामेन्टरी सैक्रेटरी साहब बताने का कष्ट करेंगे कि बसों के अन्दर जो ओवर लोडिंग होती है और जिसकी वजह से पालियों को बड़ा कष्ट होता है, उसको कब तक बंद कर देंगे?

श्री जगन नाथ : इसके लिए, अध्यक्ष महोदय, हम ज्यादा से ज्यादा बसे लगाने की कोशिश कर रहे हैं ।

चौधरी संत कंवर : अध्यक्ष महोदय, बसों की हालत इस वजह —से भी खराब है कि उसमें स्पेयर पार्ट्स ठीक तरह से नहीं डाले जाते और जो वर्कशाप इन्चार्ज हैं उन्होंने एक—एक लाख का

गबन किया है । पचास हजार का गबन हिसार में पकड़ा गया है और यह वही के कर्मचारियों ने पकडवाया है । मैं अध्यक्ष महोदय, चीफ पार्लियामैन्टरी सैक्रेटरी साहब से यह जानना चाहता हूं कि जिन कर्मचारियों ने इस गबन को पकडवाया था क्या उनको कोई प्रोत्साहन दिया गया और जो इसके लिए दोषी थे, उनके खिलाफ कोई कार्यवाही की गई?

श्री जगन नाथ : स्पीकर साहब, जो दोषी होते हैं उनको सजा मिलती ही है और जो दोषी को पकडवाता है उसे इनाम भी मिलता है ।

श्री दीप चन्द भाटिया : स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा चीफ पार्लियामैन्टरी सैक्रेटरी साहब से यह पूछना चाहता हूं कि ये जो हिदायते करते हैं, निर्देश देते हैं, उनकी तामील भी होती है या नहीं? (हंसी एव विघ्न)

श्री जगन नाथ : भाटिया साहब की शिकायत में कोई ऐसी खास बात नहीं है । मैं और मेरे अफसरों के बीच में काम के बारे में ठीक समझौता है । ठीक तरह से काम हो रहा है ।

श्री दीप चन्द भाटिया : स्पीकर साहब, अगर यह गलत बात हो तो मैं रिजाइन करने के लिए तैयार हूं ।

श्री जगन नाथ : अगर ऐसी कोई बात है कि उनकी शिकायत पर कोई एक्शन न लिया गया हो तो मैं उसको ठीक करने के लिए तैयार हूं ।

श्री दीप चन्द भाटिया : मेरे सामने आपने टेलीफोन किसी काम के लिए किया । आपने पहले ही कहा कि “साहब” ऐसा करे । मेरी समझ मे नही आता कि मिनिस्टर ही ऐसे ढंग से बात करते है तो कैसे काम कर सकेंगे ।

श्री मूल चन्द जैन : चीफ पार्लियामैन्टरी सैक्रेटरी साहब बताने की कृपा करेंगे कि ड्राइवर और कन्डक्टर के बिहेवियर के बारे में हर बस में एक कम्प्लेंट बुक होती है, उन कम्पलेन्ट बुक में दर्ज की गई शिकायतें उनके नोटिस में आयी हैं, अगर उनके नोटिस में आयी हैं तो एक्शन क्यों नही लिया जाता? जो पैसेजर शिकायत करता है, डिपार्टमेंट की तरफ से उनको कोई भी जवाब क्यों नहीं दिया जाता है?

श्री जगन नाथ : आपने तो काफी लम्बा प्रश्न पूछ लिया, इसके लिए तो अलग से नोटिस दें ।

श्री अध्यक्ष : वे यह कह रहे है कि जो शिकायत आती हैं उनको खुद देखते हैं ।

श्री जगन नाथ : खुद क्या— देखूं । मैंने तो पहले खुद कम्प्लेंट भी कीहुई है ।

श्री लछमन सिंह : जिस तरह से अभी भाटिया साहब ने कहा है कि इसी तरह की बात मैं भी सरकार के नोटिस में लाना चाहता हूं । मैंने चीफ पार्लियामैन्टरी सैक्रेटरी साहब से आर्डर कराये कि फलां जगह से फलां जगह तक बस चलायी जाये लेकिन

वे आर्डर यों के यों ही रद्दी की टोकरी में डाल दिये गये, उन पर कोई एक्शन नहीं हुआ ।

श्री जगन नाथ : अगर ऐसो कोई बात है तो एक्शन ले लेंगे ।

कंवर राम पाल सिंह : कम्पलेन्ट-बुक में कम्पलेन्ट दर्ज हुई है । कन्डक्टर और ड्राइवर के बिहेवियर के बारे में कम्पलेन्ट लिखने के बावजूद भी उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता है । अगर उनके परसनल नोटिस में यह बात है तो आपने क्या एक्शन लिया है और क्या लेने जा रहे हैं?

श्री जगन नाथ : समय समय पर एक्शन लिया गया और आगे भी लेने की कोशिश करे ।

चौधरी ईश्वर सिंह : स्पीकर साहब, मैं आपकी मार्फत चीफ पार्लियामैंटरी सैक्रेटरी साहब से पूछना चाहता हूँकि मेरा हल्का बोर्डर पर लगता है वहां पर न पंजाब की बसों की सुविधा है और न ही हरियाणा की बसों की सुविधा है क्योंकि दोनों स्टेटस का झगड़ा है, इसलिए इन हालातों को देखते हुए यात्रियों की सुविधा के लिए कोई प्रबन्ध करने का विचार है?

श्री जगन नाथ : वालियों की सुविधा का सरकार प्रबन्ध बराबर कर रही है ।

साथी अयोध्या प्रशाद : क्या मिनिस्टर साहब के नोटिस में यह बात है कि कई बसों में कम्पलेट बुक ही नहीं होती है और अगर होती है तो कई बार कंडक्टर मांगने पर भी नहीं देते हैं?

श्री जगन नाथ : ऐसा हो सकता है । ड्राइवर और कन्डक्टर शरारत कर देते हों ।

श्री शमशेर सिंह : क्या चीफ पार्लियामैन्टरी साहब बताने का कष्ट करे गे कि ट्रांसपोर्ट की परफोरमेन्स के बारे में जो मैम्बर साहिबान ने सवाल पूछे हैं उनको देखते हुए क्या सरकार पैसेन्जर टैक्स को वापिस लेगी?

डा० मंगल सैन : यह कैसे रेलेवैन्ट हे?

श्री कन्हैया लाल पोसवाल : यह पूर्ण रूप से रेलेवैन्ट है क्योंकि लोगों को फैसेलिटीज नहीं दी जा रही हैए ।

चौधरी उदय सिंह दलाल : अभी चीफ पार्लियामैन्टरी सैक्रेटरी साहब ने बताया कि जो शिकायतें आती हैं उनको दूर किया जाता है । मैं आपकी मार्फत एक मिसाल देना चाहता हूं, मैंने एक चिट्ठी सरकार को लिखी थी । जो लफज उस कन्डक्टर ने कहे थे वे लफज भी मैंने लिजे थे । 25 सवारियों की टिकट कन्डक्टर ने नहीं काटी थी । मैंने उससे कहा कि टिकट क्यों नहीं काटता तो उसने जवाब दिया कि “सरकार को क्या लौस होगा, मुझे भीतो पैसेकी जरूरत है, नौकरी चली जायेगी तो चली जाये, अगर आप नौकरी छुड़वा देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी” लेकिन

आज तक महकमे ने इस बारे में कोई एक्शन नहीं लिया । इससे खराब बात और क्या हो सकती है?

श्री जगननाथ : अगर ऐसा किसी ने जवाब दिया है तो उस कर्मचारी के खिलाफ जरूर एक्शन लेगे । दूसरे हमारे कुछ अफसर रेड्डी कमीशन में फंसे हुए हैं इसलिए जवाब देने में लेट हो गये है ।

श्री जब नारायण : मंत्री महोदय ने बताया था कि दो सौ नयी बसें सरकार मंगा रही है । मैं चीफ पार्लियामैन्टरी सैक्रेटरी साहब से पूछना चाहता हूं कि डिस्ट्रिक्टवाइज कितनी-कितनी बसे दी जायेगी और रोहतक जिले को कितनी दी जायेगी? श्री कान नाथ डिपो की इम्पोर्टेन्स के हिसाब से बांटी जायेगी ।

चौधरी खुरशीद अहमद : क्या मिनिस्टर— साहब के नोटिस में यह बात है कि सौ, सवा सौ बसों के बेंक—डाउन होते हैं, अषार ऐसा नहीं है तो मैं यह जानना चाहता है एग— जेक्ट स्टेटिक्स क्या हे?

श्री जगन नाथ : आप अलग से नोटिस दे दें जवाब दे दिया जायेगा । ज्यादा ब्रेक— डाउन का कारण यह भी है कि बाढ़ के कारण सड़के टूट गई हैं ।

श्री सुखदेव सिंह : जिस प्रकार से सरकार 'ने आठवीं 'कलास तक के बच्चों को फ्री लेवल करने की सुविधा दी हुई है',

इसी प्रकार से दसवी कलास के बच्चो को भो' बसों में फ्री ट्रेवल करने की सुविधा देंगे ।

(कोई उत्तर नहीं त्वया गया ।)

चौधरी राजेन्द्र सिंह : क्या चीफ पार्लियामेंटरी सैक्रेटरी साहब बताने का कष्ट करेंगे कि हरियाणा में कुल कितनी बसे ऐसी हैं 'जिन की लाईफ खत्म हो गई और फिर भी इस्तेमाल की जा रही हैं'?

श्री जगन नाथ : लाइफ खत्म होने के बाद कोई चीज चलती नहीं है । लेकिन फिर भी नोटिस दे दे जवाब दे दिया जायेगा ।

श्री देवी दास : चीफ पार्लियामेंटरी सैक्रेटरी साहब ने कहा था कि चण्डीगढ से दिल्ली को जो नाइट सर्विस चलती है वह वाया सोनीपत नही जा सकती । मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं कि क्या मुरथल बस स्टैन्ड पर रोकने की कृपा करेंगे, अगर वहां बस रोकी जायेगी तो किराया चण्डीगढ से मुरथल का चार्ज कर लिया जाया करेगा?

श्री जगन नाथ : अलग से नोटिस दें ।

श्री ओम प्रकाश : हर गांव में लोग बस अड्डा चाहते हैं लेकिन बसें रुकती नही हैं । मैं चीफ पार्लियामेंटरी सैक्रेटरी साहब

से यह जानना चाहता हूँ कि हर गांव में बस अड्डा बनाने या बस रुकवाने की क्या कंडीशन हैं, क्या क्राइटेरिया है?

श्री जगन नाथ : हरेक गांव में बस नहीं रोकी जा सकती ।

श्री अध्यक्ष : थोड़ा बहुत जवाब तो दे । आपका जवाब तो मैंने भी नहीं सुना ।

श्री जगन नाथ : मैंने सवाल ही नहीं सुना, जवाब क्या द । मैंने साथ वाले से सुना है ।

Mr. Speaker : I think, this is the limit. This is not right. If a responsible Minister says that he has not listened to the question, how would he answer, this is not fair. If he has not listened .to. the question, he should ask the hon. Member to repeat the question.

श्री ओम प्रकाश : मेरा सवाल यह है कि कई गांव में बसें नहीं रुकती हैं । रोड पर गांव होते हुए भी बस नहीं रुकती है और उस सवारी को अगले गांव तक का किराया देना पडता है जब कि उसका गांव का जहां बस रुकती है आधा फरलाम का फासला होता है तो मैं यह जानना चाहता हूँ कि जो बस अड्डे बनाये हैं उनकी क्या कन्डीशन हैं और क्या क्राइटेरिया है?

श्री जगन नाथ : तीन मील की लिमिट होती है । हर मील पर या आधा मील पर बस स्टैंड मंजूर होते हैं इसलिए अगले गांव तक या पिछले गांव तक का किराया लिया जाता है ।

श्री ओम प्रकाश : मैं चीफ पार्लियामेंटरी सैक्रेटरी साहब से जानना चाहता हूँ एक मील या दो मील पर बस रोक दी जाये तो डिपार्टमेंट को क्या नुकसान होता है?

श्री जगन नाथ : उस पर देखेंगे, गौर किया जायेगा ।

श्री मूल चन्द जैन : ट्रांसपोर्ट विभाग के ड्राइवरों और कन्डक्टरों की वार्किंग के बारे में इतनी शिकायतें क्यूँ और हाउस में डिस्टैटिस फैकशन है तो क्या चीफ पार्लियामेंटरी सैक्रेटरी साहब इन शिकायतों को निपटाने के लिए कोई खास अफसर मुकरर करेंगे ताकि लोगों को दिक्कत न हो?

श्री जगन नाथ : अफसर पहले ही लगाये हुए हैं । फलाईंग सुक्वैड है, जी० एम० है । वे समयसमय पर चौक करते रहे हैं ।

चौधरी लाल सिंह : क्या मन्त्री महोदय बतायेगे कि पिछली सरकार ने जो बसें रंग करके चलाई हुई हैं, उन लोगों के खिलाफ भी कोई एक्शन लिया जायेगा?

श्री जगन नाथ : उसको लिए रेड्डी कमीशन बैठा हुआ है

।

चौधरी संत कंवर : स्पीकर साहब यह बताया गया है कि आरामदायक यात्रा देने के लिये विभाग ने हाल ही में बसों के नमूनों में सुधार किया है क्या चीफ पार्लियामेन्टरी सैट्क्रेरी बताने की कृपा करेंगे कि कितनी बसों के नमूनों में सुधार किया है? क्या जो दो सौ नई बसें आयेंगी वह सारी बसें नये नमूनों से आयेंगी या उनमें से कुछ ही बसें नये नमूने की आयेंगी?

श्री जगन नाथ : इसके लिये सैपरेट नोटिस चाहिए क्योंकि यह एक अलग सवाल है ।

चौधरी मेहर सिंह राठी : क्या चीफ पार्लियामेन्टरी सैट्क्रेरी साहब यह बताने की कृपा करेंगे कि रोहद और जाखोदा में जो 'कि 3- 4 मील के फासले पर हैं', वहाँ पर कहीं भी बस नहीं रुकती, इसके इलावा नून माजरा जो कि झज्जर रोड़ पर है वहारू पर भी बस नहीं रुकती, इसके बारे में हमने कई बार शिकायत भी की है, इसके बारे में कोई एक्शन लेने के लिये तैयार हैं?

श्री जगन नाथ : इसके लिए बार-बार हमने हिदायत दी हुई है । जहां तक शिकायत का ताल्लुक है, अगर कोई शिकायत करता है तो उस पर फौरन ही एक्शन लिया जाता है ।

तारांकित प्रश्न संख्या 303

यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि माननीय सदस्य श्री देवेन्द्र शर्मा इस समय सदन में उपस्थित नहीं थे ।

Consumption of Electricity

***340. Chaudhri Des Raj :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state the canal-wise and crop-wise total consumption of electricity on the pumps functioning on the canal running under lift irrigation scheme and the amount paid during the years 1974-75, 1975-76, 1976-77 by each pump in the State ?

Irrigation and Power Minister (Shri Verendar Singh) : A statement showing the canal-wise and crop-wise total consumption of electricity and the amount paid for each pump functioning en the canals running under lift irrigation schemes during the years 1974-75, 1975-76. 1976-77 is laid on the table of the house.

STATEMENT

Pump House No.	1974-75				1975-76				1976-77			
	Kharif		Rabi		Kharif		Rabi		Kharif		Rabi	
	Exp.	Cons.	Exp.	Cons.	Exp.	Cons.	Exp. ,	Cons.	Exp.	Cons.	Exp.	Cons.
Jui Canal Lift Scheme	Rs.	Unit	Rs.	Unit	Rs.	Unit	Rs.	Unit	Rs.	Unit	Rs.	Unit
JuiCanal PHI	146197	72030 5	250536	101403 9	321070	163142 1	250124	185840 5	188096	79051 0	188314	105365
JuaCanal PH.II	97116	86622 0	200157	732442	225273	106921 9	178086	118160 6	168368	53065 8	146752	92239
Jui Canal P.H.III	110143	46682 1	164910	492810	227714	894075	161528	105148 8	196733	56063 3	156259	83876
JuiCanal P.H.V.	73865	32268 0	111893	382696	152161	667851	69745	538947	108138	34512 4	98461	508342
JuiCanal P.H.V.	84464	31851 8	110234	358500	169689	763126	80805	685266	107151	36988 1	96061	571120
JuiCanal RUNT	66324	21004 5	95255	248265	142463	582140	65373	473487	93996	25179 0	78998	401470

Jul Canal	52508	90805	65535	92985	97703	276440	44380	211405	66949	95220	57730	213015
P.H.VI[.												
Main Canal.												
1. Lohru Canal	200420. 3	75098 5	482093.1 6	100118 5	437039. 61	139612 6	430263.5 5	393603 5	272024.2		1823930. 368035.6 5	168347
2. 10-	- 223812. 6	62030 9	424908.0 4	161218 3	419154. 45	101202 8	409634.8 4	168673 4	279088.7 2	86933 5	432896.1 9	198408
3. Jo-	- 172889. 37	53729 1	378350.9 7	616239	432321. 27	988507	408213.5 6	169218 6	306078.6 9	74474 9	313644.7 7	160928
4. Loharu Canal	177387. 42	53132 2	378427.7 7	581546	183278. 32	819808	335216.3 7	131703 7	247795.8 3	72632 6	391388.7 7	168874
5. do-	- 189640. 83	52228 5	323632.8 4	100939	339243. 87	421966	270108.0 2	145634 9	424718.6 4	69751 2	341915.0 7	134628
6. -do-	151620. 76	28677 0	285626.7 6	309900	274931. 85	531285	224194.3 7	742040	196196.1 6	46207 0	307400.6 6	857897
7.	77591.3	88917	174327.7	157355	11471.8	239903	138863.8	514077	115391.7	26827	110066.7	565631

PH-1 RD 20	40403.2 5	24355	16953.2	7905	58880.5 5	128771	27417.45	159730	53242.4	11491 5	58849.9	97114
PH 2 RD 47	8098.25	743	5713.93		8630.39	-	6630.39	770	5330.02	670	5097.97	2957
SIWANI LIFT	IRR. SCHEME	.										
1.- Siwani Feeder	Channel	Pumps										
No.]	-	-	-	-			8492.89	33972	196555.7 3	11707 47	85729.07	484375
No.2	-		-	-	-	-	42626.6	170505	110465	71852 0	68675.71	467820
No.3	-	-	-	-	-	-	7594.31	36377	104667.1	53450]	88744.12	218300
No. 4	-	-	-	-	-	-	-	-	77003.32	31770 9	85685.12	173950
No. 5	-	-	-	-	-	-	13012.01	52048	68844.62	31407 2	40534.27	38921
No.6	-	-	-	-	-	-	9672.95	38692	30547.55	30441	28813.83	3029
No.7	-	-	-	-	-	-	31450.81	125803	20973.52	48348	33399.26	4432

											4		
No.8	-	-	-	-	-	-	6652.05	26608	26287.7	19934	52617.68	9265	
No.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.	Feeder Pumps.												
Deosar													
Rupana	-	-	-	-	-	-	8513.16	42565	15648.29	88024	10116.26	30009	
Deosar	-	-	-	-	-	-	7924.92	39635	17099.96	11522	10475.59	37837	
										9			
3.	Channel Pumps												
Nigana Feeder													
No.1	-	-	-	-	-	-	698.74	275840	76036.64	39384	93187.72	40640	
No.2	-	-	-	-	-	-	785.74	15338	55687.17	26760	58215.85	27880	
No.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1374.93	6017	
No.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3586.99	24578	
No.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3529.37	12675	

No.6

- - - - -

Statement showing information regarding canal-wise total consumption of electricity on the pumps on Lift Irrigation Scheme and the amount paid during the year 1974-75,75-76 and 76-77.

S.No. Name of canal alongwith pump Houses	Year 1974- 75	Year 1975-76				Year 1976-77						
		Exp.	Cons.	Exp.	Cons.	Exp.	Cons.	Exp.	Cons.			
1. Rewari Lift Irrigation Scheme												
Pump House No. 1.	59179	146750	103501	234428	95137	292970	64223	208950	81785	216206	66823	19344
Pump House	35419	80386	67183	102422	63310	139117	60282	163357	79396	59044	46899	42345

No. II.

Jhajjar Lift	Irrigation	Scheme										
Pump House No.1	21779	—	34314	—	2286 1	—	3535 5	—	42014	—	7161 7	—**
Pump House No. 2	36412	—	24011	—	3733 4	—	2409 4	—	75040	—	8321 8	—
Pump House No. 3	5100	—	5700	—	7636	—	5663	—	14020	—	1617 9	—
Pump House No. 4	2700	—	7100	—	2863	—	7212	—	9810		1226 7	—
Pump House No. 5	41000	—	5200	—	4191	—	5314	—	21500	—	2434 4	—

** No meters have been fixed on pump houses on jhajjar Lift

Irrigation Scheme.

चौधरी देस राज : क्या मिनिस्टर साहब यह बताने की कृपा करेंगे कि लिफ्ट इरीगेशन स्कीम पर मीटर्ज क्यों नहीं लगाये गये हैं? 12

श्री वीरेन्द्र सिंह : मीटर्ज जो नहीं लगाये गये हैं वह मीटर्ज की कमी होने के कारण हैं ।

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू : स्पीकर साहब, मैं वजीर साहबसे यह पूछना चाहता हूँ कि मीटर्ज की कमी कब तक दूर हो जायेगी?

श्री वीरेन्द्र सिंह : स्पीकर साहब, मीटर्ज की कमी अब तो वैसे ही दूर हो जायेगी क्योंकि अब फ्लैट रेट आ गया है । सैकिण्डली यह सवाल बहुत इम्पोर्टेन्ट है । कल भी बाबू मूल चन्द जैन जी ने इस बारे में कुछ कहा था कि लिफ्ट इरीगेशन स्कीम पर बहुत खर्च किया गया है । मैं स्पीकर साहब, आपकी इजाजत से यह बताना चाहूंगा कि लिफ्ट इरीगेशन स्कीम का पहले मूद्दा तो यह रहा होगा कि जिस एरिया में से यह जा रही है, उस एरिया के सारे गांव, आपको पता ही है कि इस किसम का इलाका था जहां पर लोग पानी के दर्शन करने के लिये तरसते थे ओर पानी पहुंचाना उनके लिए एक बड़ा भारी पुण्य होगा, को पानी दिया जाये । इस स्कीम को कामयाब करके नहरों को पैरीनीयल बनाने में जो भी पैसा इस पर खर्च आया, उसकी फिगरज हमारे पास हैं उसके हिसाब से 225. 18 लाख रुपया लगा और 197 4-7

5, 197 5-7 8 और 197 6- 77 इन तीनों सालों में जो काप हमारे हिसाब से हुई है वह साढ़े सात सौ लाख रुपये की बैठती है । तो इस काम के लिए इन हालात में नान पैरीनीयल नहरों को औरीनीयल बनाने के लिए 5 करोड़ रुपया रखा गया है । इसी नहरों से पीने का पानी भी लोगों को सप्लाई करना है ।

श्री लहरी सिंह मेहरा : क्या मन्त्री महोदय यह बतायेंगे कि जहां पर आपने लिफ्ट इरीगेशन स्कीम शुरू की हुई है और पानी वहाँ पर पम्पों का जमीन में काफी नीचे चला गया है, उसका क्या इन्तजाम सरकार करने जा रही है?

श्री वीरेन्द्र सिंह : . स्पीकर साहब, मेरे ख्याल में यह आगुमैटेशन ट्यूबवैल्ज की बात कर रहे हैं । इसके लिए सैपरेट नोटिस चाहिए । अगर आप कहें तो मैं जवाब दे देता हूँ ।

The number of Stipendry, Ad-hoc JBT

Teachers and B.ED. Masters

***403 Rao Dalip Singh :** Will the Minister for Education be pleased to state -

(a) the total number of stipendry , Adhoc JBT Teachers and B.Ed. Masters in the State separately to date; and

(b) whether there is any proposal under consideration of the Government to regularise the services of the employees as referred to in part (a) above ?

शिक्षा मंत्री (कर्नल राव राम सिंह) :

(ए) जे० बी० टी० बी० एड० कुल
जोड़

अध्यापक मास्टर / मिस्टरज

(1) स्टार्डिपेन्डरी 8674 2230
10904

(2) एडहाक 984 542 1526

(बी) मामले का निरीक्षण किया जा रहा
है ।

राव दलीप सिंह : क्या मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि मामले का निरीक्षण करने में एक दो महीने लगेंगे या 7-8 साल लग जायेंगे?

कर्नल राव राम सिंह : यह काम जल्दी से जल्दी खत्म करने की कोशिश की जायेगी । The Government is seized of the problem. जो पिछली सरकार थी उनसे मास्टरों के साथ, जे०बी०टी० टीचर्स के साथ मेरे विचार में बड़ा घोर बेइन्साफ किया था कि सात साल तक टीचर्स की अप्वायंटमेंट रैगुलर नहीं की । मैं माननीय सदस्यों के नोटिस में यह बात लाना— चाहता हूँ कि सन् 1970 से सन् 1977 तक एक भी टीचर उन्होंने रैगुलर अप्वायंट नहीं किया । सब को एडहाक बेसिक पर 7 साल तक—

चलाते रहे । किसी भी टीचर को परमानेंट बेसिज पर नहीं लगाया, सब को एडहाक, टैम्पोरेरी लगाया । किस क्राइटेरिया पर उनको एडहाक, सिक्स मन्थस बेसिज पर रखा जाता था यह मैं माननीय सदस्यों के इमैजीनेशन पर छोड़ता हूँ । मैं यह आश्वासन देना चाहता हूँ कि मामला बहुत गम्भीर है तकरीबन 1 5 हजार टीचर्ज इन्वाल्वड हैं, उनको रैगुलर करने में टाईम लगेगा । गवर्नमेंट इस बारे में पालिसी पर विचार कर रही है और तकरीबन-तकरीबन फाइनेलाईज हो चली है जल्दी से जल्दी उस पर कार्यवाही करके उनको रैगुलर बनाने के आदेश जारी कर दिये जायेगे ।

श्री भले राम : क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि एडहाक और स्टाइपेंडरी टीचर में क्या फर्क है?

कर्नल राव राम सिंह : यह दो टर्मज बड़ी देर से चली आ रही हैं । मेरे ख्याल में ये मिसनौमर हैं क्योंकि यह असली मायना कन्वे नहीं करती । जो मायना इस डिपार्टमेंट में निकाला जाता है वह मैं बता देता हूँ । स्टाइपेंडरी टीचर्ज कहां है जो स्ट्राईक से पहले एडहाक बेसिज पर लगाये गये । स्ट्राईक के दौरान लगाये गये और स्ट्राईक के खत्म होने से पहले लगाये गये है । इन्हे स्टाइपेंडरी टीचर्ज कहते हैं । जो टीचर स्ट्राईक 'के बाद लगाये गये, उन्हें एडहाक टीचर्ज कहते है ।

चौधरी हरि चन्द हुड्डा : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि उनके पास कोई ऐसी शिकायत आयी है कि

एडहाक बेसिज पर जो टीचर्ज लगरू! ये गये हैं, उनमें से कुछ टीचर्ज पिछले एम0एल 0एज 0 के सिफारिशी थे? क्या ऐसी— कोई शिकायत उनके पास आयी है?

कर्नल राव राम सिंह : मैं सवाल नहीं समझा । (विधन) इसके बारे में मैं एक बात जरूर अर्ज करना— चाहूंगा कि जो भी टीचर्ज स्टाइपेंडरी और एडहाक 'टीचर्ज' लगाये गये हैं, वे सब हमारे ही बच्चे हैं हरियाणा के ही तो रहने बॉले हैं और अब हमारे पीसे काम भी कर रहे हैं, हम उनके केस को पूरी सिम्पथी के साथ विचार करेंगे चाहे वे किसी भी एम0 एल 0ए 0 के रहे हों ।

श्री लहरी सिंह मेहरा : जैसे कि मंत्री जी ने बताया कि 1 5 हजार टीचर्ज इससे अफैक्टिड हैं, क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि उनमें से कुछ को हटा दिया जायेगा । अगर हटा दिया जायेगा तो कब तक तथा क्यों हटा दिया जायेगा?

कर्नल राव राम सिंह : यह सारा मामला विचाराधीन है । इसके बारे में इस वक्त मैं कुछ कह नहीं सकता । मैं इस वक्त इतना ही कहना चाहता हूँ कि सारे टीचर्ज हमारे अपने बच्चे हैं, उनके मामले दुम सिम्पैथटीकली कंसीडर करेंगे ।

चौधरी गंगा राम : अध्यक्ष महोदय, जिस समय हम मीसा के अन्दर जेल में पड़े हुए थे, उस समय हरियाणा के जितने भी एडहाक बेसिज पर लगे हुए जे 0.बी टी0 और बी0 ए 0बी0एड0 टीचर्ज नै रैगुलर होने के लिये जीन्द के अन्दर एक फन्कशन किया

था और उस फन्कशन में श्री सुरेन्द्र सिंह जी को नेता बनाया था । उन्होंने यह वायदा किया था कि मैं नेता बनने के बाद आपको रैगुलर करा दूंगा और इनके गले में 50 हजार रुपये की माला टीचर्ज ने डाली थी । मैं मंत्री महोदय से और सरकार से यह पूछना चाहूंगा कि क्या वह 5 0, 000 रुपये वापस लेने के लिये कोई इन्कवायरी बैठायी गयी है, अगर नहीं बैठायी गयी है तो इन्कवायरी होनी चाहिये और वह 5 0, 000 रुपया वापिस लिया जाना चाहिये?

कर्नल राव राम सिंह : जीन्द तौ बहुत अमीर इलाका है । बावल जो भूखा इलाका है, बावल की 84, वहां से 2 लाख रुपये की माना, जब यह वायदा किया गया था कि वह माला एकदम बावल कालेज. को ने दी जायेगी, वह फौरन उस वक्त के रक्षा मंत्री जी ने एकदम युवक, हरियाणा के युवक नेता के गले के अन्दर डाल दी और वह 5 मिनट के अन्दर गायब हो गयी ।

चौधरी सरदार खां : स्पीकर साहब, गवर्नमेंट ने एडहाक और स्टार्डिपेडरी टीचर्ज के बारे में तो पालिसी तय. भर दी कि. उनको रेगूलर किया जाएगा । क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जो टीचर्ज, जे 0बी टी0 टीचर्ज अभी तक अनएम्प्लाएड है उनके बारे में सरकार की क्या पालिसी है?

कर्नल राव राम सिंह : अनएम्प्लाएमेंट की पात यह है कि बी0एड0 टीचर्ज तकरीबन दस—बारह हजार एम्प्लाएमेंट

ऐक्सचेन्ज में रजिस्टर है और जे 0बी0 टी0 की फिगरज इस वक्त मेरे पास नहीं हैं लेकिन मेरे ख्याल से पांच-छ हजार एम्प्लायमेंट ऐक्सचेन्ज की लिस्ट पर हैं । जैसे भी वेकेन्सीज क्रिएट होती जाएंगी वै से उनको एम्पलाय किया जाएगा लेकिन उनको सौ परसेन्ट एम्प्लायमेंट की गारन्टी सरकार नहीं दे सकती ।

चौधरी गुलजार सिंह : क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि 1970-71 से जो एक हजार टीचर्ज एडहाक पर लगे हुए हैं क्या सरकार का उनको रेगूलर करने का कोई विचार है?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

Mr. Speaker : Question Hour is over please.

**नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गये
तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर**

**Amount Sanctioned for the Construction of Chaff
al**

***369. Shri Mool Chand Jain :** Will the Minister for Revenue be pleased to state —

(a) whether it is a fact that a sum of Rs. 5000/- was sanctioned for the construction of Chaupal for Harijans in Village Jalwana, Tehsil Panipat, District Karnal

(b) if so, whether the amount has been disbursed; if not the reasons thereof ?

राजस्व मन्त्री (श्री प्रीत सिंह) :

(क) जिला करनाल की तहसील पानीपत में जलवाना नाम का कोई ग्राम नहीं है । परन्तु तहसील पानीपत में जलमाना नाम का एक ग्राम है और इस ग्राम की चौपाल के लिए कोई राशि स्वीकृत नहीं की गई थी ।

(ख) उपरोक्त (क) के दृष्टिगत प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

Loharu High School

***435. Shri Hira Nand Arya :** Will the Minister for Education be pleased to state the amount sanctioned for the building of Loharu High School togetherwith the time by which the work will be started thereon ?

शिक्षा मन्त्री (कर्नल राव राम सिंह) : इस कार्य के लिये मार्च, 1977 में 12,07,000 रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई थी परन्तु वित्तीय कठिनाई के कारण इसके लिये राशि की व्यवस्था नहीं की जा सकी । सरकार ने समस्त नये निर्माण कार्यों पर प्रतिबन्ध लगा दिया है इसलिये इसके आरम्भ करने के लिये कोई समय सीमा नहीं बताई जा सकती ।

Whole-time Employees of the Home Guards

***456. Shri Kanwal Singh :** Will the Minister for Industries be pleased to state—

(a) whether the whole-time employees of the Home

Guards have not been given pension on retirement ;

(b) if so, whether it is a fact that their service has been declared non-pensionable; and

(c) if so, a copy of the letter or memo as referred to in part (b) above, be laid on the table of the House '?

उद्योग मन्त्री (डा 3 मंगल सैन) :

(ए) मुख्यालय स्टाफ के पद पहले से ही पेंशनेबल है जबकि क्षेत्रीय पदों को 30 1- 1975 से पेंशनेबल घोषित कर दिया गया है और इस प्रकार जो पूर्ण-कालिक कर्मचारी 30- 1- 75 से पहले क्षेत्रीय पदों से रिटायर हुये थे, उन्हें पेंशन नहीं दी गई है ।

(बी) ऐसे कोई स्पष्ट आदेश जारी नहीं किये गये जिन द्वारा इन पदों को नान-पेंशनेबल घोषित किया गया हो ।

(सी) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

Suspension of Sarpanches

***458. Shri Mani Ram :** Will the Minister for Development and Panchayats be pleased to state

(a) whether any enquiry was conducted against the suspended Sarpanches of Gram Panchayat Saktakhe on 19-10-1977 by A.G.A. Sirsa; if so, the result thereof ; and

(b) the. number of suspended Sarpanches who are found guilty after making the enquiry togetherwith the action

taken against them ?

****Interim Reply**

Tara Singh,
78/1060

D.O.No. LA 2 (DPH)-

Development Minister,
Haryana.

Development

8th March, 1978.

Subject : — Starred Assembly Question No. 458.

My dear Brig. Sahib,

The Starred Assembly Question 458 asked by Shri Mani Ram, M.L.A. has been fixed for answer on 9.3.78. The reply to the Assembly Question is not ready as the required information is awaited from the Deputy Commissioner, Sirsa.

I shall be grateful if you kindly extend the time for answering the question under proviso (2) of Rule 41 (II) of the Rules of Procedure and conduct of business in the Punjab Legislative Assembly 1950. This question may be included in the list of questions for any date after 21st March, 1978.

With regards,

Yours sincerely,

Sd/-

(Tara Singh)

Brig. Ran Singh,
Speaker, Haryana Vidhan Sabha,
Chandigarh.

Complaint against Doctor of E.S.I. Dispensary

***467. Lala Balwant Rai Tayal :** Will the Minister for Health be pleased to state --

(a) the number of complaints received so far against the Doctor of E.S.I. Dispensary No. 1 of Hissar since March, 1977 together with the action taken thereon ;

(b) the details of the enquiry, if any, conducted on these complaints be placed on the table of the House; and

(c) the time by which the Hospital constructed near E.S.I. Dispensary No. 1 Hissar is likely to start functioning ?

Food and Supplies Minister (Shrimati Dr. Kamla Verma) :

(a) Fourteen complaints have been received against the doctors of E.S.I. Dispensary No. 1, Hissar since March, 1977. Eleven complaints are against one doctor and the remaining three against the other doctors posted in this dispensary from time to time. Enquiries have been made in respect of ten complaints and the remaining four)are still being enquired into. Some of the allegations contained in these ten complaints have been proved and the reports of the enquiry officers are under consideration for taking necessary

disciplinary action against the defaulters.

(b) The enquiry reports are still under consideration for taking action. Hence it is not advisable to place them on the table of the house.

(c) The building of the 12- bedded ward is almost complete. As soon as possession is given to the health department, the ward shall be commissioned.

Sugar Quota

***472. Shri Mange Ram Gupta :** Will the Minister for Health be pleased to state the reasons for not giving the quota of sugar so far to the village depot set up by the Government in Village Jamni, Tehsil Safidon, District Jind ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्रीमती डाक्टर कमला वर्मा) : गांव जामनी में चीनी का मासिक राशन मिनी बैंक के डिपू द्वारा लोगों को नियमित रूप से दिया जा रहा है ।

Panchayat Bhawan at Chandigarh

***215. Shri Shamsheer Singh :** Will the Minister for Development and Panchayats be pleased to state—

(a) whether Panchayat Bhawan at Chandigarh was planned to provide cheap accommodation at nominal payment for the rural population of Punjab and Haryana and its cost of construction was met by Panchayati Raj Institutions of the Joint Punjab; and

(b) whether the accommodation in the said

Panchayat Bhawan is being provided to the rural population of Haryana and if not, from when the said building will be utilised for the purpose, it was constructed ?

विकास मन्त्री (सरदार तारा सिंह) :

(क) हां । पंचायत भवन, चण्डीगढ पंजाब तथा हरियाणा के ग्रामीण वासियों को सस्ती रिहायश की जगह उपलब्ध करवाने केलिये बनाया गया था । पंचायत भवन पर सरकार ने शीर्ष " 103-कैपिटल प्रोजैक्ट" के अधीन खर्च किया था । वह खर्च बाद में पंचायती राज संस्थाओं द्वारा पूरा किया जाना था ।

(ख) हरियाणा के ग्रामीण वासी पंचायत भवन चण्डीगढ में रियायती दर पर किराया देकर ठहर सकते है ।

Dacoities and Murders committed in the State

***232. Swami Aditya Vesh :** Will the Minister for Industries be pleased to state the total number of cases of Dacoities and Murders Committed in the State during the last 6 months and whether the government is considering to make a comprehensive scheme for the prevention of such heinous crimes thereof togetherwith the steps taken by the Government to check the increasing lawlessness in the State ?

उद्योग मन्त्री (डा 0 मंगल सैम) :

(अ) डकैती 12

हत्या

124

(ब) हां, राज्य के सभी जिला पुलिस अधीक्षकों को पर्याप्त निवारक कार्यवाही करने के लिए निदेश दिये जा चुके हैं ।

Improvement Trusts in the State

***264. Chaudhri Jagjit Singh Pohloo :** Will the Minister for Industries be pleased to state—

(a) the district-wise total number of Improvement Trusts in the State, seperately at present ;

(b) the names and addresses of each Chairman of the Improvement Trusts as referred to in part (a) ; and

(c) the number of Chairman of the improvement trusts out of those referred to in part (a) above belonging to Agriculturist Families ?

Industries Minister (Dr. Mangal Sain) :

A & B) A statement is laid on the table of the House.

c) Five

Statement showing the _districtwise total number of Improvement Trusts 16 In the State and the name and addresses of each Chairman of the the Improvement Trust.

Sr. No	District	Number of Name and address of the Imprevern Chairman ent Trusts District -
--------	----------	--

wise

- | | | |
|----------------------|---|--|
| 1. Gurgaon | 1 | (i) Sh. Mool Chand Meheshwari ,
advo-
cate, Civi Lines, Gurgaon. |
| 2. Sonapat | 1 | (i) Sit. Amar Nath Sharma,
Mohalla Rishi Nagar, Sonapat. |
| 3. Rohtak , | 2 | (i) Sh. Hukam Chand Goal.
Civil Lines Rohtak

(ii) Sh. Rao Jagmal Singh, Jhah
jar. |
| 4. Bhiwani | 2 | (i) Bhiwani. Chander Bhan,
Ex.M.L.A. Village Obera, Tahsil
Loharu, Distt. Bhiwani.

(ii) Sh. Sardar Singh, Charkhi
Dadri. |
| 5. Sirsa | 2 | (i) Sh. Mahabir Parshad
Ratusaria, Gali Bambaywali,
Sirsa.

(ii) Sh. Ram Dayal Vaid,
Ex.M.L.A Mandi Dabwall |
| 4.. Maherdargar
h | 1 | (1) Sh. satbir Singh s/o Rao
Jagrnl Singh Village
Qutabpur PO. Rewari, Distt.
Mahendergarh |

7. Hissar 3 (i) Sh. Parkash Chand Jain,
Bazar Vakilan Hissar.
- (ii) Sh. Harish Chander s,o
Sh. Chhabil Dass C/o M/S
Jamna Dass Chhabil Dass
Kali Devi Road, Hansi.
- (iii) Sh. Balbir Singh,
House No. 10,
Mohalla Lung, Fatehbad.
8. Karnal 2 (i) Sh. Chetan Dass, Jundla
Gate. Karnal.
- (ii) Sh. Inder Sain, House No.
94/3 Panipat.
9. Jind 1 (i)Sh. Radhey Shyam Tayal s/ o
Sh. Puran Mal Tayal C/o
Florance Surgical Cotton
Factory Bhiwani Road, Jind.
10. Ambala 3 (i) Sh. Gore lal Jain C/o
Adarsh Pushtak Bhandar, Ambala
City .
- (ii) Sh. Roshan Lal Dugal, Model
Colony, Yamunanager.
- (iii) Sh. Sat Parkash Goel S/o
Sh. Chander Bhan, Gandhi-

Dham, Jagadhri.

11. Kurukshetra 1 (i) Sh. Amar Nath C/o
Messers Amar

Nath Kailash Chander,
Commission

Agent, Kaithal Mandi.

**Managing Director of Central Co-operative Banks
in the State**

***351. Chaudhri Sant Kanwar :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) the approximate total amount incurred per year on the salary of Managing Directors of Central Cooperative Banks who are taken from the Government service, alongwith the other expenses spent in providing them other facilities like car, telephone and other staff allocated with them ; and

(b) whether there is any proposal under consideration of the Govt. to appoint non-officials as Managing Director in place of official one and if not, the reasons thereof ?

सिंचाई तथा बिजली मन्त्री (श्री वीरेन्द्र सिंह) :

(क) ग्यारह केन्द्रीय सहकारी बैंकों के प्रबन्धक निदेशकों का वार्षिक व्यय लगभग रुपये 1, 7 5, 000 वेतन, अवकाश वेतन, पेंशन योगदान के रूप में अदायगी की गई ।

दूरभाष की सुविधा कार्यालय व निवास स्थान के लिए दी गई है जिसका प्रति मास का व्यय 200 रुपये प्रति अधिकारी है । कार का प्रयोग प्रबन्धक निदेशक व अन्य बैंक अधि- कारियों सहित किया जाता है । प्रत्येक कार का प्रति मास का व्यय लगभग 1000 रुपये है ।

(ख) नहीं । क्योंकि सरकार की अत्याधिक राशि (जोकि दस लाख से अधिक है) राज्य के केन्द्रीय सहकारी बैंक में लगी हुई है तथा कानून अनुसार प्रबन्धक निदेशक की नियुक्ति सरकारी अधिकारियों में से करनी अनिवार्य है ।

अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Construction of Chaupals for Harijans and Wells for Jamadars

98. Swami Aditya Vesh : Will the Minister for Revenue be pleased to state—

(a) the names of the Assembly constituencies where the grants for construction of chopals for Harijans and wells for Jamadars were given during the period from July, 1977 to January, 1978 togetherwith the amount thereof given, each case and the extent to which the same was utilise ; and

(b) the district wise total number of chopals of Jamadars for which grants were given during the period as referred to in part (a) above ?

राजस्व मन्त्री (श्री प्रीत सिंह) :

(क) जुलाई, 1977 से जनवरी, 1978 तक की अवधि के दौरान हरिजनों के लिए चौपाले तथा जमादारों के लिए कुएं का निर्माण करने हेतु विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्रवार कोई राशि स्वीकृत नहीं की गई थी । वास्तव ' में, तथाकथित उद्देश्यों के लिए उपरोक्त समय के दौरान कोई भी अनुदान की राशि स्वीकृत नहीं की गई थी ।

(ख) उपरोक्त (क) के दृष्टिगत प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता ।

Deluxe and Air-Conditioned Buses

99. Swami kditya Vesh : Will the Chief Minister be pleased to state —

(a) the total number of Deluxe and Air-conditioned buses plying in the State together-with the total purchase price thereof;

(b) the names of districts in which the said buses are being plied ; and

(c) whether the government is considering to purchase more Deluxe and Air-conditioned buses; if so, the number thereof together-with the names of places where those are likely to be plied ?

मुख्य मन्त्री (चौधरी देवी लाल) :

(क) डीलैक्स 15 कुल मूल्य

वातानुकूलित 2 रुपये 2231234

(ख) (1) चण्डीगढ—देहली और वापसी

(2) देहली—शिमला और वापसी

(ग) दो और वातानुकूलित बसें निर्माणाधीन हैं और 15 मार्च, 1978 तक हरियाणा में बन कर पहुंचने की आशा है । कुछ और डीलैक्स बसें वर्ष 1978-7 9 में निर्माण करने की विचाराधीन है ।

जिन रुटों पर यह बसें चलाई जानी हैं, उन के बारे विचार किया जा रहा है ।

Engineering Training Institute

116. Swami Aditya Vesh : Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) whether the Govt. is considering to open new Engineering Training Institutes in the State ;

(b) if so, the names of places where the Govt. intends to open the said institutions; and

(c) if not, the steps which the Government proposed to take to satisfy the increasing interest amongst the youth of Haryana in the Technical Education togetherwith the time by which the said proposal will be implemented ?

सिंचाई तथा विजली मन्त्री (श्री वीरेन्द्र सिंह) :

(ए) नहीं ।

(बी) प्रश्न ही पैदा नहीं होता ।

(सी) इस समय हरियाणा राज्य में 6 सरकारी तथा 3 गैर सरकारी तकनीकी संस्थायें भिन्न-भिन्न तकनीकी कोर्सों के लिये प्रशिक्षण दे रही हैं । जिनमें 1290 छात्रों की प्रतिवर्ष क्षमता है । इसके अतिरिक्त एक क्षेत्रीय इन्जीनयरिंग कालेज भी है जिसमें 250 छात्रों की क्षमता है । इस से यह महसूस किया जाता है कि तकनीकी कोर्सों के लिये वर्तमान व्यवस्था डिप्लोमा लैवल पर हरियाणा राज्य के लिये पर्याप्त है ।

Moral Education

117. Swami Aditya Vesh : Will the Minister for Education be pleased to state—

(a) whether there is any scheme under consideration of the Government to impart moral education to the children in the State, if so, the nature thereof together with the time by which it will be implemented ; and

(b) if not, the steps being taken by the Government to check the immorality among the youth in the State together with the time by which those will be taken ?

Education Minister (Col. Rao Ram Singh) :

(a) No new scheme is under consideration.

(b) Emphasis is otherwise laid on the maintenance of high moral and ethical standards by the teachers as well as the taught.

Pass Books

155. Shri Surrinder Singh : Will the Minister for Revenue be pleased to state—

(a) the number of pass books prepared and sold to the land owners tenants upto 31st March, 1977 and

(b) the number of pass books sold from 1st April, 1977 to 31st January, 1978 ?

राजस्व मन्त्री (श्री प्रीत सिंह) :

	तैयारकी	बेची	बाई
	सई	पास	पास बुक
	बुके		
(क) 31 मार्च, 1977 तक तैयार की गई तथा जमीदारों/मुजारों को बेची गई पास बुको की संख्या	9,04,350	8,59,721	
(ख) 1-4-77 से 31- 1-78 तक बेची गई पास बुकों की संख्या	—	10,229	

University Grants Commission

92. Shri Surrinder Singh : Will the Minister for Education be pleased to state -

(a) whether it is a fact that the University Grants

Commission has not recognised the Maharshi Dayanand University, Rohtak, if so, the reasons thereto; and

(b) the steps taken by the Government to get the University recognised ?

शिक्षा मन्त्री (कर्नल राव राम सिंह) :

(ए) महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय वैध रूप से स्थापित है । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अभी इसे सहायतानुदान देना नहीं माना है । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इस विश्वविद्यालय को सहायतानुदान दिए जाने के राज्य सरकार के प्रस्ताव पर सक्रीयता से विचार कर रहा है ।

(बी) राज्य सरकार ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को कई बार प्रार्थना की है कि महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय को सहायतानुदान दिए जाने के लिए अनुमोदन प्रदान करें । विश्व विद्यालय अपना शैक्षणिक पाठ्यक्रम बढ़ाने के लिए जीव-विज्ञान के कुछ विभाग खोलने का दिवार रखता है । राज्य सरकार ने इसे एक अच्छा विश्वविद्यालय बनाने के किर काफी मात्रा में सहायतानुदान भी दिया है ।

Department of Sanskrit

93. Shri Surrinder Singh : Will the Minister for Education be pleased to state —

(a) whether it is a fact that the department of Sanskrit has been closed in the Maharshi Dayanand University

, Rohtak;

(b) if so, what are the reasons thereof; and

(c) whether it is a fact that staff recruitment had already been made for the M. Phil. classes ?

शिक्षा मैत्री (कर्नल राव राम सिंह :) :

(ए) नहीं । विश्वविद्यालय में संस्कृत विभाग कभी भी खोला ही नहीं गया था ।

(बी) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

(सी) हां । एक प्रोफ़ेसर तथा एक प्राध्यापक की नियुक्ति की गई थी परन्तु बाद में यह इसलिये रद्द कर दी गई, क्योंकि वे निर्धारित अवधि में कार्यभार ग्रहण करने में असफल रहे ।

Milk Plants in the State

123. Rao Dalip Singh : Will the Minister for Development and Panchayats be pleased to state -

(a) the district-wise number of Milk Plants in the state at present ;

(b) the plant-wise total cost involved in the construction and installation of milk-plants in the State ;

(c) whether the plants mentioned in part (a) above are running in profit ; if so, the plantwise profit during the years 1974-75, 1975-76, 1976-77 and 1977-78 ; and

(d) the average collection of milk in each Milk Plant in the years 1975-76, 1976-77 and 1977-78 to-date; and

(e) the average collection of milk in the Chilling Centre at Narnaul during the year 1976-77 and 1977-78 ?

विकास मन्त्री (सरदार तारा सिंह) :

(ए) तथा (बी) अपेक्षित सूचना सदन के पटल पर रखी जाती है ।

(सी) जी नहीं । केवल जीन्द में स्थित मिल्क प्लांट ने लाभ कमाया है और अपेक्षित सूचना सदन के पटल पर रखी जाती है ।

(डी) अपेक्षित सूचना सदन के पटल पर रखी जाती है ।

(ई) 5037 किलोग्राम (अगस्त 1977 से जनवरी, 1978 तक)

स्टेटमेंट

(ए) जिले का

नाम मिल्क प्लांटों की संख्या

जीन्द 1

भिवानी 1

रोहतक	1
अम्बाला	1
कुरुक्षेत्र	1 (निजि क्षेत्र में)

(बी) मिल्क

प्लांट रुपये लाखों में

जीन्द 128.95

भिवानी 73.72

रोहतक 229.00

अम्बाला 81.20

ज्ञात नहीं चूकि निजि क्षेत्र में
पेहवा (कुरुक्षेत्र) है ।

(सी) जीन्द स्थित मिल्क

प्लांट लाभ

वर्ष रुपये लाखों में

1974— 75	11.95
1975—76	1.18
1976—77	7.50
1977—78	उपलब्ध नहीं ।

नोट :- वर्ष 1975—76 तथा 1 976—77 के लिये उक्त आंकड़े प्रोविजनल हैं चूंकि इन वर्षों के लेखों के आडिट को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है ।

(डी) मिल्क प्लांट

वर्षवार दूध किलोग्रामों में

	1975—76	1976—77	1977— 78 (जनवरी 1978 तक)
जींद	25,612	20,032	16,132
भिवानी	11,370	7426	11,504
अम्बाला	10,869	6,640	7,669
रोहतक	-	15,129	10,734
पेहवा	ज्ञात नहीं चूंकि निजि क्षेत्र में		

(कुरुक्षेत्र)

है ।

Selection Grade to Teachers and Masters

124. Rao Dalip Singh : Will the Minister for Education be pleased to state —

(a) the district-wise total number of Teachers and Masters, separately who have been awarded Selection Grade after completion of eighteen years of service in the State to-date ;

(b) the district-wise total number of Teachers and Masters, separately who have not been awarded Selection Grade after completion of eighteen years of service in the State to-date ;

(c) the reasons for-not awarding Selection Grade to the Teachers and Masters mentioned in part (b) above; and

(d) the date and year when the last Selection Grade was released, to Lecturer and Masters in the State district-wise to-date ?

शिक्षा मन्त्री (कर्नल राव राम सिंह) :

(क) (ख) तथा (घ) विवरणिका सदन में प्रस्तुत है ।

(ग) राजकीय टीचरों के दो काडर हैं—एक स्टेट काडर तथा दूसरा प्रान्तीय— कृत काडर । स्टेट काडर में 15 प्रतिशत पदों पर सिलैक्शन ग्रेड दिया जाता है, जबकि प्रान्तीयकृत

काडर, जोकि घटने वाला काडर है, के अध्यापकों को 18 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण करने के पश्चात् सिलैक्शन ग्रेड दिया जाता है । सेवा नियमों के अनुसार, यदि किसी प्रान्तीयकृत काडर के टीचर को उसकी प्रार्थना पर किसी अन्य जिले में बदला जाता है तो वह उस जिले के स्टेट काडर पर आ जाता है, जिसमे उसकी वरिष्ठता सबसे नीचे रखी जाती है ।

254 अध्यापक, जिनका ब्यौरा विवरणी में है, प्रान्तीयकृत टीचरों के नियम लागू होने के बाद उनकी प्रार्थना पर एक जिले से दूसरे जिले में बदले गये थे । वे अब स्टेट काडर पर आ गये है और 18 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर भी सिलैक्शन ग्रेड लेने के पाल नहीं बनते है । 6 मास्टर्स/मिस्ट्रेसिज को सिलैक्शन ग्रेड देने के मामलों का निरीक्षण किया जा रहा है ।

जिलावार सिलैक्शन ग्रेड की विवरणिका

क्रमांक	जिला	18 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर सिलैक्शन ग्रेड मिलने वाले टीचरज/मास्टरज/मिस्ट्रेसिज की संख्या	18 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर टीचर्च/मास्टर्ज/मिस्ट्रूसिज जिन्हें सिलैक्शन ग्रेड नहीं दिया गया	वर्ष तथा तिथि जब मास्टर / मिस्ट्रेसिज को अन्तिम सिलैक्शन ग्रेड दिया गया

		टीचरज	मास्टरसज / मिस्ट्रे सिज	टीचरज	मास्टरसज / मिस्ट्रे सिज	
1	अम्बाला	154	32	40	-	10-12-75
2	भिवानी	241	13	2	--	30-12-77
3	गुडगांव	284	74	44	3	3-3-78
4	हिसार	489	41	-	-	29-12-76
5	जीन्द	34	15	10	1	27-1-76
6	करनाल	218	25	24	1	16-12-77
7	कुरुक्षेत्र	192	26	9	-	29-1-76
8	महेन्दगढ	195	29	1	--	29-1-76
9	रोहतक	633	63 -	32	-	23-9-77
10	सोनीपत		22	86	1	30-12-77
11	सिरसा	82	8	6	—	21-6-76
	कुल	2,522	348	254	6	

नोट :- स्कूल लैक्चररज के लिए कोई सिलैक्शन ग्रेड देने की व्यवस्था नहीं अत उन्हें सिलैक्शन ग्रेड देने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

Passenger Tax Through State Transport Authority

126. Lala Balwant Rai Tayal : Will the Minister for Finance be pleased to state—

(a) the district-wise total number of Bank drafts with their amount paid as Passengers Tax by the contract carriages through State Transport Authorities which were noted at the barriers from the copy of route permits presented by the contract carriages but not received in the District Excise & Taxation Officers' office from the State Transport Authorities during the financial years 1973-74, 1974-75, 1975-76, and 1977-78. to-date;

(b) the district-wise total number of Bank drafts and their amount in which the delay was made for more than five days, one month, two months, three months, four months, five months, six months, and above six months separately for their submission to the Bank for encashment during the above said years ;

(c) the district wise total number of Bank drafts and their amount as referred to in part (b) above in which the delay was made for more than ten days by the Bank to encash the drafts;

(d) the district-wise total number of Bank drafts and their amount their receiving date in the district offices and date on which these were sent for revalidation during the said financial years separately ;

(e) the district-wise total number of Bank drafts and their amount during the said financial years which were

used more than once by the Contract Carriages ;

(f) the district-wise total number of Bank drafts and their amount gone to loss to Government Revenue which were received by the District Excise & Taxation Officers' office from the State Transport Authorities during the said financial years but their amount did not tally with the amount which was noted at the barrier from the copy of route permits presented by the Contract Carriages ;

(g) the barrier wise number of cases of which the particulars were noted at the barrier from the copy of the route permits presented by the Contract Carriages during the said financial years but were not legible ;

(h) the district-wise barrier-wise, and period-wise record during the said period which was lost and the names of the officers/ officials responsible for the loss of such record ; and

(i) the names of the District Excise & Taxation Officers and Officers/ Officials posted in the Passengers Tax Branch of the District Excise & Taxation Officers' Office and names of the Assistant Excise & Taxation Officers/Taxation Inspector s posted at the barrier during the said period ?

***Interim Reply**

Subject: Unstarred Assembly Question No. 126 asked by Sh. Balwant Rai Tayal, M.L.A., regarding the Passenger Tax through State Transport Authorities.

Will the Secretary, Haryana Vidhan Sabha kindly refer to the subject cited above ?

2. The Unstarred Assembly Question No. 126 appearing in the list of unstarred question on the 9th March, 1978 in the name of Sh. Balwant Rai Tayal, M.L.A. is not ready.

The reply will be submitted as soon as the relevant information has been collected.

Sd/-

Minister-in

Charge.

Dated:

The Secretary,

Haryana Vidhan Sabha,

Chandigarh.

U.O. No. ET(VII-78/1303 Chandigarh, dated the 8th March, 1978.

Memorandum of Hissar Textile Mill

127. Lala Balwant Rai Tayal : Will the Minister for Finance be pleased to state whether any memorandum was given by the workers of the Hissar Textile Mill on 15-12-1977; if so, the action taken thereon ?

वित्त मन्त्री (चौधरी सतबीर सिंह मलिक) : प्रश्न से यह स्पष्ट नहीं होता कि यह प्रश्न कौन से प्रतिवेदन के बारे में दिया

गया है । इसमें यह भी नहीं लिखा कि यह प्रतिवेदन श्रमिकों के कौन से ग्रुप द्वारा दिया गया है तथा किस को दिया गया है ।

उचित उत्तर उपरोक्त सूचना के प्राप्त होने के पश्चात् ही दिया जा सकता है ।

**8 मार्च, 1978 को किए गए बहिर्गमन के सम्बन्ध में
अध्यक्ष द्वारा अवलोकन**

Shri Snrrinder Singh : On a point of Personal Explanation, Sir.

Mr. Speaker : Please wait.

Hon. Members, I want to make an observation.

Yesterday, the Members belonging to the Vishal Haryana Party and Congress (I) staged a walk-out from the House in protest against allocation of time to them for participating in the general discussion on the Budget. Uptil now the general discussion on the Budget lasted for four hours and thirty seven minutes. It will thus be seen that every Member is entitled to speak roughly for three minutes. The entire strength of the Opposition consists of 14 members and as such, according to the simple arithmetic method, they could be allotted only forty-two minutes in all. But , on the other hand, they have already spoken for one hour and forty six minutes.

These figures speak for themselves.

In view of this, the walk out was wholly unjustified.

(Interruptions) Incidentally, this precedent for allowing time as per strength of various parties was established a long time ago by Shri Bansi Lal. My intention was to help the Opposition to get more time during discussion. But, unfortunately, by their own acts of omission and commission they have lost this concession as the Treasury Benches are now demanding full share of their time.

वैयक्तिक स्पष्टीकरण—

श्री सुरेन्द्र सिंह द्वारा

श्री सुरेन्द्र सिंह (तोशाम) : स्पीकर साहबा इस सदन के स्तर पर कई बार पर्सनल एलीनेशन लाए जाते हैं और खास तौर पर चौधरी गंगा राम का प्रोफेशन हो गया है कि 'किसी भी मैम्बर पर छीटाकसी किए बगैर नहीं रह सकते (व्यवधान) । क्वेश्चन आवर ये स्पीकर साहब मुझ पर यह इल्जाम लगाया गया कि जब चौधरी गंगा राम मीसा में थे तो उस वक्त जींद में मास्टर्स ने पचास हजार की थैली मुझे भेंट की । मैं खुल्लमखुल्ला इस सदन में पूछना चाहता हूँ कि उनका सोर्स आफ इन्फरमेशन क्या था । वे मीसा में रहते हुए ऐसी बातें घडते रहते थे (व्यवधान) उस पब्लिक मीटिंग में कोई पैसा नहीं दिया गया । अगर उस यूनियन के आदमियों ने मझे पैसा देना बताया है तो मैं कहता हूँ ' कि मैंने कोई पैसा नहीं लिया और हो चकला है कि इस जनता पार्टी' के— कोई सदस्य वहां मौजूद हो । मैं प्रार्थना करूंगा कि

इस किस्म की गलत बयानी इस सदन में न करे और इसके अलावा—

श्री अध्यक्ष : बस काफी है (व्यवधान) ।

विशेषाधिकार प्रश्न

शिक्षा मन्त्री (कर्नल राव राम सिंह) : दो लाख के बारे में मेरे दोस्त का स्टेटमेंट है (व्यवधान) बावल की पब्लिक मीटिंग में मैं मौजूद था

श्री सुरेन्द्र सिंह : इनके बारे में मैं बता सकता हूँ (व्यवधान)

Col. Rao Ram Singh : Listen you have had your time.

श्री सुरेन्द्र सिंह : ये संजय के पास नाक रगड़ते थे I have seen you many times.

कर्नल राव राम सिंह : नाक तौ तुमने रगडा होगी तुम्हारे बाप ने रगड़ा होगी (व्यवधान) तूने रगडी तेरे बाप ने रगड़ा (व्यवधान.) ।

Mr. Speaker : I would request everyone to please take his seat.

Shri Surrinder Singh : He should be made to withdraw those words. (Interruptions).

श्री शमशेर सिंह : स्पीकर साहब, बाप का कोई मतलब नहीं है । ये शब्द वापिस लेने चाहिए ।

Shri Surrinder Singh : He should be made to withdraw these words (Interruption).

Mr. Speaker : If I am on my legs, every one should sit down

देखिए मि० सुरेन्द्र सिंह शरू में आपने गलत इस्तेमाल किया

Industries Minister (Dr. Mangal Sein) : Yes sir. He must withdraw first.

Mr. Speaker : Mr. Surinder Singh you must withdraw first. Then Col. Ram Singh will withdraw.

Shri Surinder Singh : Mr. Speaker.....

Mr. Speaker : Please finish the matter.

Shri Surinder Singh : I withdraw the words. But, at the same time, the situation remains that no personal allegations should be made. These have been made by very responsible Minister in the House.

Col. Rao Ram Singh : I wish to say कि इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि किसी पब्लिक मीटिंग में मेरे को पैसा नहीं दिया था । बावल वाली मीटिंग में मैं मौजूद था और कम से कम मेरा ख्याल है दो-तीन हजार लोग मौजूद थे । जब ये वादा.

(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह : हमारी मीटिंग में आप भी जाया करते थे..

कर्नल राव राम सिंह : तुम्हारी मीटिंग में तो जाना मनहूसों कारू -काम था । (व्यवधान) यह वादा किया गया था कि दो लाख रुपए की माला डलते ही एकदम बावल में चो जनता कालिज है उसको दे देंगे । जब वह पैसा दे दिया गया तो उसी वक्त रक्षा मन्त्री ने बुला कर कहा कि मैं यह पैसा यूथ कांग्रेस को देता हूँ । सुरेन्द्र सिंह उस पैसे को 'लेकर चले गए । यह मेरे सामने की बात है और अब यह कहते हैं कि इनको किसी पब्लिक मीटिंग में पैसा नहीं दिया गया ।

श्री सुरेन्द्र सिंह : मैं मन्त्री महोदय को चैलेन्ज देता हूँ कि अगर स्था मन्त्री चौधरी बसी लाल ने उस वक्त मुझे पैसा दिया हो तो मैं अस्तीफा दे दूंगा और अगर यह स्टेटमेंट गलत हो तो ये अस्तीफा देकर दुबारा चुनाव लड़े ।

कर्नल राव राम सिंह : मैं चौलेन्ज को अक्सैप्ट करता हूँ ।

Shri Surrinder Singh : Your Public Relations Department is there.

डा० मंगल सैन : स्पीकर साहब, मेरी सबमीशन है कि इस औगस्ट हाउस में रूलज के मुताबिक अपनी बात कहने की छूट

है । जब हम कोई बात कहते हैं तो स्पीकर साहब अपोजीशन के जो हमारे आनरेबल मैम्बर हैं, वे परेशान तो हैं ही क्योंकि उनके हाथ से राजसत्ता चली गई है और जनता ने उनको उखाड़ दिया है और इनके गिसडीङ्ज के बारे में कमिशन बैठे हुए हैं, उनको पर्सनल एक्सप्लेनेशन का अधिकार आपने दिया लेकिन उन्होंने अनावश्यक बातें कहना और लालपीला होना शुरू कर दिया । हाउस में इन्होंने चौलैन्ज किया, यह हिस्टरी में पहला ही मौका है । स्पीकर साहब, मेरी प्रोपोजल यह है कि तीन आदमियों की कमेटी बिठा दी जाए । अगर वे गलत होंगे तो वे अस्तीफा दे देंगे और अगर मेरे साथी गलत होंगे तो ये अस्तीफा दे देंगे ।

श्री सुरेन्द्र सिंह : स्पीकर साहब, मेरी वर्डिंग यह है कि चौधरी बंसी लाल ने अगर मुझे पैसा दिया हो । यूथ हांग्रेस को पैसा दिया था राह में मानता हूं। I still stand on my words, (Interruptions.)

डा० मंगल सैन : राह झूठ साबित हो गया यहां पर He should now withdraw, Sir. (Interruptions.) स्पीकर साहब, मेरी सबमीशन यह है.....

चौधरी राम लाल वधवा : स्पीकर साहब, आन ए प्यायंट आफ आर्डर, मेरी प्रार्थना है कि एक आनरेबल मैम्बर ने हाउस में पहले एक स्टेटमेंट देकर उस स्टेटमेंट को बदला एं और ऐसा करके हाउस को प्रिविलेज तोड़ी हूं । यह मामला प्रिविलेज कमेटी ब्हो जाना चाहिए । यह मेरी प्रार्थना है ।

डा० मंगल सैन : स्पीकर साहब, मेरी सबमीशन है कि जब सदन में एक बात कही गई और आनरेबल मैम्बर ने उसे रिफ्यूट किया और इस हद तक चले गए, उन्होंने कहा कि अगर उस समय के रक्षा मन्त्री को दो लाख रुपया जनता कालिज के लिए लोगों ने इकट्ठा करके दिया और बजाए उन्होंने जनता कालिज को देने के बूथ कांग्रेस को दे दिया दो लाख रुपया । उन्होंने कहा कि मैं चैलेन्ज कबूल करता हूं, मैं अस्तीफा देने के लिए तैयार हूं । स्पीकर साहब, मेरी प्रोपोजल है कि तीन आदमियों की कमेटी बना दी जाए, अगर ये रिगल आउट होना चाहते हैं, इनमें खुददारी है, इनमें कोई मोरेलिटी है तो ये अस्तीफा देकर अपने बापू के पास चले जाएं ।

श्री शमशेर सिंह : स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट है कि कर्नल राम सिंह ने अपने शब्द वापिस नहीं लिए हैं आपके हुक्म के बावजूद

श्री अध्यक्ष : वे विदड्रा कर रहे हैं, वे शब्द विदड्रा हो गए हैं (व्यवधान) ।

श्री शमशेर सिंह : इन्होंने विदड्रा नहीं किए ।

मुख्य मन्त्री(चौधरी देवी लाल) : स्पीकर साहब, यह लफज विदड्रा करने का सवाल नहीं है, दोनों तरफ से एलीगेशनज लगाये गये हैं और चैलेन्ज दिये गये हैं इसके लिये कोई कमेटी जरूर मुकर्रर होनी चाहिये । स्पीकर साहब, मुझे याद है कि मरहूम

सरदार प्रताप सिंह कैरों ने इसी हाउस में यह चैलेन्ज दिया था और ऋ चैलेन्ज कबूल किया गया था और उस वक्त बाकायदा कमिशन बैठाया गया था, इसलिये हमारी यह रिक्वेस्ट है कि इस हाउस की 3 मैम्बरों की एक कमेटी जरूर मुकर्रर होनी चाहिये ।

श्री सुरेन्द्र सिंह : स्पीकर साहब, जो वर्डज मिनिस्टर साहब ने कहे हैं वे आपके रिकार्ड पर हैं, टेप रिकार्डर मौजूद हैं, उनको अभी पढवा 'लिया जाए कि इन्होंने यह नहीं कहा कि **चौधरी बंसीलाल** ने सुरेन्द्र को बुलाकर वहीं स्टेज पर पैसा दिया था ।

कर्नल राव राम सिंह : स्पीकर साहब, यह तो रिकार्ड है कि मैंने कहा, यह तो रिकार्ड की बात है (विघ्न) कि रक्षा मन्त्री ने युवक नेता को बुलाकर पैसा दिया

Mr. Speaker : One at a time please. Kindly sit down. Col. Rao Ram Singh is speaking.

कर्नल राय राम सिंह : स्पीकर साहब, अभी बजाकर सुनाया जा सकता है कि बावल की मीटिंग में (जब के रक्षा मन्त्री ने) एक युवक नेता को पैसा दिया गया और उसके बाद मैंने यह कहा कि जनता कालेज केलिये 2 लाख रुपया जमा किया गया था जो उस वक्त के रक्षा मन्त्री ने मूव कांग्रेस के श्री सुरेन्द्र सिंह को वह पैसा दिया, इस स्टेटमेंट पर मैं वर्ड बाउंड हूं । I will move it. It was done in front of atleast three/four thousand people. (Interruptions)

Mr. Speaker : Let me say something please. I think, the matter is rather complicated. I refer it to the Privileges Committee.

श्री सुरेन्द्र सिंह : स्पीकर साहब, मैं औपसे दखास्त करूंगा कि वह संज कुछ आपके ' टेप रिकार्डर पर है (शोर)

श्री अध्यक्ष : वह तो प्रिविलेज कमेटी करेगी ।

चौधरी राम लाल वधवा : स्पीकर साहब, प्रिविलिज कमेटी को रेफर करने के बाद ये इसको चलेन्ज नहीं कर सकते ।

Mr. Speaker : The Finance Minister may kindly now make the statement.

वित्त मंत्री द्वारा वक्तव्य

सरकार की नई आबकारी नीति सम्बन्धी

वित्त मन्त्री (चौधरी सतबीर सिंह मलिक) : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि सदन को ज्ञात ही है कि सरकार ने सदन में यह आश्वासन दिया था कि जिन ग्राम पंचायतों 'द्वारा रेजुलेशन पारित करके अपने-अपने क्षेत्र में देसी शराब के ठेके बन्द करने की मांग की जाएगी, बन्द कर दिये जाएंगे । सरकार ने 2- 1 0 1977 से ग्राम चोटाला के 8 मील के घेरे तथा ग्राम तावडू के इर्द-गिर्द 144 ग्रामों' की पट्टी को नशाबन्दी क्षेत्र घोषित कर 'दिया हुआ है । राज्य में आगामी चार वर्षों के भीतर पूर्ण क्षेत्र

नशाबन्दी करने की मांग को ध्यान में रखते हुये यह कार्यवाही की गयी थी ।

2. वर्ष 1978- 79 की आबकारी नीति सरकार द्वारा उपरोक्त आश्वासनों को ध्यान में रखते हुये बनाई गयी है । शराब की बिक्री में हो रहे अनाचार को समाप्त करने के लिये भी सरकार द्वारा प्रयत्न किया गया है । अधिक मादकता वाली शराब की खपत को कम करने के लिये सरकार ने शुल्क तथा करों की माता को बढ़ाने का फैसला किया है तथा और भी पग उठाये हैं जिनका वर्णन मैं अब करना चाहूंगा ।

3. इस समय वर्ष में शुष्क दिनों की संख्या 1 5 हए । सरकार ने निर्णय किया है कि इन दिनों की संख्या बढ़ाकर 79 कर दी जाए । (तालियां) इनमें निम्नलिखित दिन शामिल होंगे

1. हर मास की प्रथम तथा सात तिथि
2. सभी शनिवार
3. गणतन्त्र दिवस 26 जनवरी,
4. महात्मा गांधी का शहीदी दिन 30 जनवरी
5. फरवरी मास का अन्तिम दिन
6. स्वतन्त्रता दिवस 15 अगस्त
7. महात्मा गांधी का जन्मदिवस 2 अक्तूबर

8. श्री जयप्रकाश नारायण का जन्म दिवस 11 अक्तूबर
9. हरियाणा दिवस प्रथम नवम्बर
10. बाल दिवस 14 नवम्बर
11. किसान दिवस 23 दिसम्बर

सरकार ने निर्णय लिया है कि शिक्षा केन्द्रों, पूजा स्थानों, जन साधारण के मनोरंजन स्थानों, हस्पतालों । लेबर कालोनियों, हरिजन बस्तियों, बस स्टैंड, बस स्टाप और गांव के कूओं से शराब की दुकानें 1 00 मीटर की दूरी पर रखी जाएंगी । इसी प्रकार शराब की दुकानों को राष्ट्रीय मांगों के 100 मीटर के भीतर, नगरपालिका सीमा या हरियाणा पर्यटन निगम द्वारा चलाई जा रही बार्ज को छोड़ कर, खोलने की इजाजत नहीं दी जायेगी ।

(इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए)

5. सरकार ने निर्णय लिया है कि वर्ष 197 7- 78 के शराब के कोटे को 20 प्रतिशत कम करके वर्ष 197 8- 79 के लिये कोटा निर्धारित किया जायेगा । देसी शराब के बड़े बड़े ठेकेदारों के एकाधिकार को समाप्त करने के लिये सरकार ने शराब की दुकानों को निलामी द्वारा देने की प्रथा को समाप्त करने का निर्णय लिया है । इस एकाधिकार के कारण राज्य भे देसी

शराब के वितरण प्रणाली पर काबू होने के कारण राज्य में अना-चार, समगलिंग तथा भ्रष्टाचार हो रहा था । 1- 4- 1978 से देसी शराब की दुकानों पर उसी प्रकार बिकेगी जिस प्रकार कि अब आई 0 एम0 एफ0 एस0 बिक रही है ।

8. जिन ग्राम पंचायतों द्वारा वैध रेजुलेशन पररित करके अपने क्षेत्र में से चल रही शराब की दुकाने बन्द करने की मांग की जाएगी वहां शराब की दुकानें नहीं खोली जाएगी, बशर्ते कि ऐसे क्षेत्रों में या ग्रामों में आबकारी से सम्बन्धित अधिक जुर्म न हों । यद्यपि कानून के अनुसार किसी प्रस्ताव को पारित करने के लिये पंचायत में 2-3 सदस्यों का बहुमत होना आवश्यक है तथापि सरकार ने यह निर्णय लिया है कि साधारण बहुमत से पारित किये गये प्रस्ताव भी इस मनोरथ के लिये जायज माने जाएंगे । आशा है कि 120 गांवों में जहां पर इस समय देसी शराब की दुकानें चला रही है, वहां दुकाने नहीं खुलेगी । जिन ग्रामों में इस समय देसी शराब की कोई दुकान नहीं चल रही है वहां ऐसी दुकानें नहीं खोली जाएंगी ।

7. देसी शराब की बिक्री के लिये ऐसे व्यक्तियों को लाइसेंस प्रदान किये जाएंगे जिनकी वित्तीय स्थिति अच्छी हो तथा उन्होंने आबकारी एक्ट तथा और किसी अन्य जुर्म के तहत सजा न पायी हो । देसी शराब के लिये ऐसे लाइसेन्स अगले दो या तीन सप्ताह में दिये जाएंगे ।

8. ऐसे लाईसैंसों की शहरी क्षेत्रों में लाइसेन्स फीस 2,0000 रुपये तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 1 5,000 रुपये वार्षिक होगी । इसके अतिरिक्त उन्हें, 15,000 रुपये की सिक्योरिटी भी देनी होगी । शराब के बाजार में बिकने से पहले सरकार द्वारा प्रति! प्रूफ लिटर 34 रुपये (1 7 रुपये आबकारी शुल्क तथा 17 रु0 असैस्ड फीस/मुल्क) चार्ज किया जायेगा । इस समय सरकार को देसी शराब की निलामी द्वारा बिक्री से प्रति प्रूफ लिटर 30 रुपये 7 8, पैसे का शुल्क मिलता है और अब यह बढ़कर 35 रुपये से 53 पैसे हो जायेगा ।

9. आई0एम0एफ0 लीकर के लाईसैंसों की वर्तमान लाईसैंस फीस जोकि 5,000 रुपये हए, को बढ़ाकर शहरी क्षेत्रों में जहां आबादी, 50,000 से कम है, 10,000 रुपये वार्षिक तथा जहां आबादी 50000 से अधिक है, 15000 रुपये वार्षिक की जा रही है । जैसा कि सदन को ज्ञात ही है कि सरकार ने आई0एम0एफ0एल0 पर बिक्री कर 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है । इस निर्णय को कार्यान्वित करने के लिये चालू अधिवेशन में एक विधेयक लगया जा रहा है ।

10. अधिक मादकता वाली शराब तथा 5 प्रतिशत से 6 प्रतिशत मादकता वाली बीयर, जोकि इस समय बाजार में बिक रही है, की खपत को अनुत्साहित करने के लिये— हरियाणा ब्रीवरीज को 3 प्रतिशत मादकता वाली बीयर बनाने के लिये कहा गया है । इसके फलस्वरूप धीरे—धीरे अधिक मादकता वाली बीयर का स्थान

कम मादकता काली बीयर ले लेगी । ग्रामीण क्षेत्र में शराब के लाईसैन्स धारकों को 2, 0 00 रुपये प्रतिवर्ष— निश्चित लाईसैन्स फीस की अतिरिक्त अदायगी पर बीयर बेचने की इजाजत भी अई? जाएगी ।

11 इसके साथ ही राज्य में नाजायज शराब की कशीदगी को रोकने के लिये भी सरकार उपयुक्त कदम उठाने की बहुत उत्सुक है

श्री मूल चन्द जैन : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर हैं कि मिनिस्टर साहब जो स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं, उस स्टेटमेंट की कापी हमारे पास टेबल पर तो आयी नहीं ।

चौधरी सतबीर सिंह मलिक : उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो सरकार की पालिसी की । हाउस के अन्दर अनाउसमेंट कर रहा हूँ

श्री मूल चन्द जैन : उपाध्यक्ष महोदय, कायदा के यह है कि जो स्टेटमेंट भई यहां पर पढ़ी जाए, वह टेबल आफ दी हाउस पर अवश्य आनी चाहिए ।

चौधरी सतबीर सिंह मलिक : मैम्बर साहिबान के पास भी पहुंच जाएगी । उपाध्यक्ष महोदय, प्रचालन सम्बंधी विम को खुदढ तथा स्मर्थ बनाया जायेगा तथा आबकारी नियमों को हृढता से लागू किया जायेगा । आबकारी अधिनिम के उपलब्ध की उलघना करने वालों को और कड़ा दण्ड देने के उद्देश्य से इस

अधिनियम में उपयुक्त सशोधन करने के लिये विधान सभा के आगामी सत्र में एक विधेयक लाया जायेगा ।

जो कोई खाना-यब शराबकसी या नाजायज शराब के बारे में सूचना देगा और कसूरवार लोगों को सूचना के आधार पर सजा होगी, ऐसे व्यक्तियों को सरकार की तरफ से इनाम दियर जावेगा ।

गैर सरकारी संकल्प सं० 1

गेहूँ, कपास, चावल, गन्ना क्या दालों के उत्पादन परिव्यय के प्रश्न पर विचार करने के धिर -सदर की एह उच्चाधिकार समिति नियुक्त करने सम्बन्धी

श्री शमशेर सिंह (नरवाना) : उपाध्यक्ष महोदय. मैं निम्नलिखित प्रस्ताव पेण करता हू यह राज्य सरकार से सिफारिश करता है कि वह गेहूँ, कपास, चावल, गन्ना तथा दालों के प्रति क्विटल उत्पादन परिव्यय के प्रश्न पर विचार करने के लिये इस सदन की एक उच्च प्राधिकार समिति नियुक्त करे जिसकी सहायता हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों जिनमें किसान शामिल होंगे द्वारा की जाए ।

वह राज्य सरकार से यह भी सिफारिश करता है कि वह उक्त समिति की सिफारिशों की रोशनी में उपर्युक्त प्रत्येक वस्तु की आधार-कीमत नियत करने के लिए केन्द्रीय सरकार से निचेदन करे

।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्रस्ताव जो है वह हरियाणा के सब से महत्वपूर्ण तबके के यानी किसान के बारे में है । किसान की प्रगति के लिये हरियाणा की— जनता सरकार बहुत लम्बे चौड़े वायदे करती है । मेरे इस प्रस्ताव में किसान की जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले बहुत से अहम सवाल हैं । उपाध्यक्ष महोदय, आज हरियाणा में जो खेती कि पेदावार की मुखतलिफ जिसे' हैं उनके भाव इस प्रकार मुकर्रर हुए हैं । गदम का भाव 110 रुपये प्रति क्विंटल, राइस कोर्स का भाव 78 रुपये प्रति क्विंटल, बासमन्त्री का 85 रुपये प्रति क्विंटल, अमरीकन कपास का भाव 265 रुपये प्रति क्विंटल और जो दाले है उनमें से सिर्फ चने का भाव 125 रुपये प्रति क्विंटल मुकर्रर किया गया है और बाकी दालों के भाव मुकर्रर नहीं किये गये हैं । इसके बाद शूगर—केन जो है वह साढे तेरह रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से हरियाणा के कोआप्रेटिव शूगर मिल हम से खरीदते है । उपाध्यक्ष महोदय, हरियाणा जनता पार्टी ने चुनाव के समय किसानों से बहुत लम्बे चौड़े वायदे किये कि अगर वह ताकत में आ गई तो गे हूं का भाव 150 रुपये के हिसाब से दिलाएगी उन्होंने किसानों से इस बात का भी वायदा किया कि चावल का भाव 100 रुपये और गन्ने का भाव 15 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से दिलाया जाएगा और कपास के बारे में 60 0— 700 रुपये क्विंटल के हिसाब से वायदा किया था । इसी' तरह से किसान की खेती. में पैदा होने वाली जो अलग अलग किस्म की जिसें हैं उनके भाव दिलाने के बारे में इन्होंने बड़े लम्बे चौड़े वायदे किये थें । इसके अलावा उपाध्यक्ष

महोदय, आज जो सरकार ताकत में है इसकी पार्टी के नेताओं ने चुनाव के पहले. बीच में तथा बाद में यह भी वायदा किया किं खेती खाडी में इस्तेमाल होने वाली जो बहुत -सी चीजे है जिसमे मशीनरी', खाद. डीजल और इनसैक्टिसाइडज और दूसरी बेशुमार किस्म की चीजे है वे भी किसानों को सस्ते भाव पर उपलब्ध करवाई जाएंगी । लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, निहायत ही दुख की- बात है कि सत्ता में आने के बाद आजकी सरकार उन सारी बातों को भूल गई है । जो 1 50 रुपये प्रति क्विंटल गदम का भाव दिलाने का वायदा था वह खोदा पहाड़ और निकला चूहा वाली बात हुई है । ये केवल पांच रुपये की बढ़ौतरी गदम के भाव में करवा सके और वह भी सिर्फ कागजों में उपाध्यक्ष महोदय, आपको भी इस बात का अच्छी' तरह से ज्ञान है कि हरियाणा की किसी भी मंडी में किसान को 108 या 107 रुपये से -ज्यादा उसकी गदम का भाव नहीं मिला है । चाहे सरकार ने गेहूं के ग्रेड का नाम लिया और चाहे और कोई बहाना लिया लेकिन मामला ज्यो का ज्यों ही रहा । कांग्रेस सरकार के राज में गेहूं का भाव 105 रुपये था ये उससे फालतू नहीं दिलवा सके । इसी तरह से उपाध्यक्ष महोदय, न सिर्फ गदम की ही बात है बल्कि गन्ने और कपास क जहां तक ताल्लुक है पिछले कई दिनों से इस हाउस में इस बात पर लंबी चोडी चर्चा हुई । जिस तरह से इन दो चीजों के भाव हरियाणा में और सारे देश में गिर रहे है उससे किसान को बहुत बड़ी हानि पहुंचने वाली है । गन्ने की आज यह हालत है कि जमुना नगर का सरस्वती मिल जब गन्ना पेलता था तो वहां

8 या साढ़े आठ रुपय से ज्यादा गन्ना नहीं खरीदा गया । मुझे कल ही किसी ने एक बात सुनाई कि दिल्ली में चौधरी चरण सिंह जी की कोठी पर यू 0पी 0 से बहुत से किसान गन्ने का सवाल लेकर आए । उन्होंने इस बात का नारा लगाया कि 'गन्ने का भाव पौने छरू और चौधरी चरण सिंह की जय' शह नारा उन किसानों की आर्थिक और माली स्थिति की भावना को व्यक्त करता है । हरियाणा के किसानों की भी चाहे वे रोहतक के हैं, सोनीपत के हैं, पानीपत के हैं या करनाल के हैं, बुरी हालत है और खास तौर से अम्बाला जिले की मिल की हालत बहुत खराब है । पिछले 20 दिनों से हजारों क्विंटल गन्ना या तो किसान के खेतों में छिला हुआ पड़ा है या मिल के बाहर पड़ा सूख रहा है

सिंचाई तथा बिजली मन्त्री (श्री वीरेन्द्र सिंह) : उपाध्यक्ष महोदय, क्या ये रैजोल्यूशन पर बोन रहे हैं, रैजोल्यूशन तो कमेटी की अप्वायटमेंट के बारे में है ।

श्री शमशेर सिंह : गन्ने की कीमत के बारे में अगर कोई कमेटी बनानी है तो गन्ने की कीमत क्या है अगर यह बात कही जाती है तो इससे ज्यादा रैलेवैसी क्या हो सकती है? इसी तरह से उपाध्यक्ष महोदय, कपास खासतौर से सिरसा! हिसार और फतेह—बाद के इलाकों में ज्यादा होती है । सभी किसानों को पता है कैसे बुरी तरह से कपास के भाव क्रैश हुए हैं । आज कपास के भाव 150 से 200 रुपये प्रति विद—टल है जिसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं है । किसान बेचारे पिस रहे हैं और यह

सरकार मूक आवाज. से गउओं की तरह देखती रही । कपास जिसके पर किसान को बहुत रुपया खर्च करना पड़ता है पहले उसे जमीन की तैयारी पर इतना खर्चा करना पड़ता है उसके बाद स्प्रे करने के लिये और दूसरी चीजो में बहुत रुपया खर्च करना पड़ता है । इसी तरह से. गन्ने की जो फसल है उसको किसान की धरती पूरे एक साल तक संभाल कर रखती है । इसके पर भी किसान को बहुत मेहनत करनी पड़ती है और बहुत मेहनत के बाद किसान को गन्ने की फसल मिलती है । जानता पार्टी की सरकार ने किसान को उसकी जिन्स का उचित भाव दिलवाने का वायदा किया था, लेकिन उचित भाव दिलवाने में बिल्कुल नाकामयाब रही है और इसकी वजह से किसान बेचौन हैं । खेतीबाड़ी की पैदावार बढ़ाने के लिए किसान को जिन चीजों की जरूरत है, जैसे फारेन मशीनरी की जरूरत पडती है, बाद की जरूरत पडती है, और कई दूसरी चीजे है, उन सब के ज्यादा भाव बढ़ गए है.....

श्री वीरेन्द्र सिंह : डिप्टी स्पीकर साहब, हाउस का टाईम वेस्ट हो रहा है, ये रैजोल्यूशन पर नहीं बोल रहे ।

वित्त मन्त्री (चौधरी सतवीर सिंह मलिक) : डारके दिल में किसान के लिए बड़ा दर्द हए. (व्यवधान)

चौधरी हरस्वरूप बूरा : डिप्टी स्पीकर साहब, रैजोल्यूशन दो बातों के लिए है । एक तो यह है 'कि सिलैक्ट कमेटी बनाई जाए और दूसरी यह कि स्पोर्ट प्राईस फिक्स करने के

लिए सैन्ट्रल गवर्नमेंट को सिफारिश की जाए । मेरे दोस्त इन दो बातों पर बोलें तो अच्छा है । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिए, मैं रैजोल्यूशन मूव कर देता हूँ ।

Shri Verendar Singh : It is not in the purview of this resolution.

श्री शमशेर सिंह : मुझे बोलने तो दीजिए । ट्रैक्टरों की कीमते पिछले दस सालों में बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं । अगर सरकार यह चाहती है कि किसान की आवाज बिलकूल न उठे, कोई उसकी आवाज न उठाए.....

चौधरी सतबीर सिंह मलिक : आज ये किसान के लिए आवाज उठाने वाले हो गए और जब 'किसान की नसबन्दी हुआ करती थी तब कहां थे, तब बिलकूल भी शरमाते नहीं थे.. (व्यवधान)

चौधरी संत कंवर : डिप्टी स्पीकर साहब, अगला रैजोल्यूशन बहुत जरूरी है, इस को जल्दी ही निपटा दें, टाईम वेस्ट हो रहा है ।

श्री शमशेर सिंह : डिप्टी स्पीकर साहब, अगर वजीरों को इस तरह से इन्टरफीयरेंस करने के लिए अलाउ करेंगे तो ठीक नहीं । मैं बता रहा था 'कि खेतीबाड़ी में इस्तेमाल होने वाली किस-किस चीज की कीमतें बढ़ी हैं, ताकि जो कमेटी बनेगी वह

अच्छी तरह से समझ सकें । पिछले पांच सालों में टैरक्टर की कीमत 10 हजार से बढ़कर आज 50-60 हजार रुपये हो गई है । खाद के एक थैले की कीमत 50 रुपये से 100 रुपये हो गई है । बिजली की दूर बढ़ी, पेट्रोल बढ़ा है.....

श्री वीरेन्द्र सिंह : इसकी कोई रैलेवेन्सी इस रैजोल्युशन के साथ नहीं है । (व्यवधान)

श्री शमशेर सिंह : किसानों को जो कर्जा दिया जाता है उसका व्याज 16 परसेंट तक पहुंच गया है । आबयाने का रेट, बिजली का रेट कई गुना हो गया है । किसान को अपनी आजीविका के लिए जिन चीजों की जरूरत पड़ती है, जैसे लकड़ी है, साबुन है, तेल है, इनकी कीमतें इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं जिसकी कोई हद नहीं । इन चीजों को ध्यान में रखते हुए किसान की जिन्स की कीमत मुर्कर करने के लिए, एग्रीकल्चर प्राईस कमीशन को जो भारत सरकार की एक एजेंसी है, उसको एप्रोच करें । यही एजेंसी कीमतें निर्धारित करती है । एग्रीकल्चर प्राईस कमीशन., इंडियन कौंसिल आफ एग्रीकल्चर रिसर्च और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, इनकी रिपोर्ट के आधार पर कीमत मुर्कर करते हैं । उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से हाउस के सामने यह बात कहना चाहूंगा कि इन एजेंसियों में किसान की आवाज, जो असल में खेती करने वाले हैं, कोई नहीं सुनता, इनकी कोई "से" नहीं होती । ये एजेंसियां किसान की समस्याओं से बिल्कुल अनभिज्ञ हैं, इनको किसान की कठिनाईयों का बिल्कुल ज्ञान— नहीं है ।

(व्यवधान) किसान की फसल को कोई इन्शोरेंस कवर नहीं करती । ओलों से, सर्दी से, बरसात से, किसी भी नैचुरल क्लेमिटी से बचने के लिए कोई इन्तजाम नहीं है । इसके मुकाबले में जो दूसरे व्यवसाय हैं, उन को इन्शोरेंस कवर करती है । उपाध्यक्ष महोदय., मैं यह भी कहना चाहूंगा ?? किसान का जो प्रोफैशन है वह हैंडीकैप्ड हैं और हैंडीकैप की कंडीशनक है जैसे खेतीबा डी की छोटी-छोटी चीजें खरीदने के लिए, एक-एक रुपये की चीज खरीदने के लिए दूर-दूर जाना पड़ता है । बीज. खाद और दूसरी. अन्य चीजें खरीदने के लिए चार पांच रुपये बस का किराया देना पड़ता है और सारी दिहाड़ी खराब हो जाती है- ।

श्री उपाध्यक्ष : आप रैजोल्युशन पर बोले ।

श्री शमशेर सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, किसान को जयने बच्चे पढ़ाने हों तो होस्टल में रखने पड़ते हैं, बीमारी का अगर इलाज करवाना हो तो दूसरी जगह जाना पड़ता है । कहने का मतलब यह है कि शहरों में जो दूसरे व्यवसाय हैं उनकी निस्वत किसान का व्यवसाय हैंडीकैप्ड है और ज्यादा खर्च करना पड़ता है ।

श्री वीरेन्द्र सिंह : रैजोल्युशन के मुताबिक कमेटी एप्वायंट करवाना चाहते हैं लेकिन ये पता नहीं किस सब्जैक्ट पर बोल रहे हैं । पूरी डायरी लिख कर लाए हैं और उसको प्रत्य क्रना चाहते हैं ।

श्री मूल चन्द जैन : प्वायंट आफ आर्डर सर । क्या मिनिस्टर साहब इस प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? अगर स्वीकार करते हैं फिर तो ठीक हैं, बनी इनको बोलने दे । किस लिए रुकावट डाल रहे हैं? (व्यवधान)

चौधरी संत कंवर : 15 मिनट बोलते हो चुके हैं, दूसरे मैम्बरों को बोलने का भी मौका दे । (व्यवधान)

श्री शमशेर सिंह : ये जो जनता पार्टी के एम 0एल 0ए 0 हैं, जिस तरह से वे इन्टरफीयरेंस करना चाहते हैं, उसका मेरी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला, मैंने अपनी बात कहनी है, इससे डिगने वाला नहीं हू । हमारे पर इन बातों का कोई असर पड़ने वाला नहीं है (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि किसान की बड़ी हैडीकैप्ड कंडीशन्ज हैं । किसान जो पेदा करता है, आज— तक किसी एजेसी ने उसका तखमीना नहीं लगाया । किसी एजेसी ने उसके हक में आवाज नहीं उठाई । किसान का सारा परिवार, किसान की बह—बेटिया सर्दी में, गर्मी में, नैचुरल कलेमिटीज में जमीन का काम करती हैं । इनकी मजदूरी, इनकी सुपरविजन के बारे में किसी ने आवाज नहीं उठाई, किसी एजेसी ने कसीडर नहीं किया । जैसा कि मैंने अभी बताया कि किसान द्वारा इस्तेमाल करने वाली चीजों के भाव पिछले पांच—सात सालों में सौ गुना से पांच सौ गुना तक बढ़े हैं । लेकिन किसान की अपनी पैदावार के भाव इन्क्रीज नहीं हुए । किसी एजेसी, किसी यूनि—वर्सिटी ने इन बातों की तरफ ध्यान नहीं दिया । मैं सदन

को उदाहरण देकर बताता हूँ कि खेतीबाड़ी व्यवसाय के अतिरिक्त 'जितने अन्य व्यवसाय हैं, जैसे दुकानदार हैं, ये जिन चीजों को बेचते हैं इन में बहुत सी सड़ जाती हैं, खराब हो जाती हैं, कई बिकती नहीं हैं । ये इन सब चीजों को ध्यान में रख कर ओवर-आल मार्जन रख कर चीजों की कीमत निर्धारित करते हैं और इकनोमिक्स निकालते हैं । लेकिन किसान के मामले में, खेती बाड़ी के मामले में, इनकी जिन्स के मामले में कोई इकनोमिक्स नहीं है, कोई 'हिसाब किताब नहीं है और इसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि पिछले दस साल में हरियाणा के किसान का बाल बाल कर्ज के अन्दर बंधा हुआ है । आज कोई किसान ऐसा नहीं है जिसकी जमीन लैंड मॉर्गेज बैंक के पास या कोआप्रेटिव बैंक के पास रहन न हो । आज टैरक्टर के लिए, ट्यूबवैल के लिए, बीज के लिए और हर दूसरी चीज के लिए किसान को कर्ज लेना पड़ता है । तो उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सदन के सामने मैं यह बात रखना चाहता हूँ कि किसान की जिन्स की जो कीमत है अगर वह पूरी होती तो ग्रीन रैवोल्यूशन की जो इतने सालों से शोर मचा हुआ है इसके बावजूद किसान का बाल बाल कर्जा में बंधे होने की जरूरत नहीं थी । आज, जैसा मैंने पहले कहा, किसी किसान के पास टैरक्टर खरीदने के लिए पूंजी नहीं है, ट्यूबवैल लगाने के लिए और जमीन की दूसरी प्रोग्रेसिव इम्प्रूजमेंट्स करने के लिए उसके पास पूंजी नहीं है । यह इस बात का सबूत है कि 'किसान को जिन्स का पूरा भाव नहीं मिल रहा है । दूसरी ओर आप देखें किसान की लिविंग कंडीशन में

कोई फर्क नहीं आया है । सारे हरियाणा में आज किसी भी किसान के घर में बाथ रूम नहीं है, गुसलखाना नहीं है, लैट्रीन नहीं है या कोई दूसरी चीज नहीं है जिसमें बीमार माता या बूढ़ा बाप दिन या रात के वक्त अपने आप को ईज कर सके । उनके रहन सहन का तरीका, उनके कपड़े, बिस्तर और किचन आदि में आप भी । डिप्टी स्पीकर साहब, अच्छी तरह से जानते हैं क्योंकि आप भी किसान हैं, पिछले 20-30 साल से कोई तबदीली नहीं आई है । इससे सिद्ध होता है कि किसान का व्यवसाय घाटे का व्यवसाय है । इसमें कोई फायदा नहीं है । इसलिए इस प्रस्ताव के द्वारा, उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकारी बजिज पर बैठे हुए साथियों और मिनिस्टर साहिबान से दरख्वास्त करता हूं कि इन बातों को देखते हुए यह जरूरी है कि इस हाउस के मैम्बरों की एक कमेटी बनाई जाए जो किसानों को, ऐक्सपर्ट्स को एसोशिएट करके इन सारी बातों का ध्यान रखते हुए यह निर्धारित करे कि प्रति क्विटल फलां फलां जिन्स पर किसान का कितना खर्च होता है । उपाध्यक्ष महोदय, इसका यह फायदा होगा कि हरियाणा के किसान को, किसानों के नुमायदों को, चाहे वे असैम्बली में हैं या पार्लियामैन्ट में है, आवाज उठाने के लिए एक ठोस, साइंटिफिक आधार मिलेगा । वे कह सकेंगे सरकार को, जनता पार्टी की थोथे वायदे करने वाली बहरी सरकार को, जो यह झूठे वायदे करती थी कि किसान को 1 50 रुपये का भाव दिलाएंगे, कि किसान को एक क्विटल जिन्स पैदा करने के लिए इतना रुपया खर्च करना पड़ता है । इन

शब्दों के साथ मैं हाउस से रिक्वैस्ट करूंगा कि यह इस प्रस्ताव को अवश्य स्वीकार करे ।

Mr. Deputy Speaker : Motion moved—

This House recommends to the State Government to appoint a high powered Committee of this House assisted by experts from Haryana Agricultural University including farmers to go into the question of cost of production of per quintal of Wheat, Cotton, Rice Sugar-cane and Pulses.

This House further recommends to the State Government to approach the Central Government to fix the support price of each of the above-said commodities in the light of the recommendations of the said Committee.

चौधरी हरस्वरूप बूरा (मेहम) : उपाध्यक्ष महोदय, हाउस के सामने जो प्रस्ताव है, मैं उसका हृदय से स्वागत करता हूँ और अपने फाजिल दोस्त चौधरी शमशेर सिंह जी का, जो यह रैजोल्यूशन लाए हैं, धन्यवाद भी करता हूँ । उपाध्यक्ष महोदय, इसरैजोल्यूशन के अन्दर दो बातें कही गई हैं । एक बात तो हाई पावर्ड कमेटी के संगठन की है और दूसरी बात यह है कि हमारी सरकार केन्द्रीय सरकार से इन चीजों की स्पोर्ट प्राईस दिलाने के लिए प्रार्थना करे । मैं अपनी सरकार से यह दरखास्त करूंगा कि कमेटी नियुक्त करने के बारे में तो वह जैसा उचित समझे वैसा करे, मैं इस बात को ज्यादा स्पोर्ट नहीं करूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि किसानों के लिए, जो 30 साल से पिसते आ रहे हैं, उचित भाव दिलाने के लिए, स्पोर्ट प्राईस दिलाने के लिए यह

जरूर प्रयत्न करे । (विघ्न) उपाध्यक्ष महोदय, गरीब किसान 30 साल से गरीबी और पिछड़ेपन से संघर्ष करते आ रहे हैं । सही मायनों में अगर हमें उसे स्वतन्त्र करना है, उसे अपने पांव पर खड़ा करना है, तो इस रैजोल्यूशन के पीछे जो भावना है स्पोर्ट प्राईस दिलाने की, उस हद तक सरकार को अवश्य मानना चाहिए क्योंकि यह निहायत जरूरी है । गरीबी से दबा हुआ तबका तभी पर उठाया जा सकता है जब उसे उसकी पैदावार का उचित भाव मिले । मैं अपनी सरकार से यह अर्ज करूंगा कि भाव जो हैं वे एक साल पहले मुकर्रर होने चाहिए ता कि किसान को पता हो कि मेरी फसल का भाव कितना है और उसके मुताबिक वह अपनी फसल की बिजाई कर सके । आज जो भी खेती बाड़ी के अन्दर चीजे इस्तेमाल होती हैं, जैसे बीज, खाद, बिजली, टैरक्टर आदि उनकी कीमतें बहुत मंहगी हैं लेकिन किसान की जो फसलें हैं, जिनका खास तौर पर रैजोल्यूशन में जिक्र किया गया है, वे बहुत सस्ती हैं ।

इसलिए इन समस्याओं को दूर करने के लिए यह जरूरी है कि स्पोर्ट प्राईस, हक उचित प्राईस, किसानों को दिलाई जाए । मैं उपाध्यक्ष महोदय, यह बात भी यहां पर जरूर कहूंगा कि जहां उचित भाव दिलाने के लिए किसानों का ध्यान रखा जाए वहां कंजयूमर भी अवश्य ख्याल रखा जाए । उपाध्यक्ष महोदय, यह बात भी मैं जरूर कहूंगा कि किसान की फसल के पर जो लागत आती है उसको देखते हुए उसको इतनी प्राईस मिलनी चाहिए कि

वह अपनी लागत भी पूरी कर सके और उसे निर्वाह करने के लिए म्उनाफा भी मिल सके क्योंकि इसके बगैर वही बात हो जाती है जैसे एक शेर है—

तंगदस्ती भी बुरी कसरते दौलत भी बुरी,

दोनों हालात में इस्मान बदल जाता है ।

उपाध्यक्ष महोदय, किसानों की स्थिति इतनी डांवाडोल हो चुकी है कि इसको ठीक करने के लिए मैं अपनी सरकार से यह प्रार्थना करूंगा कि जिस हद तक मैंने शुरू में अर्ज किया है उस हद तक इस प्रस्ताव को जरूर मंजूर करें । आज मेरे किसान की हालत क्या हो रही है, भावों के प्रति, इसे मैं एक शेर के द्वारा दर्शाना चाहता हूँ—

नित मर मर कं जी रहा हूँ

जिगर की आग पी रहा हूँ,

मुझे तो भाव की शिकायत है,

दवा सपनों की री रहा हूँ ।

उपाध्यक्ष महोदय, किसान सपनों के अन्दर देखता है कि मेरे भाव बढ़ेंगे । इसलिए मैं आनी सरकार से पुरजोर अर्ज करना चाहता हूँ कि यह जरूर सैटर से सिफारिश क ताकि उसे ज्यादा से ज्यादा स्पोर्ट प्राईस मिल सके ।

राव राम नारायण (साल्हावास) : डिप्टी स्पीकर साहब, चौधरी शमशेर सिंह जी ने जो रैजोल्यूशन पेश किया है, मैं इसका तदिहेल से समर्थन करता हूं और इनको मुबारिक-बाद देता हूं । इस रैजोल्यूशन की बहुत ही सख्त जरूरत थी लेकिन इसमें इतनी और ऐडीशन होनी चाहिए कि जो हाई पावर्ड कमेटी स्पोर्ट प्राईस वर्क आउट करे उस पर थोड़ा सा नफा लगा करके ग्रोअर्ज को वह कीमत मिलनी चाहिए । अगर किसी वजह से मार्किट में कीमत गिर जाती. हैं तो गवर्नमेंट अरेंजमेंट करे उस जिन्स को उस स्पोर्ट प्राईस पर खरीदने का ताकि ग्रोअर्ज को कोई नुकसान न हो ।

चौधरी रिजक राम (राई) : डिप्टी स्पीकर साफ, आज जो प्रस्ताव चौधरी शमशेर सिंह जी ने सदन के सामने रखा है उस पर हरेक सदस्य. को पूरा ध्यान देने की आवश्यकता हैं । चौधरी. शमशेर सिंह जी ने प्रस्ताव पेश करते हुए कुछ नुक्ताचीनी की आज की सरकार की नीतियों की । यह भी उन्होंने फरमाया कि सरकार ने चुनाव के वक्त ज्यादा कीमतें दिलाने के वायदे किये थे, उनको सरकार पूरे नहीं कर सकीं । उन्होंने फरमाया कि किसानों की हालत बुरी है, उन्हे उनकी जिन्स की कीमतें पूरी नहीं मिल रही हैं । मैं उनकी बहुत सी बातों पर इतफाक करते हुए दो-तीन बातें आपकी इजाजत से हाउस में रखना चाहता हूं । जब से देश आजाद हुआ, दुर्भाग्य से देश की सत्ता उन लोगों के हाथों में रही जो वैस्ट्रेनाइज्ड थे । मेरा कहने का मतलब इतना पोलिटिशियन से नहीं जितना सर्विसीज मे बैठे हुए लोगों से है ।

सर्विंसीज में बैठे हुए लोगों में किसानों की और देहात के लोगों की नुमाइन्दगीं बहुत कम' है । डिप्टी स्पीकर साहब कई लोग योजना भवन या एग्रीकलचर कमीशन के दफतर में बैठ कर खेती के बारे में या कारखानेदारों के बारे अपनी नीति निर्धारित करते रहे हैं ।

मैंने इस बारे में विचार करने की कोशिश की है और मुताएला भी किया । एग्रीकलचर प्राइस कमीशन के चेयरमैन धर्म-नारायण जी काफी अर्से से चले आ रहे हैं । डिटी स्पीकर साहब आपने भी 'किताबें पढी होंगी और मैंने भी पढी हैं । उन किताबों को पढने से पता लगता है कि एग्रीकलचर प्राइस कमीशन में जमींदारों की, किसानों की जिन्स की कीमत मुकर्रर करने वाले कैसे लोग हैं, उनके क्या विचार हैं? ए 0 एन0 खुशसे ने अपनी किताब "डिवैल्पमेंट आफ एग्रीकलचर" में एक आर्टीकल लिखा था । उसमें उन्होंने लिखा था कि देश आजाद होने के बाद जो कीमतें बढ़ रही हैं उनसे अगर देश को कोई खतरा है तो देहात की अनाज की पैदावार की कीमत बढ़ने से है । अगर इस पर रोक-थाम नहीं की गई तो इसके नतायाज बहुत हानिकारक हो सकते हैं । यह उन्होंने लिखा है । आगे उन्होंने सुझाव दिये हैं. कि देश की आर्थिक व्यवस्था को ठीक हालत में रखने के लिये यह आवश्यक है कि किसा नो की जिन्स की कीमतें कम से कम रखें । उन्होंने लिखा है कि जहां तक हो सके वे कीमतें मार्किट प्राइस से, प्रिवेलिंग प्राइस से कम रखी जायें । इतना ही नहीं

बल्कि उन्होंने कहा है कि जिन्स की कीमतें कम देने के अलावा किसानों पर टैक्स इतने लगाए जाएं कि उनसे ज्यादा से ज्यादा रुपया मिल सके । अगर उनके पास कुछ और रुपया बचे तो स्माल सेविंग के जरिए या और दूसरे तरीकों से उन लोगों से रुपया लिया जाए वरना देश की अर्थ-व्यवस्था को बड़ा खतरा हो सकता है । उन्होंने यह बात लिखी है । **चौधरी** शमशेर सिंह जी जो फरमा रहे हैं, उनके जजबात ठीक हैं । हम यहां देखते रहे हैं और मैं आपको भी बताना चाहता हूं कि जो नीति बनाने वाले हैं चाहे वे योजना भवन में बैठे हैं या कहीं और बैठे हैं उन सब की यही कोशिश रही है कि किसानों की जिन्स की कम से कम कीमत दी जाए और उन पर ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगाए जाएं । उसके पास किसी भी हालत में पैसा इकट्ठा न हो । मैंने उस सरकार में रह कर देखा है कि जो भी पालिसी वहां के चेयरमैन ने रखी है उसी पालिसीको कांग्रेस पार्टी बरतती रही है । कांग्रेस उस पालिसी पर चलती रही है कि किसानों की जिन्स की कीमत कम से कम रहे । **चौधरी** शमशेर सिंह जी ने गन्ने और दूसरी प्रोडक्शन के बारे में फरमाया । डिप्टी स्पीकर साहब इस हाउसका कोई भी सदस्य इस बात को भूला नहीं है कि तीस साल तक फूड जोन बना कर चाहे वह चावल था, चाहे कोर्स येन था, चाहे गेहूं था सब को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने पर पाबन्दी लगी । यह सब इस गर्ज से किया गया कि किसान की जिन्स की कीमतें कम हो जायें । फूड जोन बनाये ताकि कीमतें कम से कम मिले । हरियाणा भी सरप्लस स्टेट है हरियाणा से पैड़ी, वीहट, कोर्स ग्रेन

दूसरी स्टेट को नहीं जाने दिया । नतीजा यह हुआ कि हरियाणा में जिन्स की कीमतें गिरीं । फूड जोन बनाने का मकसद यही था कि यहां कीमतें गिरे । आपने यह भी देखा होगा कि जब से सरकार ने कीमतें मुकर्रर करनी शुरू की उसी साल से जो प्रिवेलिग मार्किट प्राइस थी उसने बहुत कम कीमत मुकर्रर की है । 'डिप्टी स्पीकर साहब मैं आपका ज्यादा समय न लेते हुए आपके सामने थोड़ी सी फीगर रखना चाहता हूं । सन् 1965-66 में पैडी की कीमत 36 से 45 रुपये मुकर्रर की गई जब कि मार्किट प्रिवेलिंग प्राइस 43 से 86 रुपये तक थी । सन 1960-67 में 39 से 45 रुपये तक कीमतें मुकर्रर की लेकिन मार्किट प्राइस उस वक्त 56 से 101 रुपये थी । सन् 1967-68 में 45 और 56 के दरमियान मुकर्रर की जब कि मार्किट में कीमते 65 और 134 रुपये थी । इसी तरह से चावल की कीमतें 1965-68 में 66 से 76 रुपये तक सरकार ने मुकर्रर की थी लेकिन प्रिवॉलंग मार्किट प्राइस 181 रुपये थी । सन् 1966-67 में 64 से 76 रुपये रखी जब कि मार्किट प्राइस 218 रुपये थी । सन् 1967-68 में 72 से 99 रुपये तक फिक्स की जबकि मार्किट में भाव 162 रुपये था गेहूं की जो कीमतें सरकार ने मुकर्रर कीं वे मार्किट प्राइस से कम मुकर्रर की । सरकार ने फूड जोन्स ही नहीं बनाए बल्कि फूड येन की सिक्योरिटी वो कर्जे देने भी बन्द कर दिए, स्पैकुलेशन बना दी । मिल वालों को हिदायतें कीं कि ओपन मार्किट से नहीं खरीद सकेंगे । उन सभी जोन्स में कीमतें नीची रहीं । डिप्टी स्पीकर साहब यह कहने के । तो कह सकते हैं कि जनता पार्टी ने यह

नहीं किया वह नहीं किया । क्या वे इस बात को भूल गए कि फूड जोन्स की वजह से एक— एक किसान को कितने का खसारा रहा और जिसकी वजह से कितने ही किसान आये साल गिरपतार हुए और उनके चालान हुए । सारी जिन्हें उनकी जबत होती थी । अभी पोहलू साहब कह रहे थे कि जमींदारों के घर—घर जाकर छापे मारे । जमींदारों के घरों से पुलिस अनाज निकालती थी । ये लोग इस बात को भूल गए हैं । कांग्रेस की सरकार ने जो तीस साल तक किसानों के साथ जुल्म किया, अन्याय किया वह जनता पार्टी की सरकार ने सता में आते ही खत्म किया । फूड जोन्स की वजह से किसानों की जिन्स की कीमतें गिरीं थी उसको खत्म किया । (श्री पोहलू की ओर से विधन) आप तो नौ मरीने वजीर बने रहे, मैंने बनाया था । अब चाहे कितनी ही खुशामदे कर लें, अब मिनिस्टर नहीं बन सकता । मुझे भी इतनी जल्दी भूल गया । जब भी मैं बोलता हूं तो यह जरूर इन्ट्रप्शन करता है, बीच में टोकता है ।

डिप्टी स्पीकर साहब कमीशन ने जो भाव मुकर्रर किये उनके बारे में कहना चाहता हूं । क्रास के बारे में खास तौर पर कहना चाहता हूं । हमारे हरियाणा प्रांत के हिसार, सिरसा और जीन्द के इलाके में काफी मात्रा में कपास पैदा होती है । कहा नरमा । अमरीकन, मीडियम स्टैपल भी होती है । लेकिन अभी दो—तीन दिन हुए चौधरी वीरेन्द्र सिंह : ने एक स्टेटमेंट पढ़ी थी और उसको हाउस की टेबल पर रखा था । उन्होंने फरमाया था

कि किस तरह से हम कोशिश कर रहे हैं कि कपास की कीमत, जो सप ओर्ट प्राइस सरकार ने मुकर्रर की है वह बढ़ाई जाये । पोहलू साहब को बाद होगा कि सरकार ने जिस वक्त कीमतें मुकर्रर की तो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर और पं जाव के चीप, मिनिस्टर हवाई जहाज से दिल्ली गये और सैन्टर की सरकार के सा मने पूरी' ता क्त लगाई और उनको समझाया कि आपने जो कीमतें मुकर्रर की है वह कम है । उन्होंने कहा कि ये कपास की कीमतें जो घटायी हैं, ये कारखानेदारों की वजह से घटा ई है । जो किसान को कीमतें कम मिंत्री हैं उसमें एक तरफ तो कारखानेदार हैं और दूसरी' तरफ सरकार में बैठे हुए लोग हैं, दफतरों में बैठे हुए लोग हैं । वे कपास की कीमत का तखमीना गलत देते हैं ताकि सरकार को बाहर से कपास मंगाने क बहाना मिल जाये । हर दफा इजिप्ट, ईरान और दूसतए मल्लों से कपास मंगाते हैं, इम्पोर्ट क्रने है । वहां पर वे 600 रुपये और – 700 रुपय क्विटल के भाव से चेते हैं । हमारे हरियाणा और देश की जो कपास है उसकी जायज कीमत नहीं मिलती है, उसको देने में सरकार गुरेज' करती है । आपने देखा होगा कि काटन कारपोरेशन आफ इडिया के जो भी कार्यकर्ता हैं वे जान-बूझ कर कारखानेदारों से मिल कर किसानों के साथ हेरा-फेरी करते है । जिस वक्त कपास का सीजन होता है, जब कपास मार्किट में आती है तो उस वक्त सी0 सी0 आई0 खरीदने के लिए नहीं अ-। ती. कुछ अर्से बाद जब पीक सीजन होता है तो कपास की कीमतें गिर जाती है और कीर-तें गिरने के बाद सी0 सी0आई0 आती है ।

अन्दाजा यह है कि हजार बेल से ज्यादा जो कपास देश में किसान पैदा करता है, लेकिन सी० सी० आई० को रिजर्व बैंक आफ इंडिया और गवर्नमेंट आफ इंडिया दोनों 19 करोड़, 20 करोड़ या 25 करोड़ से ज्यादा पैसा कपास की खरीद के लिये नहीं देती। इसका नतीजा यह है ?? वह 15 प्रतिशत, 20 प्रतिशत कपास हैं। खरीद पाते हैं और बाकी—की— जो कपास है वह टेरडर्ज या मिल ओनर्ज सस्ते दाम पर खरीदते हैं। उस हालत में भी जबकि देश में काफी पैदावार होती है, जानबूझ कर बाहर से कपास मंगायी जाती है ताकि कपास का भाव मन्दा रहे और मिल—ओनर्ज को सस्ते दाम पर कपास मिलती रहे। यह आज की बात नहीं। यह पालिसी केन्द्रीय सरकार की 30 साल से रही है। यह पालिसी 30 साल से केन्द्रीय सरकार बरतती रही है। जिसकी वजह से पंजाब के किसान और हरियाणा के किसान बिल्कुल तबाह हो चुके हैं। यही नहीं, डिप्टी स्पीकर साहब, मैं एक बात और कह कर खत्म करना चाहता हूँ। आप — देखिये, बुराई करने के तो कुछ भी कर दें, नुक्ताचीनी करने के लिये तो कोई कुछ भी कह दे लेकिन पोहलू साहब को याद होगा और पता होगा 'कि एफ० सी० आई० हरियाणा से बासमन्त्री चावल दो रुपये किलो पर खरीदतीं रही 1973—74 में और 1974—75 में दो रुपये किलो के भाव पर खरीदते'। रही है और हरियाणा की—सरकार ने वह चावल एफ० सी० आई० को 4 रुपये प्रति किलो के भाव से वेला, दो रुपये किलो का मुनाफा हरियाणा सरकार ने लिया फिर वही बासमन्त्री चावल 11 रुपये किलो के भाव तक मुस्लिम

कन्ट्रीज को बेचा गया । किसान को दो रुपये के दाम. दिये, सरकार ने उस पर दो रुपये किलो का मुनाफा कमाया और एफ0 सी. 0 आई 0 ने उसको बेचकर 7- 8 रुपये किलो का मुनाफा उठाया फिर आप कहते हैं कि जनता सरकार ने अपने वायदे पूरे नहीं किये ।

मुड का भाव गिर-गया, फलाना हो गया, वैसे तो अगर आप को सारी कार-करदगी जिस तरह सेरू अफसरान, दिल्ली की सरकार, -पिछली' कांग्रेस सरकार करती रही है, पता लग जायेगी तो मुझे यह विश्वास है कि. चौ-बरी' शमशेर सिंह जी कांग्रेस (आई) में तो रहेगे नहीं । (हंसी) कांग्रेस आई मे यह नही रहेंगे । यही नहीं, इस तरू से एफ 0 सी 0 आई 0 मुनाफा खाती रही है । मैं आपको यह वसूक के साथ कहता हूं कि हरियाणा की सरकार ने फरबरी, सत् -19? 4 - या 1 975 में यहां पर हरियाणा से बीज का बहाना लेकर गुजरात और महाराष्ट्र को गेहू बेचा और यह कहा गया किं हम बीज रूलाई - कर रहे है । वह गेहूं जो. 7 2- 76 रुपये क्विटल के भाव से खरीदा गया था, 140 रुपये प्रति क्विटल के भाव पर बीज भेजने के बहाने भेज गया उसमें उनके पार्टनर थे अमीर चन्द सिंगला जिनका अखबारों में और आपने नाम पढ़ा होगा । वह इसमें साझी था । उन्होंने कई लाख रुपये का गेहूं रोहतक के स्टोक से दूसरी जगह भेजा (विधन).. तो वहां गुजरात में नासिक की मंडियों में जाकर वह फरोख्त किया । नासिक के स्टेशन पर इस बारे में शोर पडा, उसके बारे

में पर्चे दर्ज हुए और पुलिन की जो इन्वैस्टीगेशन नायक साहब मुख्य मंत्री मनु। राष्ट्र के कराना चाहते थे वह इन्होंने रोक दी। इस तरह से सरकार ने लाखों रुपये टापने एजेंटों और चमचों से मिलकर कमाये जबकि वह गेहू जोकि 1 40 रुपये के भाव से वह—। पर बीज के नाम पर ले जाया गया जो कि यहां पर किसान से 7 2— 76 रुपये क्विटल के भाव से खरीदा गया था। आज यह जनता पार्टी की सरकार की नुक्ताचीनी करते हैं कि जाता पार्टी की सरकार किसानों के साथ इन्साफ नहीं करना चाहती। यह तो अंसलीयत और हकीकत से आंखें बन्द करना चाहते हैं। डिप्टी स्पीकर महोदय, यहां पर जो कीमतों का सवाल है, इसमें चौधरी शमशेर सिंह जी का जो रैजो— लूशन है, उसका एक और भी पहलू है 'कि कीमतों का जायजा लिया जाये और उसकी कास्ट आफ प्रोडक्शन के 'हिसाब से कीमते मुकर्रर की जाये। यह सवाल बड़ा टेढा है। इसमें कितनी ही बार हरियाणा सरकार ने कास्ट आफ प्रोडक्शन अपने एक्सपर्ट्स की मारफत, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार की तरफ से और पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, लुधियाना के जो एक्सपर्ट्स हैं, उनकी मारफत निकलवायी है। सन 1964—6 5 में निकलवायी थी जबकि चौधरी राम किशन की मिनिस्ट्री थी। उस समय सरदार गुरनाम सिंह की चेयरमैनशिप में एक कमेटी मुकर्रर की थी उन्होंने गेहू तथा और जिन्सों के बारे में छानबीन करके आनी रिपोर्ट दी। (विघ्न) अब भी हर साल सरकार अपने तरीके से एक्सपर्ट्स के द्वारा कास्ट आफ प्रोडक्शन का तखमीना लगवाकर सेन्ट्रल गवर्नमेंट को भेजती है, ए0 पी0

सी० को भेजती हैं लेकिन चौधरी शमशेर सिंह इस तत से सहमत होंगे कि ए० पी० सी० इन कीमतों को ठीक नहीं मानता । उनका अपना नाप्तोल है किसके द्वारा वे कास्ट आफ प्रोडक्शन लगाते हैं । वह जो फ़ैमिंत्री मैम्बर्ज की मेहनत है उसको कास्ट आफ प्रोडक्शन में नहीं गिनता । जोकि-सान. का नुकसान होता है वह भी कास्ट आफ प्रोडक्शन में नहीं गिनता

श्री उपाध्यक्ष : आपका समय हो गया है । आप जल्दी खत्म करें ।

चौधरी रिजक राम : बस मैं आखिरी बात कहकर समाप्त करता हूँ । उपाध्यक्ष महोदय यह जो रेजोलूशन है और जिसमें कहा गया कि एक कमेटी मुकर्रर की जाए और उस कमेटी के द्वारा किए गए तखमीने को ए० पी० सी० मान ले । जहां तक जिन्सों की कीमत का सवाल है यह कोई इतना आसान काम नहीं है । इस देश में गरीब कंज्यूमर भी हैं उनमें गरीब लोग, छोटी तनखाह वाले कर्मचारी शामिल है और सरकार को उनका इंट्रैस्ट भी वाच करना पड़ता है । उनके इंट्रैस्ट को नजरअन्दाज नहीं किया जा सकता । डिप्टी स्पीकर साहब, मैं यह कह रहा हूँ कि आखिर इस समस्या को हल करने के लिए क्या पालिसी निर्धारित की जाए । आपके सामने जम्मू और काश्मीर की मिसाल है । वहां पर पिछले पच्चीस तीस साल से पचासपै से या चालीस पैसे किलो के हिसाब से चावल सप्लाई हो रहा है । 19 48- 49 से वहां पर सबसी- जाइज्ड राइस दे रहे हैं । मद्रास में भी ऐसा ही हुआ था

और वहां पर भी सबसीजाइज्ड चावल सप्लाई किया गया था । अगर इस देश में कोई पालिसी मुकर्रर हो सकती है जिससे किसान को पूरी कीमत भी मिल जाए, उसको कुछ मुनाफा भी दिया जाए और इसके साथ ही गरीब आदमी को सबसीजाइज्ड रेट पर अनाज दिया जाए । अनाज के बगैर कोई जिन्दा नहीं रह सकता । गरीब आदमी का ज्यादातर रुपया इस अनाज पर ही खर्च होता है । जब चीनी के लिए दो भाव यानी लेवी शूगर और की शूगर तथा और भी कई चीजें हैं जिनमें दो भाव हैं तो अनाज के दो भाव क्यों न दिये जायें । बड़े बड़े कारखानेदार जो शाम को चालीस रुपये की बोतल खरीद सकते हैं तो वे ज्यादा पैसे देकर अनाज भी खरीद सकते हैं । उनसे कोई भी कीमत ली जा सकती है । उनसे चाहे पांच रुपये का भाव ले लिया जाए, दस रुपए का भाव ले लिया जाये— । बहुत से कारखाने हैं जो अपने कर्मचारियों को सबसीजाइज्ड रेट पर चीजें सप्लाई करते हैं । प्लानिंग मिनिस्टर ने पहले एलान भी किया था और उनका विचार था कि असैनशियल कमोडिटीज के लिए दो तरह की कीमत होगी । एक बड़े आदमियों के लिए अलहिदा और छोटे आदमियों के लिए अलहिदा और किसानों को उनकी पूरी कीमत मिलेगी । ऐसा किए बगैर, डिप्टी स्पीकर साहब यह सरकार कभी भी किसान को पूरी कीमत उसकी चीज की नहीं दे सकती. क्योंकि सरकार गरीब आदमी के इट्रस्ट को कभी इग्नोर नहीं कर सकती । इतना कहकर मैं समाप्त करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : अब सिंचाई मंत्री बोलेंगे ।

सिंचाई तथा बिजली मन्त्री (श्री वीरेन्द्र सिंह) : डिप्टी स्पीकर साहब, श्री शमशेर सिंह ने यह रेजोल्यूशन मूव किया और इस प्रकार से अपना भाषण किया कि जैसे सारे मुल्क और हरियाणा के किसानों का दर्द उनके पास मौजूद है और यह शेर बिल्कुल ठीक बैठता है

सारे जहां का दर्द मेरे जिगर में है ।

बहिर्गमन

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू : डिप्टी स्पीकर साहब, मुझे टाईम दीजिए मे कुछ सुजेशन देना चाहता हूं (व्यवधान) ।

श्री उपाध्यक्ष : अब मैंने मिनिस्टर को काल अपॉन कर लिया है । अब वे बोलेंगे (व्यवधान) ।

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू : आप मुझे दो मिनट दे दीजिये—

श्री वीरेन्द्र सिंह : डिप्टी स्पीकर साहब, मैं शुरू कर चुका हूं (व्यवधान).....

चौधरी हरस्वरूप बूरा : आन ए प्वांयट आफ आर्डर, डिप्टी स्पीकर साहब, जब मिनिस्टर महोदय ने बोलना शुरू कर दिया है तो किसी को भी टाईम न दिया जाए (व्यवधान) ।

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू : अगर मुझे बोलने नहीं दिया जाता तो मैं वाक आउट करता हूँ ।

(इस समय चौधरी जगजीत सिंह पोहलू सदन से उठकर चले गए)

गैर-सरकारी संकल्प संख्या

गेहूँ, कपास, चावल, गन्ना तथा वालों के उत्पादन परिव्यय के प्रश्न पर विचार करने के लिए सदन की एक उच्चाधिकार समिति नियुक्त करने सम्बन्धी (पुनरारम्भ)

श्री वीरेन्द्र सिंह : डिप्टी स्पीकर साहब, मैं अर्ज कर रहा था कि किसान के सेन्टीमेंट का या किसान के हितों का जितना ख्याल इस सरकार को है उतना कांग्रेस को कभी नहीं था । जिस पार्टी से मेरे लायक दोस्त आए हैं उस पार्टी ने तो कभी भी किसान के हित के बारे में सोचा ही नहीं था । उनकी तबाही के लिए ये लोग जिम्मेवार रहे हैं । इन्होंने तो किस! न के हित के लिए कमी सोचा ही नहीं था । चौधरी साहब, हमारे मुकाबले में लैंडलार्ड जरूर है पर किसान के सैन्टीमेंट्स का किसान के हित का जितना ख्याल इस तरफ बैठे हुए लोगों को हो सकता है उस तरफ बैठे हुए साहिबान को नहीं हो सकता । उसका कारण साफ है और मेरे लायकरू दोस्त ने खुद माना है कि देश को स्वतन्त्र हुए तीस साल हो गए लेकिन किसी किसान के घर में यूरिनल नहीं है, किसी किसान के घर में बाथरूम नहीं है, किसी किसान

के घर में सफेद चादर नहीं है, किसी किसान के घर में कोई अच्छी प्रकार की सीनरी नहीं है, कोई कारपैट नहीं है । डिप्टी स्पीकर साहब जनता पार्टी की सरकार को तो बने हुए अभी आठ ही महीने हुए हैं । इन सब बातों के लिए तो मेरे माननीय सदस्य ही जिम्मेदार हैं जो तीस साल तक किसानों को बहकाकर मजदूरों से लडवाते रहे और बड़े अफसोस की बात है कि कुछ दिन पहले श्री शमशेर सिंह बहुत अण्डे आदमी हुआ करते थे जब से कांग्रेस के बेन्चिज पर बैठने लगे पता नहीं क्या हो गया । मैं तो कहता हूँ कि अब भी सम्भल जाओ । मैं अर्ज कर रहा था कि पिछली कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किसान के हित के साथ कितना जुल्म किया इसके बारे में डिटेल्ड रूप में हमारे माननीय बुजुर्ग सदस्य **चौधरी** रिजक राम ने काफी रौशनी डाल दी है । मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता । मैं तो सिर्फ यह कहना चाहता हूँ कि जनता पार्टी की सरकार के हकूमत सम्भालते ही चने का भाव 95 रुपए से 125 रुपए किया है । डिप्टी स्पीकर साहब, जनता पार्टी की सरकार ने हकूमत संभालते ही फूड जोनज को तोड़ा (तालियां) जैसे कि **चौधरी** रिजक राम जी ने बताया कि एक एजेन्सी भाव मुकर्रर करने के लिये है और जुरिसडिक्शन गर्वनमेंट आफ इंडिया की है और एक एजेन्सी एग्रीकलचर प्राईस कमिशन है और उसके चेयरमैन ने एक किताब लिखी थी जैसा कि **चौधरी** रिजक राम जी ने हवाला दिया, उसके चेयरमैन को जनता पार्टी की सरकार ने मुकर्रर नहीं किया था जोकि इस किस्म की किताबे लिखता है डिप्टी स्पीकर साहब, **चौधरी** शमशेर सिंह ने यहां पर फार्मर्ज के

नुमाइन्दे का जिक्र किया । एक भूतपूर्व कांग्रेस एम0 पी0, **चौधरी** रणधीर सिंह जो बदकिस्मती से इस हरियाणा के ही रहने वाले हैं, एग्रीकल्चर प्राईस कमिशन में बैठे हैं, वह भी कांग्रेसी विचारधारा के थे, इसलिये वह भी किसानों के हित को नहीं देख पाये, ये जो जितनी बातें हैं इसकी पिछली सरकार जिम्मेवार है । वही सरकार, जिसकी यहां पर **चौधरी** शमशेर सिंह नुमाइन्दगी कर रहे हैं और फिर गिला हमारे साथ करते हैं । 1 वय 15 साल की हमारी जनता पार्टी की हकूमत हो जाए, तो किसान के घर घर में बाथ रुम होगा, यूरिनलज घर घर मिलेंगे (तालियां) और आज किसान के चेहरे पर जो जरदी है, उसको सुरखी में बदल दिया जाएगा (तालियां) **चौधरी** शमशेर सिंह क्या बात करते हैं इस जनता पार्टी की सरकार से जो किसानों की पूरी तरह से हमदर्द है, मजदूर को, गरीब किसान को, छोटे व्यापारियों को, छोटे सरकारी कर्मचारियों को इस सरकार से ऐसी कोई ताकत नहीं है जो अलग कर सके (तालियां) चौधरी साहब आप की सरकार के वे काले कारन) में एक-एक आदमी को याद हैं, उनका एक इतिहास भी लिखा जाएगा और उसका रिकार्ड भी. बाकायदा तौर पर तैयार होगा । (विधन) करनाल में तो लाखों पर जीतेंगे, आप क्या बात करते हैं—डिप्टी स्पीकर साहब, अगली बात जो मैं अर्ज करना चाहता हूं कि हमारे दोस्त आज किसानों के हितों को भूल गये । कांग्रेस पार्टी की सरकार ने अपने पिछले 30 सालों की हकूमत के दौरान किसानों की भलाई के लिये 17 से 20 परसेन्ट तक भी खर्च नहीं किया लेकिन केन्द्रीय सरकार ने इस वर्ष अपने बजट में

किसानों की भलाई केलिये 40 परसैन्ट एग्रिकल्चर सैक्टर पर रवर्च करने का फैसला किया है लेकिन हरियाणा सरकार ही एक ऐसी सरकार है जिसने 70 से 75 प्रतिशत किसानों के लिये मौजूदा बजट में खर्च करने का प्रोविजन रखा है । (थम्पिंग)

श्री शमशेर सिंह : यह दोनों ही फिगरज बोनस है ।

श्री वीरेन्द्र सिंह : डिप्टी स्पीकर साहब, ये लोग किसानों के हितों को क्या जाने । यह हरियाणा सरकार किसानों के हितों को पूरी तरह से प्रोटेक्शन देने के लिये जागरुक है और हम हर कीमत पर यह कोशिश करेंगे कि किसान को बढ़िया से बढ़िया भाव मिले किसान- के माथ कोई किसी किस्म का अन्याय नहीं होगा । जहां तक प्राईसिज का ताल्लुक है, सरकार जो अपनी तरफ से प्राईसिज रिकार्ड करके भेजती है चाहे, पलसिज की हों, या किसी और अनन की हो, उस के बारे सरकार यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट्स को कंसल्ट करती है, अपनी तरफ से सिफारिश अधिक भेजती है । यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट्स जो कास्ट प्राईस बताते है उससे अधिक सरकार रिकमेन्ड करके भेजती है तो मेरे ख्याल में ऐसा कोई अब औचित्य नहीं रह जाता कि इस हाउस की एक कमेटी बनायी जाए जो इस बारे में विचार करे । इस हाउस के 75 मैम्बर जो कि जनता पार्टी के हैं, इस सरकार के साथ हैं, सरकार पूरी तरह से जागरुक है ओर इस सरकार पर सब लोगों का पूर्ण विश्वास है कि सरकार किसानों के हितों को कभी नहीं भूलेगी इसलिये इस रैजोल्यूशन का अब फिर कोई औचित्य ही नहीं रह

जाता । मेरे लायक दोस्त भी किमान हैं उनको भी बतौर किसान हमारे पर विश्वास करना चाहिये । डिप्टी स्पीकर साहब, मैं यह कहकर कि चौधरी शमशेर सिंह जी अपना रेज्योल्यूशन वापिस ले लें, आप का धन्यवाद करता हुआ अपना स्थान लेता हूँ कि आपने मुझे बोलने का समय दिया ।

श्री उपाध्यक्ष : क्या माननीय सदस्यगण अपना रेजोल्यूशन 'विदग्धा करना चाहते हैं'?

श्री शमशेर सिंह : नहीं जी, बाई वे आफ 'रिप्लाइ' में बोलना चाहता हूँ ।

श्री उपाध्यक्ष : अच्छा आप बोलिये ।

चौधरी संत कंवर : डिप्टी स्पीकर साहब, मेरा यह प्वांयट आफ आर्डर है कि आप रूल 87 को देखिये, उसमें यह लिखा है कि जिन्होंने प्रस्ताव पेश किया हो वे 15 मिनट तक बोलेंगे, इन्होंने पहले 1 5 मिनट तक बोल लिया है

श्री उपाध्यक्ष : अच्छा आप बैठिये ।

श्री शमशेर सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, चौधरी वीरेन्द्र सिंह जी ने यहां पर बोलते हुए कांग्रेस सरकार की नीतियों, उनकी बातों की काफी नुक्ताचीनी की है, मैं उस सारी तफसील में नहीं जाना चाहता, मैं सिर्फ आपके माध्यम से इस सरकार के सामने यह कहना चाहता हूँ कि मगरमच्छ के आंसू हम बहाते हैं या ये लोग

बहाते हैं इस का आज यह इम्तहान है । आज की स्थिति में जब ये लोग सरकार के अन्दर बैठे हैं तो इनको यह अधिकार हैं कि जो कुछ मजा कहें पर किसानों की— भलाई में ही यह बात जाती है किवे एक कमेटी बना दें, यह बड़ी इन्नोसैंट बात है सरकार के जिराफ नहीं है, चाहे वे अपनी जनता पार्टी के ही मैम्बरों की एक कमेटी बता दें, उसमें कोई जरूरत नहीं 'विरोधी भाईयों' के मैम्बरों को लेने की पर सरकार को यह पता है 'कि अगर सरकार इस प्रकार की कोई कमेटी बना देती है तो वह खुद नंगी होगी, एक्सपोज होगी। चौधरी रिजक राम जी ने कहा कि पहले फूड जोनज थे, फारवर्ड टेर डिंगज थी उन पर पाबन्दी थी और फायनेशियल कर्बज भी थे लेकिन मैं उन को यह कहना चाहता हूँ कि वह स्थिति 'बिल्कुल मुखतलिफ थी फारवर्ड टेरडिंग और फायनेनशियल रिस्ट्रेक्शन्ज थे । पहले मिडल क्लास के व्यापारी 'किसान से अनाज खरीदते थे और उनसे आगे बम्बई कलकत्ता के बड़े बड़े व्यापारी अनाज खरीद कर मुनाफा कमाते थे, इस चीज को कर्ब करने के 'लिये फूड जोनज बनाये गये थे ताकि दूसरी जगह के बड़े बड़े व्यापारी उसका नाजायज फायदा न उठाएं दूसरी बात यह थी कि उस समय अनाज की स्केरसिटी थी इस वजह से भी फूड जोनज बनाये गये थे पर अब स्थिति और है, देश में अनाज की कोई कमी नहीं है, इसलिये फूड जोनज तोड़ दिये गये हैं । तो डिप्टी स्पीकर साहब मैं आपके माध्यम से यह दर्खास्त करूंगा कि इसमें कोई पार्टीबाजी का सवाल नहीं है, इसको सारे हाउस के मैम्बर साहिबान दिल से चाहते हैं, इसके

लिये किसी भी मैम्बर के पर कोई अंकुश लगाने का मतलब ही नहीं है, आप इस बात को मन्जूर करें और हाउस की एक कमेटी बनायें जोकि सिर्फ इस बात का फैसला करे कि किसान को एक क्विंटल गन्दम पैदा करने पर कितना खर्चा करना पड़ता है, यह एक मामूली सी बात है, इसलिये डिप्टी स्पीकर साहब, मैं दख्तास्त करूंगा कि इसको मान लिया जाए ।

Mr. Deputy Speaker : Question is—

This House recommends to the State Government to appoint a high powered Committee of this House assisted by experts from Haryana Agricultural University including farmers to go into the question of cost of production of per quintal of Wheat, Cotton, Rice, Sugar-cane and pulses.

This House further recommends to the State Government to approach the Central Government to fix the support price of each of the above-said commodities in the light of the recommendations of Cie said Committee.

The motion was lost

गैर-सरकारी संकल्प संख्या 2

राज्य वें पूर्ण नशाबन्दी लागू करने को सुगम बनाने हेतु प्रथम पग के रूप में राज्य में 21 वर्ष तक की आयु के सभी व्यक्तियों को शराब बिक्री तथा उनके पीने पर पाबन्दी लगाने सम्बन्धी

Mr. Deputy Speaker : The next resolution is in the

name of Shri Baldev Tayal. He may please move his resolution.

Shri Baldev Tayal (Hansi) : Mr. Deputy Speaker Sir, in view of the latest provision of law brought to my notice, I, with your and with the permission of the house, do not move my resolution.

Mr. Deputy Speaker : Alright.

The next resolution is in the name of Shri Hari Chand Hooda. He may please move his resolution.

गैर-सरकारी संकल्प संख्या 3

तहसील झज्जर के ब्लाक बेरी तथा गाइड के क्षेत्रों को औद्योगिक तथा आर्थिक रूप में पिछड़ा घोषित करने सम्बन्धी

चौधरी हरि चन्द हुड्डा (किलोई) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूँ डिप्टी स्पीकर साहब, मैंने बेरी और नाहड के क्षेत्रों को सम्पन्न बनाने के लिये अपना प्रस्ताव रखा है । रोहतक ब्लाक में जो मसीद, मुकराली, छोटी मुकराली और चमारियाँ के इलाके हैं ये पानी ने तोड़ रखे हैं । यह एक आंखों देखा दृश्य है । जो लोग गोहाने से रोहतक को जाते हैं तो रोहतक शहर में 8— 9 फुट का बंध लगा हुआ है और वहां 8— 9 फुट पानी खड़ा हो जाता है और उससे रोहतक ब्लाक के 1 वय 1 1 गांव पानी में डूब जाते हैं इसलिये उनकी हालत भी नाहड तथा बेरी क्षेत्रों जैसी है । मैं यह चाहता हूँ कि जो फलड इफैक्टिव एरियाज है उनको सैल्फ सफिशिएंट बनाने के लिये सरकार प्रयत्न

करे तथा उनके अलावा जो और ब्लाक भी ऐसे हैं उनकी तरफ भी ध्यान दिया जाए और पोलिटिकल खलूफा से मेरी. यह दर्खास्त है कि वे मसलें को उलझाने की बजाए सुलझाने में ज्यादा ध्यान दे वरना ऐसा न हो जैसे अखबार को जनता पढ़ कर रद्दी की टोकरी में फेंक देती हैं, ऐसा हशर न हो जहां तक इन ब्लाकों को सैल्फ सफिशिएंट बनाने की बात है यह कोई नई बात नहीं है । देहातो के लोग तीस साल पहले । आजादी मिलने से पहले सैल्फ सफिशिएंट रहे हैं । गांवों में खुदा का नूर भी है और खुदा का झूर भी है । गांवों में पुरानी दास्तां की झलक आज भी मिलती है । वेद और पुराणों की आज भी गांव गांव में देखने को चर्चा मिलती है । गांवों के लोग 30 साल पहले वैल प्लान्ड थे और वे सारी बातें खुद कर लेते हैं थे । उस समय कोई लम्बा चौड़ा ला भी नहीं होता था केवल एक ही सिस्टम था और वह था तागडी या पागडी. का । इस सिस्टम से गौरों के लोग सैल्फ सफिशिएंट रहते थे । उस समय किसान और दस्तकार की दस्तकारी का मेल जोल रहा है । सारा गांव अपना धंधा करता था और अपने बच्चों से मेल जोल रख कर कमाता और खाता था । यह सब कुछ गुलामी के बावजूद भी होता रहा ' लेकिन 30 साल पहले जो हकूमत आई वह हकूमत के साथ-साथ पार्टिशन भी लाई । यह कितनी बदकिस्मती है कि देश में आजादी आये और हकूमत बदले और वहां हकूमत के साथ पार्टिशन भी लाए । उस पार्टिशन की वजह से कितने लोग बेकार हुए और 8- 10 लाख लोग मारे गये लेकिन इतिहास में उनका नाम भी नहीं रहा । यह जो इतिहास

बनाने जा रहे हैं इसकी जिम्मेदारी किस पर होगी? इसकी जिम्मेदारी जनता पर नहीं होगी । जो लोग पीछे चले गये वह तो चले गये बोर इन तीख सालों में आजादी के बाद जो वाकायात हुए वह सारे पिछली हकूमत की वजह से हुए । पहली बात तो यह हुई कि गांवों में जो ईमानदारी तथा इन्साफ था उसकी सफाई कर दी गई दूसरे गांवों के किसान और मजदूर में एक तो खींचा तानी करवा दी और फिर उनके पर टैक्सों और कर्जों का इतना बोझ लाद दिया कि गांव का किसान निढाल हो गया । गांव के दस्तकार की दस्तकारी का ऐसा सिस्टम बना दिया कि वह सिस्टम उसको खा ही गया । जैसे जुलाहे को टाटा खा गया, मोची को बाटा खा गया । कुम्हार को क्राकरी हाउस खा गया और सारे ही देहात में एक अंधेरा छा गया । अब यह जनता पार्टी अपने साधनों से, अपने विचारों से और जंपने बजट से एक प्रयत्न करने जा रही है । अच्छा तो यह है कि इस पार्टी को कुछ टाइम मिले इसलिये इस को उलझाया न जाए बल्कि इसे सुलझाया जाए । अगर ऐसा होगा तो सार देश को सुख का सांस मिल सकता है 1 अब मैं सैल्फ सफिशिएंसी के बारे में बात करूंगा कि यह जो बजट है जैसे पंचायतों के फंड आते हैं उसी तरह से सारे हरियाणा के जो फंड हैं उसे बजट कहा जाता है और इस बजट को हम फंडज भी कह देते हैं । ये जो लोग बैठे हैं ये हरियाणा की पंचायत हैं.....

चौधरी हरस्वरूप बूरा : डिप्टी स्पीकर साहब, मेरा प्वांयट आफ आर्डर है कि जो रैजोल्यूशन है वह बेरी तथा नाहड

के इलाकों को आत्म निर्भर बनानेके लिये औद्योगिक सुविधाएं देने संबंधी है लेकिन माननीय सदस्य और ही बातें कर रहे हैं ।

चौधरी हरि चन्द हुड्डा : डिप्टी स्पीकर साहब मैं अभी सैल्फ सफिशिएंसी की बात कर रहा था । यह बात मैं सब केरु लिये कर रहा था । जैसे हम बजट लाते हैं तो इसमें सब से बढ़िया बात तो यह है कि ऐसी चीजों को हमें डिसेंटरलाइज. कर देना चाहिये । पहली. जीत तो यह है कि किसी भी पैसे के लिंपे ईमानदारी की जरूरत है अपार हम। रें पास पैसा है— और ईमानदारी नहीं है तो क्या होगा ? वह उसी तरह से होगा जैसे पहले 30 साल. पैसा बर्बाद होता रहा है । मैं हाउस. के आनरेबल मैबर्ज से कहूंगा कि जहां भी पैसा है उस पैसे की डिस्ट्रीब्यूशन में कितनी ईमानदारी वे दिखाते हैं यह उसकी तसवीर होगी । अगर हमने ईमानदारी. दिखाई तब तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन ठीक होगी और अगर न दिखाई तो डिस्ट्रीब्यूशन ठीक नहीं हो सकती । डिसेंटरलाइजेशन उसको कहते हैं कि फर्ज करो हम कोई पैसा जिलों में ले जाते हैं तो वह पैसा जिलों से ब्लाकों में जाए, ब्लाकों से गांवों में जाए और गांवों से गरीबों के घरों में जाए । ऐसा करने से बीच का जो मामला है वह खत्म हो जाएगा और इससे देश को सुख का' सांस मिलेगा । दूसरी बात मैं ब्लाकों के सिलसिले. में कहना चाहूंगा । जो हमारे ब्लाक हैं उनकी जो डिवैल्पमेंट करने जा रहे हैं, उसके लिए फार्मूला इस्तेमाल' किया जाए । फार्मूला दह है कि ब्लैक्स की जो प्रौब्लम्ज हैं उनको हल

करने के लिए लोकल ओपीनियन आफ दी पीपल ली जाए । तागडी पागड़ी का जो पुराना सिस्टम था, अपार यह रहा तो देश बड़े सुख से जीएगा । अगर हम इस सिस्टम को लेकर चलेंगे, जनता की ओपीनियन से चलेंगे तो एक्सप्लायटेशन हट जाएगी ।

अब मैं इसके बारे में कुछ सुझाव रखूंगा । फर्ज करो हम देहातों के लोगों को पैसा नहीं दे सकते तो कम से कम उन के रास्ते में रुकावट भी न डालें । कमाना तो उन्होंने है, सारा बर्डन' बरदाश्त करना है, सारा देश उन के सिर पर है, अगर इनको देना कुछ नहीं है तो उन के रास्ते में जो रुकावटें हैं, अगर उनको दूर कर दें तो शायद यह उनकी बड़ी सेवा होगी । मेरे ख्याल में यह उनकी सबसे बड़ी सेवा होगी । (व्यवधान) मिसाल के तौर पर बन्दोबस्त 183 1 में हुआ, 1 841 में भी हुआ 1879 में भी हुआ और अब 1 961 का पंजाब एक्ट है । इस तरह से बन्दोबस्त होता-होता लास्ट तक आ गया और गांवों में' निल है बन्दोबस्त पर बजट भी ज्यादा नहीं लगता, कोई लम्बी चौड़ी बात नहीं है । एक पटवारी के पास ज्यादा से ज्यादा तीन गांव होते हैं, तो तीन सर्कल होते हैं । पटवारी महीने में, या पन्द्रह दिन में बन्दोबस्त कर दे तो लोगों की परेशानी दूर हो जायेगी । उस बन्दोबस्त की एक कापी गांव की पंचायत में रख दो जाए और एक कापी सरकार के पास चली जाए । इससे यह होगा कि एक गांव के 8, 0— 90 मुकदमें खत्म हो जाएंगे, गांव वालों को चौन मिलेगा । इस सुन्टरफीयरैसं को दूर कर दें ताकि वे सैल्फ सफिशिएंट

होते चले जाएं और लिटिगेशन पर फजूल पैसा न लगाएं मुकदमों से लोग बच जाएंगे, सुख से कमाने लगेंगे । जहर तक सीलिंग का ताल्लुक है न किसान से कोई जमीन ली और न किसी मजदूर को दी गई । यह एक बर्निंग क्वेश्चन है.....

श्री उपाध्यक्ष : आपको बोलते हुए 1 0 मिनट हो गए हैं, आप बैठ जाइए ।

चौधरी हरि चन्द हुड्डा : सिर्फ दो मिनट और लूंगा । आप सीलिंग को खत्म कर और मारे हरियाणा में बर्निंग क्वेश्चन बना हुआ है, इससे आपस में लड़ाईया होती है । कस्टो- डियन की जमीन को लेने का सिलसिला पिछले 30 साल से चला आ रहा है लेकिन किसी को नहीं मिल रही । ये जो दो चार कानून हैं इन को खत्म करें, जितना खत्म करेंगे उतना ही जनता को रिलीफ मिलेगा । इन की जगह पटवारी अपने सर्कल में बन्दोबस्त का इन्तजाम करवा दे तो लोग सुखी हो सकते हैं । पार्टिकुलरली एक दो ब्लाक ही नहीं बल्कि सारे ब्लाकों को आराम मिल जाएगा, देहाती लोगों को सुख मिलेगा, चौरन मिलेगा, क्योंकि कई दफा किसान के पर बहुत ज्यादा बर्डन पड़ जाता है । (श्री जगन्नाथ जी की तरफ से विल) ।

श्री उपाध्यक्ष चौधरी साहब, आप बैठ जाइए, काफी समय हो गया है ।

चौधरी हरि चन्द हुड्डा : मुझे अपने दोस्त से बड़ा प्यार है, वे हंसते भी हैं और फाइल देखते ही नहीं । मैंबरों को टर्का देते हैं श्री जगन्नाथ जी. (व्यवधान) किसान के पर बहुत बर्डन बढ़ जाता है, आबयाना 10 परसैट बढ़ गया, यह भी किसान के पर बर्डन है । इसी तरह से किराया बढ़ा दिया । जनता जब हमें खैंचेगी तो हम क्या जवाब देंगे.....

श्री उपाध्यक्ष : अब आप बैठ जाइए, बाकी मैंबरों ने भी बोलना है ।

चौधरी हरि चन्द हुड्डा : एक मिनट में खत्म करता हूं । मेरे कहने का मतलब यह है कि बेरी और नाहडू के पिछड़े हुए ब्लाकों को, जो फलड इफैक्टिड इलाके हैं उनको बैकवर्ड एरिया घोषित किया जाए । 8- 10 साल से वैकवर्ड हैं, सांगला पिछड़ा हुआ है, रोहतक की झज्जर तहसील 20 साल से पिछड़ी हुई है । इनके अलावा और भी बहुत से इलाके हैं । मेरी सरकार से दर्खास्त हे कि इन सब को सैल्फ सफिशिएट बना दें, द्रुम सरकार को दुआएं देंगे ।

Mr. Deputy Speaker : Motion moved—

This House recommen is to the State Government to delcare the areas of Beni and Nahar Blocks of Tehsil Jhajjar, as Indusrially and Economically backward and to make them resourceful and self-sufficient, necessary steps be taken to provide Industrial facilities there.

चौधरी उदय सिंह दलाल : (बादली) डिप्टी स्पीकर साहब, सालाहावास, बेरी' और झज्जर का जिक्र हाउस में आया 'कि इन इलाकों में फ़ैक्ट्रीज. वगैरह लगाने के लिए इन इलाकों को बैकवर्ड घोषित किया जाये । मैं आपकी मारफत सरकार से रिक्वैस्ट करूंगा कि तहसील झज्जर का तमाम पुराना इलाका काफी बैकवर्ड था, क्योंकि इस इलाके को कुदरत की मार पड़ती है । पहले पानी नहीं था इसलिए बैकवर्ड किया था क्योंकि लोग सरकार को लगान वगैरा देने के लायक नहीं थे । अब कुदरत का प्रकोप है, सारे इलाके में फलड का पानी आ गया, तबाह हो गया, अब तो ज्यादा हालत खराब. हो गई । तीन ब्लाक्स फलड की लपेट में आ गए हैं, नाहर, झज्जर और बेरी । बहादुरगढ़ ब्लाक पुरानी तहसील झज्जर का एरिया है, फलड ने इसको भी मार दिया है । इन सभी इलाकों में बुरी तरह से तबाही हुई है । इन इलाकों के जो बेरोजगार लड़के हैं, वे छोटे धन्धे खोलकर अपना गुजारा करना चाहते हैं, उनको सरकार की तरफ से सहूलियत मिल जाएगी, इसलिए मैं आपकी मारफत सरकार से अपील. करूंगा कि इन इलाकों को बैकवर्ड घोषित कर दें और फ़ैक्ट्री- वगैरह लगा ने के लिए जो सहू- लियतें इनको मिल सकती हैं, उसमें कन्सैशन जरूर दिये.। -जाये । मैं सरकार से अपील- करूंगा कि बहादुरगढ़ ब्लाक को इस में इनक्लूड कर लिया जाए, क्योंकि यह तहसील झज्जर का पुराना ए रिया है । खामखाह नया सवाल पैदा करते है, बैकवर्ड एरिए को दोबारा बैकवर्ड एरिया डिक्लेयर करते हैं । मेरे ख्याल में आफिसरों से कागजों में गलत एंटरी हो गई है

जिसका नतीजा भुगतना पड़ रहा है । जब एक बार एक इलाके को बैकवर्ड डिक्लेयर कर दिया तो दोबारा घोषित करने की क्यों नौबत आई? अगर कोई टैक्नीकल गलती है, तो मैं सरकार से आपकी मारफत प्रार्थना करूंगा कि सरकार अपने कागजों में पूर्ति जरूर ठीक कर ले और बहादुरगढ़ तहसील झज्जर के तमाम ब्लॉकों को बैकवर्ड घोषित किया जाए । डिप्टी स्पीकर साहब, बजट पर बोलने का मेरा टाइम बाकी है, मेरा टाइम न काट लेना, बोलना जा री. रखूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष : कल बोल लेना । अब आप बैठ जाइए ।

कैप्टन मांगे राम (झज्जर—अनुसूचित जाति) : डिप्टी स्पीकर साहब, मेरे फाजिल दोस्त चौधरी साहब हरिचन्द हुड्डा जी ने यह जो रैजोल्यूशन रखा है कि :—

This House recommends to the State Government to declare the areas of Beri and Nahar Blocks of Tehsil Jhajjar, as Industrially and Economically backward and to make them resourceful and self sufficient, necessary steps be taken to provide industrial facilities there.

इसके बारे में मैं यह कहना चाहता हूँ कि इसमें झज्जर और सहलावास बलाक का नाम रह गया है । इसलिए मेरी सरकार से यह प्रार्थना है कि न सिर्फ बेरी और नाहडु ब्लॉक्स इंड—स्ट्रियली ऐंड इकोनोमिकली बैकवर्ड करार दिया लगाए, बल्कि सारे झज्जर सब—डिविजन को बैकवर्ड करार दिया जाये ।

चौधरी संत कंवर (हसनगढ़) : डिप्टी स्पीकर साहब, यह जो दो ब्लॉक्स नाहडु और बेरी की बात कही गई, इसके बारे में मेरी अर्ज यह है कि ये ब्लॉक्स तो पहब्ले. भी बैकवर्ड घोषित किए हुए थे सरकार की ओर से लेकिन चौधरी बंसी. लाल और ब्रिगेडियर रणसिंह जी की जब आपस में टसल हुई, तो पोलिटिकली गलत तरीके से इन ब्लॉकों को जो बैकवर्ड घोषित किया हुआ था, उस बात को खत्म. कर दिया. गया । जो हालत इन ब्लाकों की पहले थी, आज हालत उससे भी कही ज्यादा बदतर हो गई है । इसलिए डिप्टी स्पीकर साहब., इन दो ब्लाको की बात का तो मैं समर्थन करता हूं लेकिन जिला रोहतक के कई और भी ब्लॉक्स हैं, इसी तरह से जिला गुडगांव के ब्लॉक्स भी मैं साथ शामिल कर लेता हूं, जहां फलडज की वजह से बहुत बुरी हालत हुई है, उन्हें भी इस प्रस्ताव में शामिल किया जाए । डिप्टी स्पीकर साहब, आपको मालूम ही है कि इस दफा इतना बड़ा फलड आया जिसका तमाम जगह शोर है । यही नहीं, 'डिप्टी स्पीकर साहब, आपको मैं असलियत बताऊं, हमारे यहा तो मां-परनय और बहादुरगढ़ के इलाके में पिछले— दस साल से फलड आता रहा है । इतनी. झील वहां पर है 'कि कई कई मील. तक आज. भी वहां पानी है । अपनी सरकार ने पानी निकालने की कोशिश तो बहुत की, लेकिन सांपला और बहादुरगढ़ के पास आज. भी. पानी खड़ा है । लोगों में हिम्मत नहीं रहीं' कि वे अपना गुजारा खेती— पर कर सकें । इसलिए उन. लोगों को खुशहाल बनाने के लिए यह जरूरी हो जाता है कि उनको यह सुविधा प्रदान की. जाये । हमें

उम्मीद भी है कि हमारा यह काम अवश्य होगा क्योंकि डाक्टर मंगल. सैन जी जो उस -त्रिने का नेतृत्व करते हैं, आज हमारे इंडस्ट्रीज के मिनिस्टर हैं । आज. बहादुरगढ़ को छोड़कर रोहतक के देहात में कोई इंडस्ट्री नहीं है । - (विधन) - बहादूरगढ़ शहर में कुछ इंडस्ट्रीज हैं, लेकिन बाकी जितने ब्लॉक्स है जैसे बेरी., नाहडू, सांपला आदि इन ब्लॉक्स की तो पिछले दस, साल से इतनी बुरी हालत चल- रही है, जिसको मैं ब्यान नहीं कर सकता । उपाध्यक्ष महोदय, रोहतक पहले बड़ा प्रोसपैरस जिला हरियाणा में हुआ करता था, लेकिन बदकिस्मती रही रोहतक .।इ जले की कि डा. मंगल सैन तो लगातार विरोधी पक्ष की सीटों पर बैठते रहे और दूसरे जो काग्रैस के मेंबर रोहतक से थे, वे इतने कमजोर थे कि चौधरी बंसी लाल जी के सामने कमी मुह नहीं खोल पाए । हमेशा हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन होती रही और जब से हरियाणा वरा है रोहतक जिला पीछे जाता रहा है । - (विधन) -

श्री देवेन्द्र शर्मा : सबसे ज्यादा फायदा रोहतक ले गया । रोहतक वालों ने तो अम्बाला और कुरुक्षेत्र वालों को मार दिया । - (विधन) -

चौधरी संत कंवर : उपाध्यक्ष महोदय, ये शर्मा जी जिस जिले से ताल्लुक रखते हैं, उस जिले जैसी पैदावार अगर हमारे यहां हो और वहां बाढ़ न आए, तो हम रोहतक वाले उस जमीर के आदमी है, जो दूसरो को दिया करते हैं, सरकार से मागा नहीं करते । - (थम्पिंग) - डिप्टी स्पीकर साहब, आज हमारी बहुत

खुशकिस्मन्त्री है किं एक अच्छी सरकार हरियाणा में आई है जो किसी के साथ डिस्क्रीमिनेशन नहीं करेगी । लेकिन हमारे मेंबर साहिबान और लीडर साहिबान. डाक्टर मंगल सैन जी की, जो इंडस्ट्री मिनिस्टर भी. हैं, सबसे ज्यादा जिम्मेदारी यह हो जाती है कि इलाके को सिर्फ बैकवर्ड कराने से बात नहीं बनती, बल्कि रूरल इंडस्ट्रीज लगाने में ऐसे इलाके को प्रैफ्रैन्स दी जानी चाहिए । मैं सिर्फ रोहतक जिले की ही बात नहीं करता । बल्कि तमाम देहात के इलाके, जहां बाढ़ का पानी खड़ा है और कई सालों से कुदरत का प्रकोप होता आ रहा है, की तरफ सरकार पूरा ध्यान देगी । डिप्टी स्पीकर साहब, जहां तक नाहडु और बेरी ब्लॉक्स का ताल्लुक है, जैसा मैंने पहले. अर्ज. किया, ये पहले भी बैकवर्ड इलाके थे और अब भी हैं, लेकिन मेरी प्रोपोजल यह है कि इस रैजोल्यूशन में रोहतक, सांखला, कलानौर और दूसरे जिन ब्लॉकों में बाढ़ का पानी खड़ा है, उनको भी शामिल कर लिया जाए । डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपकी मारफत सदन को बताना चाहता हूं कि इन ब्लॉकों के लोगों ने अपने जेवर बेच कर अनाज खरीदा है । बहुत सारे गांव तो ऐसे रहे हैं, जिनके अन्दर दो-दो महीने तक ऑफिसर्ज चाहने के बावजूद भी पंहुच नहीं पाए । कैप्रिहन साहब, जो गेलरी में से अभी उठ कर चले गए, वहां गए थे, और इनको पता है कि रोहतक जिले के अन्दर कम से कम 5 0- 60 गांव ऐसे थे जिनके अन्दर से बच्चे और मवेशी बहुत मुश्किल से हमारे अफसरान ने और जनता पार्टी के मेंबरान ने निकाले । चारे की हालत यह रही कि लोगों ने जो कूप लगा रखे थे, वे तमाम के

तमाम खत्म हो गए । लेकिन हम सरकार का धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने मौके पर लोगों की बहुत मदद की । हमारे सभी मंत्री साहिबान, मुख्य मंत्री जी और दूसरे मंत्री गण वहां गए और लोगों को बड़ी राहत दी, लेकिन यह सब टैम्परेरी राहत थी । उस राहत से बात बनने वाली नहीं है । (विधन) डिप्टी स्पीकर साहब, ये शर्मा जी जो बोल रहे हैं और कंवर रामपाल सिंह जी जो देख रहे हैं, इनके यहां तो पांच पांच सौ बीघे वाले जमींदार हैं, लेकिन हमारे यहां किसी भी मेहनतकश किसान के पास औसतन पांच एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं है । उन हालात में डिप्टी स्पीकर साहब, जिस इलाके में कई साल से विनाश हो रहा है, उस इलाके को पर उठाने के लिए सरकार को जरूर प्रैफ़ेन्स देनी होगी । खेती पर जब किसान का निर्वाह नहीं होता तो यह जरूरी हो जाता है कि रूरल इंडस्ट्री को प्रोत्साहन दिया जाए । इसलिए मैं अपनी सरकार से यह उम्मीद रखता हूँ कि जहां ये नाहडू और बेरी ब्लॉक्स को इस क्षेत्र में प्रैफ़ेन्स देगी, वहां सांपला और दूसरे ब्लॉक्स को, जिनके बारे में मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ, भी बैंक-वर्ड एरिया घोषित करेगी ।

चौधरी सरदार खां (नूह): डिप्टी स्पीकर साहब, श्री हरिचन्द हुड्डा साहब ने बेरी और नाहडू के ब्लॉक्स को इंडस्ट्रियली ऐड इकोनोमिकली बैंकवर्ड करार दिला थे के लिए हाउस के सामने एक रैजोल्यूशन पेश किया है । चौधरी संत कंवर साहब ने इसका समर्थन किया है लेकिन आपके द्वारा मैं सरकार से यह रिक्वैल्ट

करना चाहूंगा कि गुड़गांव जिले के फिरोजपुर झिरका और खास तौर पर पलवल तहसील में फलड से जो नुकसान हुआ है उसको भी सब लोगों ने देखा है । इसके पेशतर भी वहां की हालत अच्छी नहीं थी । इस तहसील को पहले बैकवर्ड करार दे दिया गया था परन्तु बाद में इस बैकवर्डनैस के करार को खत्म कर दिया गया और तमाम रियायतें वापस ले ली गई । अब मैं अपनी सरकार से यह गुजारिश करूंगा कि उन इलाकों को भी बैकवर्ड करार दिया जाए । डिप्टी स्पीकर साहब, फरीदाबाद की वजह से इस इलाके को इंडस्ट्रियली ऐडवांस इलाका करार दिया गया है, लेकिन असलियत यह है कि लोग साईकिल के पन्चर भी ठीक तरह से नहीं लगा पाते, मोटर और कारों की मुरम्मत भी सही तरह से नहीं हो पाती । इसलिए मैं अपनी सरकार से पुरजोर सिफारिश करूंगा कि इस इलाके को भी इंडस्ट्रियली बैकवर्ड करार दिया जाए, ताकि वहां तमाम सहूलियतें वहां के लोगों को मिल सकें, जो दूसरे बैकवर्ड इलाकों के लोगों को मिलती हैं, पूंजीपति लोग वहां जाकर अपनी इंडस्ट्रीज लगा सकें और लोगों को रोजगार मिल सके । वहां आई. टी. आईज. के द्वारा लोगों को ट्रेड किया जाए, ताकि यहां जो ग्रामीण उद्योगों का सिलसिला चल रहा है इसमें लोग कामयाबी हासिल कर सकें, सरकार जो कर्जा ऐडवांस करती है, इस से लोग पूरा फायदा उठा सकें । जहां तक फलड का ताल्लुक है, जैसा मैंने पहले अर्ज किया, उस इलाके में ऐसी हालत है कि वहां ब्यान से बाहर है । कोई पचास गांव अभी भी ऐस है, वहा पानी भरा हुआ है फसलों की काश्त नहीं हो सकी, रिलीफ

देने के लिए भी किशतियों से नाना पड़ता है । मैं गवर्नमेंट का शुक्रगुजार हूं, 'कि इसने लोगों को बहुत रिलीफ दिया । वहा टैरक्टर दिए गए, बीज. दिए गए, खाद दी गई, यहां तक कि लोगों को रजाईयां दी गई । लोग बेइन्तहा खुश है, लेकिन यह परमानैन्ट इलाज. नहीं हुआ । जब तक उसे इंडरिट्रयली बैकवर्ड करार नदिया जाए, तब तक इसका परमानैन्ट हल नहीं होगा । इसलिए मैं एक बार फिर सरकार से गुजारिश करूंगा कि इस रैजोल्यूशन में 'दिए गए इलाके के साथ तहसील पलवल, नूह और फिरोजपुर झिरका के इला को कौ भी बैकवर्ड करार दिया जाए ।

चौधरी हरस्वरूप बूरा (मेहम) : उपाध्यक्ष महोदय, चौधरी हरिचन्द हूड्डा ने जो प्रस्ताव रखा है उनकी पुरजोर ताइद करने के लिए खड़ा हुआ हूं । वे इस प्रस्ताव को लाए, मैं उनका बहुत धन्ववादी हू । उपाध्यक्ष महोदय आप भली भांति जानते है कि सारा हरियाणा खेती बाड़ी पर निर्भर फरता है । यदि हम पिछले 10- 12 साल के हरियाणा के हालात को देखे, जो बाढ़ के कारण बने हुए हैं तो हमे यह सोचना पड़ेगा कि हरिया णा प्रदेशों की. भलाई किस प्रकार से हो सकती है । क्या हरियाणा खेती- डी पर ही निर्भर रह सकता है । मेरे विकर के अनुसार तो केवल' खेती बाड़ी पर निर्भर नहीं रह सकता । यदि हरियाणा को प्रगति के पथ पर लाना है तो हमें इंडस्ट्री. की तरफ भी काफी ध्यान देना पड़ेगा । पहले भी यह तरीका रहा है कि किसी इलाके को उठाना है तो उससे पहले बैक-वर्ड एरिया घोषित करना पड़ेगा और किया है ।

जो उस इलाक़े में सुविधाएं नहीं हैं, वे सुविधाएं दी जाएंगी, तभी वह इलाका पर उठसकेगा । इस प्रस्ताव में बेरी नाहड ब्लॉक और झज्जर तहसील के इलाके के बारे में कहा गया है कि यह इलाका रोहतक जिले का है । इसमें कुछे इलाकी बाढ़ से तबाह हो गया है और कुछ इलाके में पानी की कमी के कारण खुशकी है । इस प्रकार से दोनों तरह से उनकी खेती-बाड़ी पूरी तरह से झंझोड के रख दी है । दस बारह साल से उनकी बहुत बुरी हालत है । मैं आपके जरिए निवेदन करूंगा कि इस इलाके को सैल्फ सफिशिएट बनाने के लिए यह प्रस्ताव स्वीकार किया जाए । डिप्टी स्पीकर साहब पिछले सालों से हम लड़ते रहे हैं और हमेशा हमने इनका साथ दिया था । आपको पता होगा कि रोहतक के अन्दर एक इंडस्ट्रियल कालोनी बनाई गई, लैण्ड इक्वायर केर ली' गई लेकिन किन्ही कारणों से सारी डिवैल्पमेंट रोक दी गई । आज जनता सरकार इस इलाके को पर उठानी चाहती है । म्उझे बड़ी खुशी है । इस प्रस्ताव की मैं पुरजोर शब्दों में तार्ईद करता हूं ।

उद्योग मन्त्री (डा मंगल सैन) : डिप्टी स्पीकर साहब मेरे लायक दोस्त माननीय सदस्य चौधरी हरिचन्द हुड्डा जी एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव सदन में लाए हैं । मेरे लायक दोस्त के दिमाग में तो बहुत अच्छी-अच्छी बातें होती हैं लेकिन उस समय वे उन बातों को भूल गए और बाद में उन बातों को भी जोड़ दिया क्योंकि वे उनके दिल के जजबात हैं, वे बताना चाहते थे लेकिन, कुछ मजबूरी में वे बातें रह गई थी । उनके दिल में किसान और

मजदूर के लिए तड़प है देहात का पिछडापन, फलड से तबाह हुए इलाके के बारे में उनके हृदय में कसक होनी स्वाभाविक ही है । इसलिए डिप्टी स्पीकर महोदय सदन का ध्यान उन्होंने इस प्रस्ताव के माध्यम से दिलाया है और उन्होंने अपने प्रस्ताव में कहा है—

This House recommends to the State Government to declare the areas of Beri and Nahar Blocks of Tehsil Jhajjar, as Industrially and Economically backward and to make them resourceful and self-sufficient, necessary steps be taken to provide Industrial facilities there.

डिप्टी स्पीकर साहब वे रोहतक का जिक्र करना इसलिए भी भूल गए कि जब यह इलाका आ जाएगा तो रोहतक अपने आप ही शामिल हो जाएगा और बाद में उन्होंने शामिल भी कर दिया । मेरे लायक दोस्त रोहतक जिले के हैं इसलिए उसका समर्थन करना भी स्वाभाविक है क्योंकि हम जानते हैं यह हमारा अपना जिला है । रोहतक जिले की मिट्टी अपनी ही तासीर की है । आज सारा देश उस रोहतक जिले के महापुरुष का ऋणि है जिसने सारे किसानों की जिन्दगी बुलन्द की थी । वे महापुरुष इसी जिले के रहने वाले थे । डिप्टी स्पीकर साहब मेरे बाकी साथियों ने जो बातें कहीं हैं, उनमें है अधिक क्या जोड़? डिप्टी स्पीकर साहब आप जानते हैं कि झज्जर तहसील का इलाका बाढ़ से बिस्कूल तबाह हुआ हुआ है । बादली के उप-चुनाव में हमारे काफी साथी वहां गए होंगे, उन्होंने वहां की हालत को देखा होगा । उस एरिया को देखकर लज्जा आती है, दुःख होता है, परेशानी होती है

। वहां से 18 मील की दूरी पर भारत की राजधानी है जहां पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी हैं । वहां की यी हालत थी कि मनुष्य क्या, पशु खड़ा करने को भी जगह नहीं है । इतना बुरा हाल उस इलाके का है वही हाल पलड के कारण रोहतक जिले का भी हो गया । अब हमारा जिला भी काफी छोटा कर दिया । इस जिले में रोहतक और झज्जर दो ही तहसीलें हैं, एक बहादूरगढ और बढ़ा दी गई है । तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि रोहतक जिले का जहां तक पिछड़ेपन का सवाल है वह इन्टलैक्चुअल में बहुत आगे है, फिजिकली बहुत आगे है, हौसले में, दम में और संघर्ष में सबसे आगे है । हमारे बारे में कई बार लोग गुस्से में कह देते हैं कि ये रोहतक जो आते है वे कुछ ऐसी बातें कह देते हैं, वे इसी स्वभाव के कारण ही कह देते हैं, वे हिम्मत वाले हैं । डिप्टी स्पीकर साहब, हर संघर्ष का मुकाबला वही से शुरू हुआ । लोकतन्त्र पर जो अंकुश लगा रखा था, उसको समाप्त करने के लिए आन्दोलन रोहतक से शुरू हुआ । सत्याग्रह में सबसे ज्यादा लोग रोहतक के आए । मीसा में भिवानी के लोग ज्यादा थे, क्योंकि वहां के हुक्मरान थे, लेकिन पोलिटिकली हमारे लोग ज्यादा थे । मेरा कहने का मतलब यह है कि लोग हर मामले में ठीक हैं, लेकिन वहां पर पिछड़ापन केवल इस बाढ़ के कारण है । बाढ़ में वहां के लोग तबाह हो गए ।

डिप्टी स्पीकर साहब रोजगार के दो साधन होते हैं एक खेती और दूसरे उद्योग । खेती वहां पानी के बीच में खड़ी है

जिसके कारण लोगों में बेकारी आ गई । नौकरी में तो लोग सीमित होते हैं । बहुत थोड़े लोगों को नौकरी मिलती है । संसार में वही देश समृद्धशाली और उन्नति करता है जो नौकरी पर निर्भर न रहे । जापान और जर्मनी एक महान देश से पराजित हुए, लेकिन 32-33 वर्ष के अन्दर ही संसार में अग्रणी देश बन गए । वहां के लोगों में उद्योग की तरक्की की ओर अधिक ध्यान है । अगर यहां पर इंड्रस्ट्रियलाइजेशन कुछ हुआ भी, तो उपको पैट्रनाईज कर दिया गया । उद्योगीकरण के खास खास आदमियों को लाईसेंस दिए गए, क्योंकि जो लोग सत्ता में थे, उनकी राजनीति उनके द्वारा चलती थी, उन लोगों से वं नाजायज लाभ लिया करते थे नाजायज काम कराया करते थे । डिप्टी स्पीकर साहब हमारी सरकार की नीयत बड़ी स्पष्ट है । सत्ता में आने के पश्चात् जनता पार्टी ने फैसला पिया कि उद्योग सम्बन्धी ऐसी नीति हो कि जिसमें मासिज की प्रगति हो और पैदावार ज्यादा होनी चाहिए मात प्रोडक्शन बाई मासिज की हमारी पालिसी है । ज्यादा पैसा लघु उद्योगों में लगे । लघु और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना हमारी सरकार की पालिसी है तभी तो हमने ग्रामीण क्षेत्र में 110 यूनिट, पढ़े लिखे लोगों के लिए प्रारम्भ किए हैं । कल अपोजीशन के भाई बड़े कटाक्ष कर रहे थे और मुझे तीर मार रहे थे कि अभी तो 110 यूनिट शुरू किए हैं, अगले साल 330 यूनिट खोलने जा रहे हैं आप तो आज इस पार्टी में शामिल हुए हैं, इस पार्टी ने तो तीस साल तक राज किया है, उसने एक भी उद्योग गांव में नहीं लगाया । हमने तो 8 महीने की अल्पावधि में वह

करके दिखाया है जो वह 30 सालों तक नहीं कर सके । हमने बैंकों से कहा है कि आपको ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग लगाने के लिए कर्जा देगा देना पड़ेगा । मुझे यह घोषणा करते हुए बड़ा सन्तोष हो रहा है कि हरियाणा में चलने वाले शिडल्यूल्ड बैंकों ने, नैशनेलाईज बैंकों ने, सब बैंकों ने हमें पूरा सहयोग दिया है और दे रहे हैं । सरकार उनकी बड़ी मशकूर है । डिप्टी स्पीकर साहब तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जो मेरे मिल ने कहा कि नाहड और बेरी को बैकवर्ड इलाका एकदम से डिक्लेयर किया जाए और बाद में उन्होंने रोहतक भी फरमाया है, इसमें लिखा तो नाहड और बेरी का इलाके ही है लेकिन बाद में उन्होंने रोहतक भी शामिल करने के लिए कहा है । (विधन)— सारे हरियाणा को तो हम बैकवर्ड क्यों डिक्लेयर करवाएंगे । बैकवर्ड डिक्लेयर करवाने के लिए कुछ क्राइटेरिया होता है । आपको तो शायद पता भी होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट से बैकवर्ड एरियाज के लिए कुछ पैसा भी मिलता है । उसके लिए हमे पहले सेल्ज. टैक्स भी' सस्पेंड बरना पड़ता है और चुंगी भी माफ करनी पड़ती है । प्रदेश सरकार के पास खजाना खाली करके मेरे ये भाई दे गए हैं । ये भाई कहीं मौज मेला करते रहे हैं । जगह-जगह पर इन्होंने होटल मोटल और रैस्टोरैन्ट्स का निर्माण क्रिया है । आप जाकर देखिए एक एक रैस्टोरैन्ट में ऐसे कालीन बिछे हुए हैं कि वहां पर बैठते हुए लज्जा आती है कि हरियाणा के किसान मजदूर, छोटे व्यापारी, आम जनता के गाढ़े पसीने का पैसा किस बेदर्दी के साथ सुख सुविधा के लिए खर्च किया है । यह पैसा अगर किसान के ट्यूबवैलं के

कर्जे के लिए दिया जाता किसान को बीज लेने के लिए दिया होता, किसान को जमीन संवारने और संभालने के लिए दिया होता, मकदूरों को कारखाने लगाने के लिए दिया होता, छोटे व्यापारी को व्यापार बढ़ाने के लिए दिया होता, तो आज प्रदेश बड़ा समुद्ध होता, लेकिन उन्होंने पैसा बड़ी बेरहमी से और बड़ी बेदर्दी के साथ खर्च किया । खजाना खाली करके चले- गए हम सारे हरियाणा को तो बैकवर्ड डिक्लेयर नहीं कर सकते । यहां पर गुडगांवा जिले के भाई भी बोले और सरदार खां का कहना बिल्कुल वाजिब है कि उनका इलाका तो पहली सरकार ने पिछड़ा जान बूझ कर रखा है अनप्रीविलेज्ड रखा है, हमेशा वे डरा धमका कर वोट ले लिया करते थे मुझे ख्याल है अगर मैं गलती नहीं करता तो पहले भी वे एक बार वहां से खड़े हुए थे । वे उसी जुल्म के शिकार हुए थे । जनता पार्टी का टिकट पाने के बाद तो उन्हें जीतना ही था क्योंकि वहां की जनता इन्हे चारें ती' थी । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इनका इलाका तो बड़ा बैकवर्ड है और भी हरियाणा के क्षेत्र ऐसे है, जो बैकवर्ड हैं । हम एक साथ तो मामला नहीं ले सक्ते । यही पर मामला जो है वह नाहड और बेरी के इलाके को औकवर्ड 'डिक्लेयर करने का है कि उसे बैक-बर्ड डिक्लेयर शिया जा हु । मेरे मित्र को यह पता ही नहीं हु 'कि नाहड का इलाका तो पहले से ही बैकवर्ड घोषित है । केवल बेरी की बात गे व रह जाती है बहादुरगढ़ के इंडस्ट्रियल एरिया में वास्तव में जो इनडस्ट्रियल प्रोग्रेस हो रही है, इसकी कहानी सुनाओ तो बड़ा लम्बा समय चाहिए । यह वास्तव में जो

इंडस्ट्रियल – ईज हुआ है, यह हरियाणा के लोगों के क्रने से नही हुआ है । वह इलाका बहादूरगढ का इलाका तो बैकवर्ड नहीं कहा जा सकता । हां पानी की मार जरूर हुई है क्योकि कहा पर 5 महीने पानी खड़ा रहा और कारखाने बन्द रहे । सरकार को उनसे पुरी, हमदर्दी है । इसलिए पिछले दिनों जब बिजली की कटौती हुई तो हमने बाकी जगह 40 प्रतिशत की तो यहां पर सिर्फ 20 प्रतिशत कटौती की । इसलिए मैं यह 'निवेदन करना चाहता हू कि हमने छोटे उद्योग को प्रोत्साहन दे ने के लिए बड़े प्रयत्न विघ्न हैं । पहले एक डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज आफिसर केवल 5, 000 रुपए तक ही लोन सैक्शन कर भक्ता था, अब हमने उसे बढ़ाकर 1 0, 000 रुपए तक की पावर दे दी है । ऐसा इसलिए किया है ताकी छोटे उद्योग लगाने का लो को प्रोत्साहन मिले । तो मैं ज्यादा न कहते हुए इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि बहादुर– गढ और रोहतक को देखकर बाकी सारे जिले– को बैकवर्ड डिक्लेयर करवाने के लिए कागज चल रहे हैं । मैं अपने आदरणीय मित्र से यह कहूंगा 'कि आपकी बात हमारे विचाराधीन है और सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रहे हैं, और प्रयत्न कर रहे है कि यह कम– हो जाए आपने ध्यान दिलाया शु क्रिया । यह बात कहते हुए मैं अपने आदरणीय मित्र मेहरबान दोस्त से कहूंगा कि अपना प्रस्ताव वापिस ले लें ।

चौधरी हरि चन्द हुड्डा : डिप्टी स्पीकर साहब, डाक्टर साहब ने अश्योरैस दे दी है और बड़े मीठे मीठे शब्दों में दी है

और यहां तक ही नहीं एशिया तक की बात की हैं । वैसे जो कुछ वह कह जाते हैं, वह कर देते हैं और नहीं करेगे तो मेरे साथ रोहतक में रहते हैं । इनकी कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है । तो इस अश्योरैस को मैं पकडता हूँ और अपना प्रस्ताव में विदड़ों करता हूँ ।

Mr. Deputy Speaker : Has the hon. Member the leave of the House to withdraw his resolution ?

(Voices : Yes)

The Resolution was, by leave of the House, withdrawn.

गैर सरकारी संकल्प संख्या-4

निशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा मिडल स्तर से बडा कर उच्चतर माध्यमिक स्तर अर्थात् ग्यारवीं कक्षा तक करने सम्बन्धी

Mr. Deputy Speaker : The next resolution stands in the name of Rao Dalip Singh. He is not present in the House. The resolution is, therefore, not moved.

आधे घंटे की चर्चा

तारांकित प्रश्न सं 0 228 के उत्तर के सम्बन्ध में

Mr. Deputy Speaker : The hon. Member, Lala Mool Chand Jain, who had given notice of half-an-hour discussion on matters arising out of the answer to Starred Question No. 228 is also not present.

The House stands *Adjourned till 9.30 a.m.
tomorrow, the 10th March, 1978.

12. 48 बजे

(The Sabha then adjourned till 9.30 a.m. on Friday,
the 10th March, 1978).

परिशिष्ट

(Please see foot-note on page (9)47

Passenger Tax through State Transport Authority.

126. Lala Balwant Rai Tayal : Will the Minister for Finance be pleased to state-

(a) the districtwise total number of Bank drafts with their amount paid as Passengers Tax by the Contract Carriages through State Transport Authorities which were noted at the barriers from the copy of route permits presented by the Contract Carriages but not received in the District Excise & Taxation Officers' Office from the State Transport Authorities during the financial years 1973-74, 1974-75, 1975-76, 1976-77 and 1977-78 to date;

(b) the districtwise total number of Bank drafts and their amount in which the delay was made for more than five days, one month, two months, three months, four months, five months, six months and above six months separately for their submission to the Bank for encashment during the above said years;

(c) the district-wise total number of Bank drafts and their amount as referred to in part (b) above in which the delay was made for more than ten days by the Bank to encash the drafts;

(d) the districtwise total number of Bank drafts and their amount, their receiving date in the district offices

and date on which these were sent for revalidation during the said financial years separately;

(e) the districtwise total number of Bank drafts and their amount during the said financial years which were used more than once by the Contract Carriages;

(f) the districtwise total number of Bank drafts and their amount gone to loss to Government Revenue which were received by the District Excise & Taxation Officers' Office from the State Transport Authorities during the said financial years but their amount did not tally with the amount which was noted at the barrier from the copy of route permits presented by the Contract Carriages:

(g) the barrierwise number of cases of which the particulars were noted at the barrier from the copy of the route permits presented by the Contract Carriages during the said financial years but were not legible;

(h) the districtwise, barrierwise and periodwise record during the said period which was lost and the names of the Officers/officials responsible for the loss of such records; and

(i) the names of the District Excise & Taxation Officers and Officers/ officials posted in the Passengers Tax Branch of the District Excise & Taxation Officers' office and names of the Assistant Excise & Taxation Officers/Taxation Inspectors posted at the barrier during the said period ?.

Excise and taxation Minister (Chaudhri Sher

Singh) ; (a) to (i) The statements (1 to 9) giving the requisite information in seriatim are laid on the Table of the House.

STATEMENT—I (Reg. Part (a))

Sr.	Name of the District	1973-74		No.-1974-75		1975-76		1976-77		1977-78	
		Total No. of Bank Drafts	Amount	Total No. of Bank Drafts	Amount	Total No. of Bank Drafts	Amount	Total No. of Bank Drafts	Amount	Total No. of Bank Drafts	Amount
1.	Gurgaon	—	—	—	—	484	40892-00	—	-	—	-
2.	Narnaul	4	310-00	7	485-00	514	4286-00	489	3970-00	581	25250.00
3.	Sonepat	—	—	—	—	815	111350-30	—	—	—	—
4.	Faridabad	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

The information in respect of other districts may be treated as nil.

STATEMENT-2 (Reg. Part—b)

No. of Bank drafts in which delay was made for more than five days, one month, two months, three months, four months, five months, six months, and above six months in representing the same in the concerned Bank for encashment.

Name of the Distt.	1973-74	Five days Amount	One month s	Two month s	Three mont hs	Four months	Five month s	Six mont hs	Above six month s	1974-75	Five days	One Tw o month s	Three month s
1. Gurgaon	-do-	—	—	—	—	—	—	—	—	-do-	—	—	—
2. Narnaul	-do-	—	—	—	—	—	—	—	—	-do-	—	—	—
3. Sonapat	-do-	47	—	—	—	—	—	—	—	-do-	—	—	—

462

--

--

--

-do-

--

--

--

--

--

--

-

87799-50

--

--

--

--

--

-do-

--

--

--

--

--

--

--

STATEMENT-3 (Reg. Part (c))

No. of drafts in respect of Para No. (b) above in which the delay was made for more than 10 days by the bank.

Name of the District	1973-74	Amount	1974-75	Amount	1975-76	Amount	1976-77	Amount	1977-78	Amount
1. Gurgaon	1243	75254-30	1613	51846-00	12395	540503-10	264	30611-00	39	4498-00
2. Sonapat	—	—	—	—	116	15739-80	—	—	—	—
3. Narnaul	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-
4. Faridabad	—	—	—	—	93	8464-00	357	33087-00	—	—

The information in respect of other districts may be treated as nil.

STATEMENT-4 (Reg. Part (d))

Name of the District	1973-74	1974-75	1975-76	1976-77	1977-78	Total No. of Drafts.	Date on which received in the district offices	Date on which these were sent for re-validation.	Amount
Gurgaon	88	43	140	445	238	954	18-3-74	20-3-74	4338-00
							1-12-74	6-12-74	4148-00
							4-7-75	10-7-75	22649-00
							22-5-76	25-5-76	52620-00
							12-9-77	13-9-77	19796-95
Narnaul	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sonepat	—	—	164	—	—	164	The date of receipt has not been mentioned	—	21941-00

in the record.

Faridabad ,	—	—	—	—	3	3	12-7-77	29-7-77	375-00
					3	3	12-8-77	30-8-77	510-00
					1	1	17-8-77	19-8-77	22-00
					1	1	17-8-77	19-8-77	130-00
					1	1	17-8-77	19-8-77	170-00

The information in respect of other districts may be treated as nil.

STATEMENT-5 (Reg. Part (e))

Name of the District	1973-74	1974-75	1975-76	1976-77	1977-78	No. of drafts	Amount
1. Gurga on	—	—	16	—	—	16	1906-00
2. Narnaul	—	—		—	—	—	-
3. Sonapat	—	—	15	—	—	15	2759-00
4. Faridabad	—	—	—	—	—	—	—

The information in respect of other districts may be treated as nil.

STATEMENT-6 (Reg. Part (f))

Name of the District	1973-74	1974-75	1975-76	1976-77	1977-78	No. of Drafts in which the amount differed	Amount
1. Gurgaon	—	—	16	—	—	16	1210-00
2. Narnaul	—	—	—	—	—	—	-
3. Sonapat	—	—	75	—	—	75	6975-03
4. Faridabad	—	—	—	—	—	—	—

The information in respect of other districts may be treated as nil.

STATEMENT-7 (Reg. Part (g))

Name of the District	1973-74	1974-75	1975-76	1976-77	1977-78	No. of cases in which the particulars were found not legible	Amount
1. Gurgaon	—	—		—			-
2. Narnaul	—	—	—	—	—	—	-
3. Sonapat	—	—	—	—	—	—	-
4. Faridabad	—	—	—	—	—	—	—

The information in respect of other districts may also be treated as nil.

STATEMENT-8 (Reg. Part (h))

Name of the District	Name of the Barrier	1973-74	1974-75	1975-76	1976-77	1977-78	Name of the Officer/ Official responsible for the loss of record
1. Gurgaon	—	—	—	—	—	—	-
2. Narnaul	—	—	—	—			
3. Sonapat	—	—	—	—	—	—	—
4. Faridaba	—	—	—	—	—	—	—

The information in respect of other districts may be treated as nil.

STATEMENT-9 (Reg. Part (i))

Sr. No.	Name of the district	Year	Name of the D.E.T C./D.E.T.O.	Name of the A.E.T.O.(E) T.I.(P & G.T.)/T.I.(E)/ Clerk (P & G.T.)	Name of barrier	Name of A.E.T.O.	Name of Taxation Inspector
1	2	3	4	5	6	7	8
			Sarvshri—	Sarvshri—		Sarvshri—	Sarvshri—
1.	Gurgaon	1973-74	G.P.Kashyap, D .E.T .O.	Sajan Singh, H.T.O.(E) Raj Pal Sharma, T.I.P.G.T. Ram Kunwar, and C.D. Gaur, T.Is.(E) Bhishampitamaha and Chander Bhan, Clerks	Dundahera	M.S. Malhotra	O.P.Sharma K.B.Malhotra Shanker Singh Lilu Ram
					Sikandar Pur	Rattan	U.K, Gupta K.C.

	Singh	Gupta Brik Bhan
Daultabad	—	Balbir Singh P.C. Jain, Jee Ram
Chandu	—	—
Buderha		
Mundka	—	—
Punhana	—	—
Faridabad	D.P. Verma	Inder Singh D.N. Malik Jai Pal Singh, Pushkar Raj S.D. Verma G.C. Gupta I.S. Jain Har Gobind

				Hodel	—	Mangal Singh Vidya Nand Bal Mukand Dal Singh
				Suraj Kund	M.L. Kapoor	Ved Singh Bhim Singh Sukhbir Singh
Gurgaon	1974-75	Do	Do	Dundahera	M.S. Malhotra	K.B. Malhotra Ravi Dutt Ramesh Kumar Surat Singh
				Sikandarpur	—	U.K. Gupta, K.C. Gupta, D.P. Singh
				Daultabad	—	Attar Singh Hans Raj Ram Chander
				Chandu	—	P.C. Jain S.R.

H

Buderha		Chawla Jai Bhagwan Man Singh
Mundka		O.P. Bagri Ramesh Ahuja Subhe Singh Ram Sarup
Punhana	—	O.P. Bura Dhup Singh K.K. Goyal Ratti Ram
Faridabad	B.M. Sharma, B.L. Arya	hider Singh D.N. Malik Jai Pal Singh Pushkar Raj S.D. Verma G. C. Gupta I.S. Jain Hargobind
Hodel	A.H. Sood	Mangal Singh Vidya Nand Bal

						Mukand Dal Singh
				Suraj Kund	—Ved	Singh Bhim Singh & tanker Singh
Gurgaon	1975-76	N.S. Bedi, D.E.T.O	V.P. Chadha, E.T.O.(E) Raj Pal Sharma, Ti. (P.G.T) & P.D. Gaur M.R. Dahiya T.I. (E) Chander Bhan, Clerk	Dundahera	S.L. Tuknat Al. Bajaj- R.P. Yadav	Surat Singh Kanwal Singh Ramesh Singh Bhim Singh
				Sikander Pur	—	D.P. Singh N.L. Banga Davinder Singh
				Daultabad	—	Attar Singh Sagar Mal Yadesh Kumar Rim

						hander
				Chandu Buderha	—	S.R. Chawla P.C. Jain
						Jai Bhagwan
				Mundka	—	O.P.Bagri
						O.P. Alahawat Ashok Kumar Des Raj
				Punhana	—	P.O.P.Bura Dhup Singh K.K. Goyal
Gurgaon	1976-77	Miss Amar feet Sachdeva, D.E.T.O.	K.L. Chaudhary, A.E.T.O. (E), J.S. Malik, T.I.(E). (P.G.T.) D.S. Ranga, T.I. (E), Rajinder Singh	Dundahera	M.L. Sharma B.L. Atris R.S. Sharma	S.K. Sharma Ajit Sitigh Vidya Sagar Manga Ram

Clerk & Vijay
Singh Clerk

K.L. Dua

Sikanderpur.	—	N.K. Gupta J.C. Gupta K.B. Malhotra
Daultabad	—	Math Pal Jain S.K. Bhalla D.N. Sharma S.R. Chawla
Chandu Buderha		Indraj Singh Prabh boat K.S. Randhawa Rattan Lal
Mundka		Rail Dutt D.R. Sikka Partap Singh
Punhana	—	R.P. Sangwan

						A.K. Sharma Dhal Singh
Gurgaon	1977-78	Miss Amarjeet, Sachdeva, D.E.T.O.	S.N. Sharma A.E.T.O. from 3/78 J.S. Malik, T.I. (P.G.T) D.S. Kanga, T.I. (E), Sham Dass and Inder Singh Clerk	Dundahera	M.L. Sharma B.L. Atris R.S. Sharma K.L. Dua	S.K. Sharma Ajit Singh Vidya Sagar Manga Ram
				Sikandarpur	—	N.K. Gupta J.C. Gupta K.B. Malhotra
				Daultabad	—	Nath Pal Jain S.K. Bhalla D.N. Sharma S.R. Chawla
				Chandu	—	Inderaj Singh Prabh Dayal

					Buderha		Rattan Lal P.C. Jain
					Mundka		Ravi Dutt D.R. Sikka Partap Singh
					Punhana	—	R.P. Sangwan K.K. Sharma Dhal Singh
2	Narnaul	1973-74	T.N.Kapoor D.E.T.O.	Sajjan, Singh E.T.O.(E) M.R. Dhaiya M.M.Verma and Kishori Lal T.I. (P.G.T.)	Jaiminghpur Khera	Daryao Singh Ladwal	Anand Parkash Balraj Pannu Hans Raj Bandur Singh
					Khandora	K.K. Bhasin	Rambir Singh Devi Ram Kataria Ram Niwas

				Ishwar Singh	
	Sarvshri—	Sarvshri—		Sarvshri---	Sarvshri-
Narnaul	1974-75 Do	Sajjan Singh E.T.O. (E), M.M. Verma, Kishori Lal, R.K. Gupta and L.N. Sharma T.I. (P.G.T.)	Jaisinghpur Khera	B.M. Sharma Rachna Ram M.L. Katyal	Anand Parkash Balraj Pannu Bahadur Singh Rambir Singh R.S. Mahara
			Khandora	K.K. Bhasin	Hans Raj Parkash Chand Devi Ram Ram Niwas Ishwar Singh Madho Ram
Narnaul	1975-76 T.N. Kapoor D.E.T.O./S.R.	A.N. Bhandula A.E.T.O. (E) Sher	Jaisinghpur Khera	Rachna Ram	Jee Ram, Ami Lal Parkash

		Handa D.E.T.O.	Singh G.S. Narang and Kishori Lal TI		D.C. Phaugat M.L. Katyal	Chand Raghbir Singh Devi Ram Vidya Sagar
				Khandora	K.K. Bhasin	Rambir Singh Parkash Chand J.S. Kang Partap Singh
Narnaul	1976-77	S.R. Handa and Sajjan Singh D.E.T.O.	S.S. Sehgal & J.L. Jaisinghpur Sabharwal, Khera A.E.T.O.(E) Dil bagh Singh, Kishori Lal, Davinder Singh T.I.		D.C. Phaugat M.L. Katyal Rachna Ram	Upendar Kumar M.P. Saini K.L. Sharma Parkash Chand B.N. Rao R.K. Sharma
				Khandora	—	Raj. Kumar Vidya Singh K.K. Dalal

							S.C. Gupta
2	Narnaul	1977-78	Sajjan Singh & R.N. Chotani, D.E.T.O.	J.L. Sabharwal A.E.T.O.'s (E) Dilbagh Singh, Kishori Lal, Davinder Singh T.Is.	Jaisinghpur Khera	M.L. Arora H.B. Gandhi U.N. Bountra S.L. Arya	U.K. Gupta M.P. Saini Raj Kumar Sohan Lal Phaugat
					Khandora	Nafe Singh	Vidya Singh S.C. Gupta K.K. Dalal,
3	Sonepat	1973-74	T.R. Sharma and B.R Gupta D.E.T.Os.	A.L. Bajaj (E) Jagdish T.I. (P.G.T.) M.L. Katyal Head Assistant, Gajender Singh Clerk	A.E.T.O Shivpuri	—	Gurdial Singh M.P. Jain Dabit Singh Karta Ram Mohan Lal

Nahra-Nahri	—	—
Kundri	—	Sukhbir Singh, Partap Singh S.P. Kohli ,J.K. Sharma, K.C. Garg Nafe Singh, Gian Chand, Dalbir Singh, D.R Sikka Khusi Ram, Randhir Singh, Ram Parkash
Saidpur	—	Ganga Raj Arun Kumar Mohinder Singh Raghbir Singh Vijay Singh

Sonepat	1974-75	D.N. Chaudhary D.E.T.O.	A.L. Bajaj, A.E.T.O. (E) M.L. Puri T.I. (P.G.T.) M.L. Katyal, Head Asstt. Rajinder Singh Clerk	Shivpuri	K.L. Khanna	Balbir Singh Ram Narayan Baljit Singh Gurdial M.P. Jain Mohan Lal Rajinder Pal Jagbir Singh Kapoor Singh
				Nahra-Nahri	—	Banwari Lal Balwan Singh Chander Bosh Hawa Singh Prem Gupta
				Kundli	J.P. Dogra & J.L. Sabharwal	Nafe Singh Khushi Ram Hunt Ram R.P. Thukral Ganga Ram Dalbir Singh Randhir Singh

				Saidpur	—	J.K. Sharma Chander Dev God Chander Bosh Ragbir Singh Ganga Ram Vijay Singh Mohinder Singh Kharaiti Lal C.A. Dhingra
Sonepat	1975-76	D.N. Chaudhry D.E.T.O.	B.R. Yadav A.E.T.O.(E) B.S. Jaiji and M.S.Sinder, T.1. (P.G.T.) M.L.Katyal Head Assistant Gajender Singh Clerk	Shivpuri	K.L. Khanna	V.K. Vadhwa C.A. Dhingra B.S. Dahiya J.S. Malik Jagbir Singh Ram Narain Balbir Singh Kapoor Chand

Nahra-Nahri	—	Banwari Lal Balwan Singh Hawa Singh Preen Gupta Nafe Singh
Kund li	Rattan Lal Rao C.S. Sharda Vijay Rao	K.C. Garg K.L. Chaudhary Dharam Pal Mahavir Singh Rattan Saroop Malik K.C. Sheok and Nafe Singh Khushi Ram Hunt Ram R.P. Thukral Ganga Ram Dalbir Singh Randhir Singh

—					Saidpur	—	Balraj Gautam Chander Singh Jai pal Daryao Singh Kharati Lal C.A. Dhingra Mohinder Singh Chander Bose
9	Sonepat	1976-77	R.N. Chotani D.E.T.O.	B.R. Yadav A.E.T.O.(E) M.S. Bhinder, T.I. (P.G.T.) M.L. Katyal Head Asstt. Gajender Singh Clerk	Shivpuri	M.S. Bhinder	Devi Singh Ram Phal Ram Chander Pawar M.S. Bhinder V.K. Vadhwa C.A. Dhingra B.S. Dahiya J.S. Malik Lal Chand

Nahra-Nahri	—	Nafe Singh Balwan Singh Chander Bosh Prem Gupta
Kundli	A.L. Khurana Charan Singh N.P. Sood	Ashok Kumar Leela Ram R.K. Gupta B.M. Sharma S.R. Nehra S.P. Sharma R.N. Sidhwani
Saidpur	—	Jaipal Singh Chander Singh Daryao Singh Kharoti Lal Anand Pannu Hari Singh D.D. Chopra P.D.

					Gaur
Sonepat	1977-78	R.N. Chotani and Sajjan Singh D.E.T.Os.	B.R. Goyal A.E.T.O.(E) Shivpuri	—	Lal Chand Devi Singh Ram Phal RamChander
				Nahra-Nahri	—
					O.P. Ahlawat Khusi Ram Ram Chander Jai Parkash R.K. Gupta
				Kundli	A.L. Khurana Charan Singh I.C. Jain
					Ashok Kumar Lila Ram Khushi Ram B.M. Sharma S.K. Nehra R.N. Sidhwani R.P. Thukral

				Saidpur	—	Anand Parkash Sharma	
						Had Singh D.D. Chopra P.D. Gaur R.S. Tomar	
4	Faridabad	1975-76	hider Singh D.E.T.O.	Gurdial Singh A.E.T.O. (E) Vidya Nand T.I. Kailash Chand, Clerk	Faridabad	H.S. Chohan K.N. Chhibbar M.L. Arora	D.N. Malik Chander Parkash Pushkar Raj Om Parkash Laxmi Narain S.K. Sharma Prabhu Dayal
				Hodel	LS. Jain	Gurdial Singh Labh Singh	
				Suraj Kund	—	O.P. Tyagi Chhuni Lal Ved Parkash M.L.	

						Puri
4	Faridabad	1976-77	Inder Singh D.N. Chaudhary & K.S. Yadav, D.E.T.Os.	Gurdial Singh A.E.T.O. (E) & K.S. Dhaka, E.T.O. (E) Daryao Singh TI Kailash Chand Clerk	Faridabad	M.L. Gupta Gulab Chand R.P. Yadav Yadav K.L. Bhola R.L. Chopra Prabhu Dayal D.N. Malik Ashok Kumar K.K. Ranka S.P. Jain Pushkar Raj Chander Parkash M.S. Khichi

		Piare Lal
		Partap Singh
		Prem Inder Yadav
		Ram Chander Gupta
Hodel	I.S. Jain & S.S. Sehgal	Gurdial Singh Labh Singh Chander Bhan Jai Chand Dharam Raj K.K. Dubey Phool Chand
Suraj Kund	—	O.P. Tyagi Chuni Lal Ved Singh M.L. Puri K.C. Gupta

					J.C. Madan	
					M.R. Dhawan	
					Sukh Ram F.C.	
					Garg	
4	Faridabad	1977-78	K.S. Yadav D.E.T.O.	K.S. Dhaka, E.T.O.(E) R.L.Chopra A.E.T.O.(E) Daryao Singh T.I. Kailash Chand Clerk	Faridabad	M.L. Gupta Ashok Kumar R.P. Yadav K.K. Banka S.P. R.I. Chopra Jain M.S. Kh ichi H.N. Mittal F.C. Garg Piare O.P. Verma Lal Partap Singh Mohinder Prem Inder R.C. Kumar Gupta Gurdial
					Hodel	Sarop C.B. Gupta Phool Singh M.L. Chand Dharam Talwar Lal Raj K.K. Dubey Chand Gaje Singh MX. Dutta

Suraj Kund

K.C. Gupta F.C.
Garg J.C. Madan
Subh Ram
Gurdial Singh